महानगर नई दिल्ली सोमवार 2 सितंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

अर्थव्यवस्था को सुस्ती से निकाले सरकार : सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर के घटकर पांच फीसद तक पहुंच जाने के मद्देनजर रविवार को देश की अर्थव्यवस्था की हालत को बहुत चिंताजनक करार दिया और केंद्र की राजग सरकार से अनुरोध किया कि वह बदले की राजनीति को छोड़कर अर्थव्यवस्था को मानव-निर्मित संकट से बाहर निकलने के लिए सही सोच-समझ वाले लोगों से संपर्क करे। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी में जल्दबाजी को मानव निर्मित संकट बताया।

पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि यह आर्थिक नरमी केंद्र की राजग सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन की वजह से है। उन्होंने कहा- वर्तमान में अर्थव्यवस्था की हालत बहुत चिंताजनक है। पिछली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि मात्र पांच फीसद तक सीमित रहना नरमी के लंबे समय तक बने रहने का संकेत है। भारत में तेजी से वृद्धि की संभावनाएं हैं लेकिन राजग सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन के कारण यह नरमी आई है। सिंह ने कहा कि देश के युवा वर्ग, किसान, खेतिहर मजदूर, उद्यमी और वंचित तबके को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत इस रास्ते और आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बदले की राजनीति बंद करे और अर्थव्यवस्था को इस मानवरचित संकट से बाहर निकालने के लिए सही सोच-समझ के लोगों से सलाह ले। उन्होंने कहा कि खास तौर से विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर का केवल 0.6 फीसद रहना विशेष रूप से चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है और उनकी स्वायत्तता छीनी जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा 1.76 लाख करोड़ रुपए लिए जाने पर मनमोहन सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी राशि सरकार को देने के बाद यह किसी बाकी पेज 8 पर

आर्थिक नरमी केंद्र की राजग सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन की वजह से है।

देश के युवा वर्ग, किसान, खेतिहर मजदूर, उद्यमी और वंचित तबके को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए।

संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है और उनकी स्वायत्तता छीनी जा रही है।

नोटबंदी और जीएसटी में जल्दबाजी को मानव निर्मित संकट बताया।

आरिफ मोहम्मद खान होंगे केरल के राज्यपाल

तमिलसाई सुंदरराजन को तेलंगाना का जिम्मा और कलराज मिश्र हिमाचल से भेजे गए राजस्थान

कलराज मिश्र

बंडारु दत्तात्रेय

भगत सिंह कोश्यारी

तमिलसाई सुंदरराजन

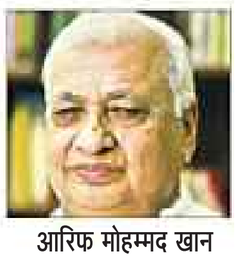
आरिफ मोहम्मद खान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मुसलिम नेता आरिफ मोहम्मद खान को मोदी सरकार ने केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। सरकार ने रविवार को खान के अलावा भाजपा के कुछ और नेताओं को भी विभिन्न राज्यों के राजभवनों में भेजा है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आदेश के अनुसार भाजपा नेता व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी (77) को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा की तमिलनाडु अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन (58) को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को राजस्थान भेजा गया है। मिश्र उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की जगह लेंगे। सिंह का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय (72) को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कोश्यारी महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल विद्या सागर राव की जगह लेंगे। सुंदरराजन तेलंगाना बाकी पेज 8 पर

विदेश मंत्रालय ने कहा

एनआरसी से छूट गए लोग 'राष्ट्र विहीन' नहीं

नई दिल्ली/बर्लिन, 1 सितंबर (भाषा)।

विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) से बाहर रहे लोग 'राष्ट्र विहीन' नहीं हैं और वे कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि एनआरसी से बाहर किए जाने से असम में एक भी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उन्हें पूर्व में प्राप्त किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया गया है।

रविवार को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष शरणार्थी अधिकारी ने भारत से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विहीन न हो।

विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया एनआरसी की अंतिम सूची के कुछ पहलुओं के बारे में विदेशी मीडिया के एक वर्ग में आई टिप्पणियों के मद्देनजर आई है। इससे पहले रविवार को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष शरणार्थी अधिकारी ने भारत से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि असम राज्य में एनआरसी से लगभग 20 लाख लोगों को बाहर किए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विहीन न हो।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रेंडी ने जिनेवा में बयान जारी कर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, 'कोई भी प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में लोग बिना किसी राष्ट्र की नागरिकता के छूट जाते हैं तो वह देशविहीनता को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि असम में रहने वाले किसी व्यक्ति के अधिकारों पर एनआरसी से बाहर किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं है उन्हें हिरासत में बाकी पेज 8 पर

'सिख लड़कियों के अपहरण व धर्मांतरण पर कार्रवाई करे पाक'

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान में दो सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मद्देनजर भारत ने रविवार को इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पड़ोसी देश से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उचित कदम उठाने को कहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने रविवार को ट्विटर पर कहा, 'नागरिक समाज और भारत के लोग पाकिस्तान में दो सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और निकाह की हाल की निंदनीय घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने पाकिस्तान को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने को कहा है।'

बताते चलें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लड़की के परिजनों ने एक वीडियो में आरोप बाकी पेज 8 पर

मंदी की आहट के बीच जीएसटी संग्रह में गिरावट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

मंदी की आहट के बीच अगस्त में जीएसटी से सरकार की आय जुलाई के मुकाबले घट गई है। अगस्त में देश का कुल जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ से घटकर 98,202 करोड़ रुपए पर अंटक गया। रविवार को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक, जुलाई में कुल जीएसटी संग्रह 1.02 लाख करोड़ का था। हालांकि अगर पिछले साल के अगस्त से तुलना की जाए तो यह संग्रह 4.5 फीसद ज्यादा है। साल 2018 के अगस्त में कुल जीएसटी संग्रह 93,960 करोड़ रुपए था।

98,202

करोड़ रुपए पर अटक गया अगस्त में देश का कुल जीएसटी संग्रह, पहले एक लाख करोड़ रहा था।

बैंकों के विलय से बड़ी उम्मीद लगाए है सरकार

बैंकों के विलय से नहीं जाएगी नौकरी : सीतारमण

खबरें पेज 2 पर

राजस्व विभाग विभाग के मुताबिक, जीएसटी के जरिए अगस्त में मिले 98,203 करोड़ रुपए में 24,818 हजार करोड़ की राशि सिर्फ आयात से मिली है। कुल जीएसटी संग्रह में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा है। 98 हजार करोड़ में से 17,733 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार बाकी पेज 8 पर

मालदीव की संसद में पाक नहीं उठा पाया कश्मीर मुद्दा

अपनों पर जुल्म करने वाले हमें न दें सीख : भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

कश्मीर के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़े पाकिस्तान की बौखलाहट और हताशा बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि मालदीव की संसद रविवार को आयोजित स्पीकर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कश्मीर मसला उठाने की नाकाम कोशिश की। रहा है। माले में हो रहे चौथे 'साउथ एशियन स्पीकर्स समिट' में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कश्मीर का मसला उठा दिया, जिस पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आपत्ति उठाते हुए तीखा बाकी पेज 8 पर

"जिस मुल्क ने बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों का जनसंहार किया हो, उसे मानवाधिकार पर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। - हरिवंश

गैर-सबसिडी वाला सिलेंडर 15.5 रुपए महंगा

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

बिना सबसिडी वाले एलपीजी सिलेंडर में रविवार को 15.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई। विमान ईंधन के मूल्य में भी एक फीसद की कमी की गई, जिससे उसका दाम चार माह के निचले स्तर पर आ गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमत में नरमी के कारण देश में विमान ईंधन की दाम में यह कमी की गई बाकी पेज 8 पर

सीएनजी के दामों में रविवार को वृद्धि की गई।

पुंछ : पाक की गोलाबारी में जवान शहीद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगी अग्रिम चौकियों और गांवों पर पाकिस्तान की तरफ से रविवार को मोर्टार के गोले दागे गए और छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया।

सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पुंछ सेक्टर के शाहपुर-केरनी क्षेत्र में सीमा पार से हुई गोलीबारी में अग्रिम चौकी पर तैनात एक सैनिक शहीद हो गया। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। पाकिस्तान द्वारा यह संघर्षविराम का उल्लंघन ऐसे समय किया गया है जब एक दिन पहले ही सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पुंछ और राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा का दौरा कर जवानों से मुलाकात की थी और मौजूदा स्थिति के साथ ही व्हाइट नाइट कोर की संचालनात्मक तैयारियों की समीक्षा की थी। इससे पहले जम्मू स्थित सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर में अगस्त तक 139 आतंकियों का सफाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

भारतीय सेना ने इस साल जनवरी से अगस्त के बीच जम्मू-कश्मीर में 139 आतंकियों का सफाया किया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इनमें नियंत्रण रेखा पर और सेना के साथ भीतरी इलाकों में हुए मुठडेड़ में मारे गए आतंकी भी शामिल हैं। ये आंकड़े 1 जनवरी 2019 से 29 अगस्त 2019 तक हैं। इस अवधि में पाकिस्तान द्वारा कुल 1,889 बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया। वर्ष 2018 में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर 1,629 बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया गया।

रक्षा बाकी पेज 8 पर

आंकड़े 1 जनवरी 2019 से 29 अगस्त 2019 तक हैं।

कुलभूषण जाधव को आज राजनयिक पहुंच की पेशकश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

पाकिस्तान ने रविवार को एलान किया कि दो सितंबर को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। पाकिस्तान की इस पेशकश पर भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राजनयिक पहुंच बिना शर्त और बिना बाधा वाली होनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह पाकिस्तान की तरफ से मिली पेशकश का अध्ययन करेगा। इसके बाद कोई फैसला किया जाएगा।

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि जाधव (49) को राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) के फैसले और पाकिस्तान बाकी पेज 8 पर

भारत ने कहा, कोई शर्त और बाधा नामंजूर

दरअसल

पाकिस्तान की मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक हैं अल्ताफ | पाक को दो टूक | स्वनिर्वासन में रह रहे अल्ताफ फिलहाल ब्रिटेन में हैं

370 हटाने पर भारत की हिमायत में आगे आए अल्ताफ

लंदन, 1 सितंबर (भाषा)।

ब्रिटेन में स्वनिर्वासन में रह रहे पाकिस्तान की मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को भारत का आंतरिक विषय बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के इस कदम को वहां (भारत) के लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है।

हुसैन (65) ने 1990 के दशक में यहां शरण मांगी थी और बाद में उन्हें ब्रिटिश नागरिकता मिल गई। हालांकि, उन्होंने एमक्यूएम पर अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में एक है।

उनकी पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची पर भी अच्छी पकड़ है। शनिवार को प्रसारित संबोधन में हुसैन जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने के भारत सरकार के फैसले पर पाक को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को अपने (पाक में) में मिलाने की चुनौती देते दिखे। उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 हटाना भारत सरकार का पूरी तरह से एक आंतरिक विषय है।'

एमक्यूएम का कराची में तीन दशकों से राजनीतिक वर्चस्व है क्योंकि उसे घनी आबादी वाले उर्दू भाषी मुहाजिरों का समर्थन है, जो 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। हुसैन उपमहाद्वीप में घटनाक्रमों पर नियमित रूप से बयान जारी करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के असैन्य और सैन्य प्रतिष्ठान पिछले 72 साल से कश्मीर के मुद्दे को लेकर देश की अवाम को गुमराह कर रहे और ठग रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान की सेना और असैन्य नेतृत्व को अब यह नाटक बंद करना चाहिए, या उन्हें कश्मीर को आजाद कराने के लिए जम्मू-कश्मीर में सेना भेजनी चाहिए।'

एमक्यूएम सचिवालय द्वारा प्रसारित वीडियो के कुछ प्रारूपों में हुसैन को भारत के समर्थन के प्रतीक के तौर पर 'सारे जहां से अच्छा...' गाते देखा जा सकता है। हालांकि, वीडियो को बनाए जाने के समय और स्थान का सत्यापन नहीं हो पाया है।'

एमक्यूएम सुप्रीमो ने इससे पहले न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की थी, बल्कि देश (पाक को) को दुनिया भर के लिए कैंसर भी करार दिया था।

हुसैन जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने के भारत सरकार के फैसले पर पाक को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को अपने (पाक में) में मिलाने की चुनौती देते दिखे। उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 हटाना भारत सरकार का पूरी तरह से एक आंतरिक विषय है।'

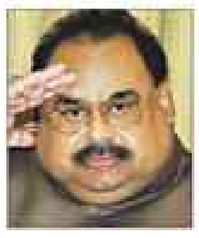

बैंकों के विलय से नहीं जाएगी नौकरी : सीतारमण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित विलय से कर्मचारियों की नौकरी जाने के खतरे की चिंता को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि विलय के फैसले से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। सीतारमण ने नौकरी जाने के बारे में बैंक यूनियनों की चिंता के बारे में कहा कि यह तथ्यहीन बात है। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को दस सरकारी बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने की घोषणा की थी। विलय के बाद कुल सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह जाएगी।

उन्होंने कहा कि ज्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र में होती हैं, जिनके आंकड़े सरकार के पास नहीं होते। उन्होंने एसबीआइ का अन्य बैंकों के साथ विलय का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं होगी। वित्त मंत्री ने यह मानने से इनकार कर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है। वित्त मंत्री ने कहा कि वह उद्योग प्रतिनिधियों से मिल रही हैं और उनकी समस्याएं सुन रही हैं। सीतारमण ने कहा कि उद्योग जगत सरकार से क्या चाहता है, इस पर सुझाव ले रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जारी रखेगी, लेकिन अन्य वाहनों की कीमत पर नहीं।

बैंकों के विलय से बड़ी उम्मीद लगाए है सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

वित्त सचिव राजीव कुमार का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के कदम से अर्थव्यवस्था के आकार को 5,000 अरब डालर पर पहुंचाने के लक्ष्य में मदद मिलेगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के विलय के माध्यम से चार बड़े सरकारी बैंक बनाने का फैसला किया है।

वित्त सचिव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले स्तर की वृद्धि को समर्थन के लिए देश को बड़े बैंकों की जरूरत है। शुक्रवार को जिस विशाल विलय की घोषणा की गई है, उससे इस लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। अब हमारे पास छह विशाल बैंक होंगे। जिनका पूंजी आधार, आकार, स्तर और दक्षता बढ़ी होगी। इससे देश को मध्य आय वर्ग वाले देशों में आने के लिए ऊंची वृद्धि के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। कुमार ने कहा कि इस एकीकरण से मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंक अस्तित्व में आ सकेंगे, जिनके पैमाने का स्तर ऊंचा होगा। उन्होंने कहा कि विलय बाद बनने वाले बैंकों की पहुंच अधिक व्यापक होगी। उनकी ऋण देने की क्षमता मजबूत होगी और वे नए भारत में ग्राहकों को अधिक बेहतर उत्पाद और प्रौद्योगिकी दे सकेंगे। भविष्य की रूपरेखा के बारे में पूछे जाने पर वित्त सचिव ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र प्रौद्योगिकी आधारित, साफ-सुथरे और प्रतिक्रिया देने वाला होगा। उन्होंने कहा कि प्रणाली से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा, चाहे वह आडिटर हो, रेटिंग एजंसियां हों या बैंकर हों। सभी बैंकों का पूंजीकरण बेहतर होगा और वे 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था को समर्थन दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेहतर दक्षता, ऊंचे लाभ, ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और अपने कर्मचारियों को अधिक लाभ पर विचार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े बैंकों को उनकी जरूरत की पूंजी से 0.25 फीसद अधिक उपलब्ध कराई है। ऐसा करते समय घरेलू प्रणाली में उनके महत्त्वपूर्ण दर्जे को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के दस बड़े बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया जाना है। विलय के बाद कुल सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह जाएगी।

नागपुर में रविवार को देवी पार्वती की प्रतिमा का शृंगार करती महिला।

बस का पिछला हिस्सा ट्रक से टकराया, चार लोगों की मौत

जयपुर, 1 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान के पाली जिले के रायपुर थानाक्षेत्र में शनिवार देर रात अहमदाबाद-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सांचौर से दिल्ली जा रही एक निजी बस का पिछला हिस्सा ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान झूठागांव के पास ट्रक से टकरा गया। जिससे बस में सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस जांच अधिकारी मांगीलाल ने रविवार को बताया कि बस में सवार जयपुर निवासी अंकित खंडेलवाल (26), भीलनमाल निवासी चौथाराम (27), सपना (9) और तरूणा (10) की मौत हो गई।

आइएसआइ से पैसे ले रहे भाजपा और बजरंग दल : दिग्विजय

भिंड (मध्य प्रदेश), 1 सितंबर (भाषा)।

कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा और बजरंग दल पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आइएसआइ से पैसे ले रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आइएसआइ के लिए मुसलमानों से ज्यादा गैर-मुसलमान जासूसी कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ट्विटर पर इसका खंडन भी किया।

दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर इस बयान का खंडन किया

दिग्विजय ने मध्य प्रदेश के भिंड में शनिवार शाम को संवाददाताओं से कहा, 'बजरंग दल और भाजपा आइएसआइ (पाकिस्तान की खुफिया एजंसी) से पैसा ले रहे हैं। इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आइएसआइ के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर-मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इस बात को भी समझ लीजिए।' भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि खबरों में बने रहने के लिए वे ऐसे बयान देते हैं। चौहान ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा, 'दिग्विजय सिंह जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं। वह और उनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उनकी विश्वसनीयता बची नहीं है। मैं उनके बयान को इसलिए गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि सारा देश संघ और भाजपा की देशभक्ति को जानता है, हमें दिग्विजय जी के प्रमाण की जरूरत नहीं है।' उन्होंने लिखा है, 'दिग्विजय सिंह, ओसामा जी और हफीज जी कहने वाले नेता हैं। वह विवादित बयान इसलिए देते हैं, ताकि सुर्खियों में बने रहें।

तत्काल से रेलवे को मिले 25,000 करोड़

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

तत्काल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों से रेलवे ने गत चार साल में 25,392 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मिली है। रेलवे ने वर्ष 2016 से 2019 के बीच तत्काल कोटे से 21,530 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं 3,862 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्रीमियम तत्काल टिकटों से हुई है।

तत्काल टिकट बुकिंग सेवा 1997 में चुनिंदा रेलगाड़ियों में शुरू की गई थी। इसका मकसद अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा देना था। वर्ष 2004 में तत्काल टिकट बुकिंग सेवा का विस्तार पूरे देश में किया गया। तत्काल टिकट के तहत द्वितीय श्रेणी में मूल किराए से 10 फीसद अतिरिक्त वसूला जाता है जबकि बाकी अन्य श्रेणियों में यह राशि मूल किराए की 30 फीसद है। हालांकि इस शुल्क में भी न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय की गई है। प्रीमियम तत्काल सेवा 2014 में शुरू की गई थी और 50 फीसद तत्काल कोटे की सीटों की बुकिंग इसके तहत डायनेमिक किराया प्रणाली (सीट उपलब्धता के आधार पर कीमत) से होती है। मध्य प्रदेश के आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर रेलवे ने बताया कि 2016-17 में तत्काल टिकट से रेलवे को 6,672 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। जो 2017-18 में बढ़कर 6,952 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। रेलवे के मुताबिक तत्काल योजना अभी 2,677 रेलगाड़ियों में लागू है और कुल 11.57 लाख सीटों में 1.71 लाख सीटों पर बुकिंग तत्काल कोटे के तहत होती है।

1997 में तत्काल टिकट बुकिंग सेवा चुनिंदा रेलगाड़ियों में शुरू की गई थी। इसका मकसद अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा देना था।

2,677 रेलगाड़ियों में लागू है तत्काल योजना अभी और कुल 11.57 लाख सीटों में 1.71 लाख सीटों पर बुकिंग तत्काल कोटे के तहत होती है।

चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक अंतिम कक्षा में पहुंचा

बंगलुरु, 1 सितंबर (भाषा)।

इसरो ने रविवार को कहा कि उसने चंद्रयान-2 को चंद्रमा की पांचवीं एवं अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराया और वह दो सितंबर को लैंडर को ऑर्बिटर से अलग करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद कहा कि अंतरिक्ष यान की सभी गतिविधियां सामान्य हैं।

इसरो ने कहा कि प्रणोदन प्रणाली का प्रयोग करते हुए चंद्रयान-2 अंतरिक्षयान को चंद्रमा की अंतिम एवं पांचवीं कक्षा में रविवार को (एक सितंबर, 2019) सफलतापूर्वक प्रवेश कराने का कार्य योजना के मुताबिक छह बजकर 21 मिनट पर शुरू किया गया। चंद्रमा की पांचवीं कक्षा में प्रवेश कराने की इस पूरी प्रक्रिया में 52 सेकेंड का समय लगा। एजंसी ने कहा कि उसका अगला कदम चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से 'विक्रम' लैंडर को अलग करना है जो दो सितंबर को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट से एक बजकर 45 मिनट के बीच किया जाएगा।

'विक्रम' लैंडर सात सितंबर को तड़के डेढ़ बजे से ढाई बजे के बीच चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Yogesh W/O Mayank Pathak R/O Bp-143, Shalimar Bagh, Delhi-110088. Have Changed My Name To Bhawna Pathak. 0040510338-5

I, Sonam Kumar W/o Harish Kumar R/o 17-D, Shatabdi Vihar Sector-61, Noida-201301(U.P.) have changed my name to Sonam Kumari for all future purposes. 0040510339-2

I, Sakshi Ghosh D/o.Late.Sh. Ganesh Chandra Ghosh R/o House.No.E-112-B,Sector-11,Pratap Vihar,Ghaziabad, UP,that the name "Baby Goldy" is my Child-Hood/ Nick name my correct and full name is Sakshi Ghosh which may be amended accordingly. 0040510351-1

I Arpit Kumar S/o Sh.Sunder Lal Aggarwal R/o 1628A, Gali No. 4/8, Jain Nagar, Karala, Delhi-110081 have changed my name to Arpit Aggarwal for all purposes. 0040510366-2

I, Shakuntala Devi W/o Chandermani R/o 17-D, Shatabdi Vihar Sector-61, Noida-201301 (U.P.) have changed my name to Shakuntla Devi for all future purposes. 0040510339-1

I, Sanjiv Gupta S/O Sudarshan Gupta R/O Hd-19,Vishakha Enclave, Pitampura, Delhi-110034. Have Changed My Name To Sanjeev Kumar Gupta. 0040510338-9

I, Manju Mishra W/O Sanjay Kumar R/O Khno. 48/16, Gali no.37/2c, B-Block, Kaushik Enclave, Burari, Delhi-110084. Changed My Name To Manju Durgapal. 0040510338-7

I, Kapil S/O Anil Kumar R/O 470/G-16,Chandan Vihar,West Sant Nagar, Burari, Delhi-110084. Changed My Name To Kapil Kumar. 0040510338-6

I, Dipti Grover W/o Harpreet Singh R/o-A4/47, Sector 17, Rohini Delhi, have change my name to Dipti Kaur for all purposes. 0040510293-2

I, Bhagwati Prasad S/O Jai Dutt Mamgain R/O 33 A, JU-Block, Pitampura, Delhi-110034.Have Changed My Name To Bhagwati Prasad Mamgain. 0040510338-8

I, Amit Kumar Gupta S/o, Mahender Gupta R/o G-4/17-18, GF, Sector-16, Rohini, Delhi-89 have changed my name to Amit Gupta for all purposes. 0040510338-4

I Asha Rani D/o Sh. Jai Chand R/o 1628A, Gali No. 4/8, Jain Nagar, Karala, Delhi -110081 have changed my name to Asha Aggarwal for all purposes. 0040510366-1

खोया+पाया

I Veena Takhtani have lost my Property Document on 25 July 2019 from Ramesh Nagar Market of E/349 Ramesh Nagar ND-15, If found contact 9815109194 0040510324-1

सार्वजनिक सूचना

नोटिस

PUBLIC NOTICE

Through this Public Notice that my client, SHRI HARDEV SINGH, Aged 68 Years, S/O Late Shri Swaran Singh R/O 207/9, Parkash Mohalla, Garhi, East of Kailash, New Delhi-65 has debarred his younger son MR. JAGJIT SINGH S/O Sh. Hardev Singh R/O 207/9, Parkash Mohalla, Garhi, East of Kailash, New Delhi-65, his wife MRS. MANDEEP KAUR D/O Late Shri Ashwani Kumar and their son MASTER ISHMEET SINGH and their daughter MS. ARSHPREET from all his movable and immoveable properties/assets. Any person deals with them in any manner who will be sole responsible for all acts, deeds and consequences.

Ajay Seth (Advocate)
Regn. No. 10659
Ch.No. 351, Lawyers Chambers, Distt. Court Saket, New Delhi-17

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
IAS GS World PCS
Committed To Excellence
Now in English Medium...
GENERAL STUDIES
Foundation Batch
Starts with
Environment & Ecology
Today
03:00 PM
With Weekly Current Affairs Classes
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
011- 27658013, 7042772062/63
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

हमीरपुर से कांग्रेस ने हरदीपक निषाद को बनाया उम्मीदवार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रविवार को हरदीपक निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिये हरदीपक निषाद की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है।

भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल को हत्या मामले में दोषी पाये जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव होना है।

बंगाल में झड़प के दौरान भाजपा सांसद घायल

कोलकाता, 1 सितंबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में सड़क जाम कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस के कथित लाठीचार्ज में रविवार को भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के सिर में चोट लग गई। सिंह ने दावा किया कि बैरकपुर पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने उन पर हमला किया, जिससे उनके सिर पर चोट लगी।

खून से सनी कमीज पहने और सिर पर पट्टी बांधे हुए सांसद ने कहा कि वर्मा एक पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने श्यामनगर में भाजपा के पार्टी कार्यालय के कब्जे को लेकर पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई की। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि कांकीनारा में दो समूहों के बीच एक झड़प के दौरान पथराव में सिंह को चोट लगी। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि सड़क जाम कर रही भीड़ ने पुलिस अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही उन पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और सड़क को खाली कराने के लिए लाठी चार्ज किया। श्यामनगर और कांकीनारा, दोनों ही इलाके बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आते हैं, जहां से सिंह सांसद हैं। सिंह के भाजपा टिकट पर चुनाव जीतने के बाद से क्षेत्र के भाटपारा और कांकीनारा सहित कई इलाके हिंसा की गिरफ्त में रहे हैं। वे तृणमूल कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए थे।

मार्च अंत तक आ सकता है देश का पहला प्रादेशिक खुशहाली सूचकांक

इंदौर, 1 सितंबर (भाषा)।

देश में अपनी तरह के पहले सरकारी अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 'हैप्पीनेस इंडेक्स' मापने की उल्टी गिनती आखिरकार शुरू होती नजर आ रही है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सूबे के नागरिकों की खुशहाली का सूचकांक घोषित हो जाएगा।

प्रदेश सरकार के राज्य आनंद संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अखिलेश अर्गल ने बताया, 'खुशहाली सूचकांक' मापने के लिए हम सर्वेक्षण की प्रश्नावली को अंतिम रूप दे रहे हैं। यह सर्वेक्षण नवंबर में शुरू होना है। हमारा लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सर्वेक्षण पूरा कर सूबे का 'हैप्पिनेस इंडेक्स' घोषित कर दिया जाए।' उन्होंने बताया कि देश में अपनी तरह के पहले सर्वेक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के रेखी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पिनेस को अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है। अर्गल ने बताया कि हैप्पिनेस इंडेक्स मापने के सर्वेक्षण में सूबे के गांवों, कस्बों और शहरों के करीब 15,000 लोगों से सीधा संपर्क किया जाएगा।

पहला खुशहाली सूचकांक

हैप्पीनेस इंडेक्स मापने के सर्वेक्षण में सूबे के गांवों, कस्बों और शहरों के करीब 15,000 लोगों से सीधा संपर्क किया जाएगा। सर्वेक्षण में उनकी जीवनशैली, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उपलब्धियों, अभिरुचियों, सकारात्मक व नकारात्मक भावनाओं, मानवीय संबंधों, जिंदगी के प्रति संतुष्टि के भाव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, पर्यावरण से जुड़ाव, दिनचर्या में समय के उपयोग आदि विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे।

सर्वेक्षण में उनकी जीवनशैली, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उपलब्धियों, अभिरुचियों, सकारात्मक व नकारात्मक भावनाओं, मानवीय संबंधों, जिंदगी के प्रति संतुष्टि के भाव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, पर्यावरण से जुड़ाव, दिनचर्या में समय के उपयोग आदि विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे।

उन्होंने बताया, 'सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सूबे के नागरिकों का हैप्पिनेस इंडेक्स घोषित किया जाएगा। इससे लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के उपाय करने में प्रदेश सरकार को खासी मदद मिलेगी।' अर्गल ने कहा कि नागरिकों के हैप्पिनेस इंडेक्स मापने के अभियान अब तक विदेशों में ही चले हैं। प्रदेश में इस सूचकांक का वास्तविक स्तर पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की प्रश्नावली को भारतीय और स्थानीय सांचे में ढाला जा रहा है।

बहरहाल, अहम सवाल यह है कि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से भरे सूबे में क्या नागरिकों की खुशहाली का कोई साझा सूचकांक घोषित किया जा सकता है? इस प्रश्न पर राज्य आनंद संस्थान के सीईओ ने कहा, 'यह सच है कि प्रसन्नता सापेक्ष होती है और हर आदमी की खुशी के कारण अलग-अलग होते हैं। इसके बावजूद हम हैप्पिनेस इंडेक्स घोषित करने के लिए सर्वेक्षण की ऐसी पद्धति गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समाज के सभी तबकों की प्रसन्नता के स्तर की सामूहिक तौर पर थाह ली जा सके।'

56 देशों में खुशहाली के स्तर को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 20 मार्च को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत पिछले साल के मुकाबले सात पायदान नीचे खिसककर 140वें स्थान पर रहा है। इस फेहरिस्त में भारत वर्ष 2018 में 133वें स्थान पर था।

खबरों में शहर

भाजपा की ली सदस्यता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रविवार को बदरपुर विधानसभा में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। यह सदस्यता अभियान बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के बदरपुर वार्ड, मोलड़बंद वार्ड, हरिनगर वार्ड, मीठापुर वार्ड और जैतपुर वार्ड में आयोजित किया गया। रामबीर सिंह ने कहा कि इस दौरान सभी उम्र वर्ग के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। महिलाएं भी भाजपा में शामिल हुईं।

रामलीला भूमि पूजन समारोह शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

दिल्ली में रामलीलाओं के लिए भूमि पूजन शुरू हो गया है। रविवार को श्री केशव रामलीला कमेटी रोहिणी और श्री राम वाटिका तिकोना पार्क कश्मीरी गेट पर भूमि पूजन समारोह हुआ। रोहिणी में विधायक तो कश्मीरी गेट में मेयर शामिल हुए। केशव रामलीला कमेटी रोहिणी पश्चिमी मेट्रो के पास 21 ब्राह्मणों से भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न कराते हुए कलाकारों ने रामलीला मंचन की झलकियां भी प्रस्तुत कीं। कमेटी के चैयरमेन विपिन कुमार गोयल और मुख्य संरक्षक मिथलेश कुमार अग्रवाल के मुताबिक इस बार के रामलीला मंचन का मुख्य आकर्षण श्रीमद भागवत गीता का पाठ है जो आचार्य भरत जी महाराज करेंगे।

छात्र के साथ दुर्व्यवहार पर पुलिस खुद फंसी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

दिल्ली पुलिस ने आदर्श नगर थाने के अधिकारियों के खिलाफ विधि के तीसरे वर्ष के एक छात्र के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया है। उत्तर-पश्चिम की पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य ने कहा कि प्रमोद कुमार की शिकायत पर एससी-एसटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच शुरू की गई है। विधि की पढ़ाई कर रहे कुमार ने आरोप लगाया है कि आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिसकर्मियों ने न केवल उसे प्रताड़ित किया, पिटाई की और गाली दी, यहां तक कि जातिवादी टिप्पणी भी की। कथित उत्पीड़न के विरोध में शनिवार रात को दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के कई छात्र आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए।

तनाव को कम करने के लिए होगी कार्यशाला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

बच्चों में परीक्षाओं और बड़ों में जीवन से तमाम चुनौतियों से पैदा तनाव को कम करने के लिए मानसिक रोग विशेषज्ञों ने राजधानी में दो कार्यशालाएं आयोजित करने का फैसला किया है। 15 सितंबर को आयोजित होने वालीं इन कार्यशालाओं में जहां बच्चों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे, वहीं बड़ों के लिए भी खास परिचर्चा रखी गई है।

दिल्ली विधानसभा शोध केंद्र का उद्घाटन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली विधानसभा के शोध केंद्र का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

एक्सप्रेसकर्मी सेवानिवृत्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

इंडियन एक्सप्रेस समूह के प्रोसेस विभाग में बतौर सीनियर कैमरामैन कार्यरत राजेश अरोड़ा 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। रविवार को नोएडा दफ्तर में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रबंधन और उनके साथियों ने उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उपहार भेंट किए और स्वस्थ रहने की कामना की।

रविवार से देश भर में लागू हुआ मोटर वाहन (संशोधन) कानून-2019

दिल्ली में पहले दिन कटे 3900 चालान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

दिल्ली समेत पूरे देश में मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 एक सितंबर को लागू हो गया। रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी दिल्ली यातायात पुलिस ने शाम तक 3900 वाहन चालकों को नियम तोड़ने के आरोप में चालान काटे।

सड़क पर चलते समय अब यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर पहले की तुलना में कई गुणा चालान की राशी बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद भी वाहन चालक निमयों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। नए नियम के तहत वाहन चालक मौके पर चालान की धनराशि का भुगतान नहीं कर सकेंगे। उनको अब आदालत में जाकर ही चालान की धनराशि जमा करनी होगा। मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 रविवार से लागू होने के बाद भैरों मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस ने जांच अभियान चलाया। साथ ही दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास वाहन चलते समय फोन पर बात करने पर चालक का चालान किया गया। इसी तरह नजफगढ़ रोड पर कई वाहन चालकों को रोककर पुलिस ने गाड़ी के कागज और लाइसेंस की जांच की। यहां पर भी नियम तोड़ने वालों का पुलिस अधिकारी ने चालान काटे। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि नए निमय लागू होने के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। छुट्टी का दिन होने के बाद भी बड़ी संख्या में वाहन चालक नियम को तोड़ते पाए गए। शाहदरा जीटी रोड पर सवारी ई-रिक्शा में माल ढोने और कार चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने पर नए नियमों के तहत चालान किया गया।

वहीं, रोहिणी में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान काटा गया। खुरेजी चौक पर कई वाहन चालकों का चालान किया गया। रिंग रोड पर वाहन चालकों को रोककर यातायात पुलिस ने चालान किया। कई लोग चालान से बचने की कोशिश करते हुए भी नजर आए।

एक सितंबर यानी रविवार से देशभर में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 लागू हो गया है। इसके तहत अब वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है।

नए नियम की खास बातें

- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब पांच हजार रुपए का चालान, पहले सिफ पांच सौ रुपए का था।
- नाबालिग वाहन चलाता है तो दस हजार का चालान कटेगा जबकि पहले मात्र 500 रुपए था। साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।
- शराब पीकर वाहन चलाने पर छह महीने तक की सजा या फिर दस हजार रुपए का तक का जुमार्ना भरना पड़ सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना।
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपए का चालान है, जबकि पहले 100 रुपए था।
- निर्धारित से अधिक गति पर गाड़ी चलाई तो एक से दो हजार रुपए तक का चालान काटा जाएगा।

यहां काटे गए चालान

नए नियम लागू होने के बाद भैरों मार्ग, रिंग रोड, नजफगढ़, खुरेजी चौक, बुराड़ी, मुकरबा चौक, सिंघु बोर्डर, पीरागढ़ी, राजा गार्डन, पंजाबी बाग, मायापुरी, धौंला कुआं चौक, लाजपत नगर, भोगल आश्रम, बदरपुर बोर्डर, खजूरी चौक, आनंद विहार, गगन सिनेमा, शाहदरा जीटी रोड व अन्य इलाकों में यातायात पुलिस अधिकारी वाहन चालकों का चालान काटते नजर आए।

बच्चा चोरी संदेह पर पिटाई करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बच्चा चोरी के संदेह में भीड़ के हाथों मूक-बधिर गर्भवती महिला की पिटाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला के परिवार ने इस घटना को लेकर हर्ष विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

जिले के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर के मुताबिक हर्ष विहार में 27 अगस्त को चार महीने की गर्भवती महिला की बच्चा चोर होने के संदेह में पिटाई की गई थी। दक्षिण-पूर्व के तुगलकाबाद की इस महिला को उसके परिवार ने अस्पताल में भर्ती कराया है और उसकी हालत स्थिर है। हमने तीन व्यक्तियों दीपक (27), बी शंकुतला (52) और ललित कुमार (29) को गिरफ्तार किया है। तीनों मंडोली के निवासी हैं। उधर, महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने 18 अगस्त को फरीदाबाद में उसे घर से निकाल दिया था और तब से वह गायब थी। वह किसी तरह हर्ष विहार पहुंची और फुटपाथ पर रह रही थी। स्थानीय लोग उसे खाना दे देते थे लेकिन 27 अगस्त को उन्होंने बच्चा चोरी के आरोपों को लेकर उस पर हमला किया। परिवार इस घटना का वीडियो देखने के बाद दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा।

फोटो : अरुष चोपड़ा

मुख्यमंत्री ने अपने घर से की डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार सहित किया पूरे घर का निरीक्षण
- सिसोदिया, गोपालराय, राजेंद्र गौतम और आतिशी ने भी अपने घरों का निरीक्षण किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत अपने घर से की और इस दौरान उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया ताकि कहीं पानी जमा न हो। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, गोपालराय, राजेंद्र पाल गौतम और आतिशी सहित दिल्ली सरकार के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने भी अपने घरों का निरीक्षण किया ताकि कहीं जमा पानी न हो।

केजरीवाल ने ट्वीट किया-मेरे परिवार और मैंने अपने घर का निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि घर के किसी हिस्से में साफ पानी जमा न हो। यह आपके परिवार को डेंगू से बचाने का बेहतरीन तरीका है। मैं यह देखकर खुश हूं कि पूरी दिल्ली के लोग इस अभियान # 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में दिल्ली के लोगों से एक सितंबर से 15 नवंबर के बीच हर रविवार दस मिनट यह सुनिश्चित करने में व्यतीत करने की अपील की कि उनके घरों में और आसपास पानी जमा नहीं हो।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि शनिवार को मुझे इंस्टाग्राम पर किया गया सर्वेक्षण मिला। मैंने प्रतिभागियों से पूछा कि क्या वे जानते हैं कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि 35 फीसद प्रतिभागियों ने बताया कि डेंगू के मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर (एडीज एजिप्टी) साफ पानी में पनपते हैं जो सामान्यतः हमारे घरों में होता है। ये मच्छर 200 मीटर से अधिक दूरी तक नहीं उड़ सकते। इसका मतलब है कि ये आप के घर में या पड़ोस में पनपते हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में डेंगू के 15,000 मामले सामने आए थे और 60 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में यह संख्या घटकर 2,798 और चार मौतों पर आ गई। हम इसे कम करना चाहते हैं। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस साल डेंगू से एक भी मौत न हो।

'समकालीन कविता की प्रतिध्वनियां' पर कविता पाठ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर के मासिक साहित्यिक कार्यक्रम 'डायलॉग' में 'समकालीन कविता की प्रतिध्वनियां' विषय पर समकालीन कवित्रियों ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि मिथिलेश श्रीवास्तव ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर चर्चित कवि और आजकल पत्रिका के संपादक राकेश रेणु, उपेंद्र कुमार और विमल कुमार रहे।

आमंत्रित कवित्रियों में रंजिता सिंह, मौली सेठ, प्रीति राघव, पुष्पलता सिंह, दिव्या जैन, अंजू शर्मा, ममता जयंत और नेहा नाहट शामिल रहीं। कविता पाठ की शुरुआत प्रीति राघव ने अमृता प्रीतम को समर्पित अपनी कविता 'तुम मत आना अमृत' से की जिसमें अमृता की वेदना को दर्शाई गई है। ममता जैन की कविता 'मेरा बचपन तुमसे अच्छा' श्रोताओं ने खूब सराहा। दिव्या जैन ने बचपन, जवानी और बुढ़ापा पर 'लौट कर गुजरी घड़ी' गजल प्रस्तुत की। स्वागत वक्तव्य कविता अमित ने किया।

अनुच्छेद 370 और पर्यावरण के मुद्दों पर लड़ा जाएगा डूसू चुनाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

- डूसू के सभी चारों पदों पर एबीवीपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं : श्रीनिवास

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के सभी चारों पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवार जीत रहे हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने बताया कि वह अनुच्छेद 370 और पर्यावरण जैसे मुद्दों को लेकर इन चुनावों में डीयू के विद्यार्थियों के सामने जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। श्रीनिवास ने कहा कि हालत यह है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) को चुनाव में उतारने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं।

श्रीनिवास ने कहा कि एबीवीपी नीत डूसू ने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि यह सभी जानते हैं कि डीयू में छात्रावासों की बहुत कमी है और हम इस समस्या को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से छात्रावासों के निर्माण में पूरा सहयोग करने का वादा किया गया था। 2019-20 में डूसू ने विशेषकर छात्राओं के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें साहसी आदि कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस साल हम विद्यार्थियों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाएंगे। इसमें 'मेरी यमुना, स्वच्छ यमुना' प्रमुख है।

श्रीनिवास ने कहा कि आइसा को इस बार जेएनयू छात्र संघ में अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी नहीं मिली है। यह आइसा के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी जेएनयू में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और हमें परिणामों से बहुत उम्मीद हैं।

हार्दिक पटेल मामले पर एनएसयूआइ ने दिया जवाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआइ) बीते दिनों जेएनयू में एक मशाल जूलुस निकाला था। इस दौरान गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के जूलुस में शामिल होने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जेएनयू छात्र संघ चुनाव समिति ने एनएसयूआइ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनएसयूआइ जेएनयू के छात्र नेता मसूद अहमद ने बताया कि कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया गया है।

अहमद ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर जेएनयू में एक मशाल जूलुस का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुछ क्षण के लिए हार्दिक पटेल वहां आए जरूर थे लेकिन हमारे मना करने के बाद वह अपने मित्रों से मिलने चले गए थे। उन्होंने बताया कि पेटल को एनएसयूआइ की ओर से जूलुस के लिए न कोई निमंत्रण दिया गया था न ही हमें उनके आने की जानकारी थी।

Management Aptitude Test
MAT
SEPTEMBER 2019
AIMA
ALL INDIA MANAGEMENT ASSOCIATION
Eligibility: Graduates / Final year students of any Graduate Course
For registration log on to
https://mat.aima.in
Computer Based Test (CBT)
Online Registration ends : 08 Sept '19
Test Date : 14 Sept '19
Paper Based Test (PBT)
Online Registration ends : 16 Sept '19
Test Date (Revised) : 21 Sept '19
Important: Previous MAT candidates can apply again
Candidates may apply for both PBT and CBT

शिक्षा निदेशक कर्नल सिंह को नौकरी बचाने के लिए खानी पड़ रही हैं ठोकरें

अब वे न निगम के रहे न सेना के

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

सेना में कर्नल की नौकरी कर रहे अशोक कुमार सिंह ने डिपुटेशन पर अखिल भारतीय स्तरीय चयन के बाद तीन साल के लिए पूर्वी निगम में बतौर शिक्षा निदेशक नौकरी शुरू की लेकिन निगम में शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बीड़ा उठाना उन्हें महंगा पड़ गया। शिक्षा विभाग में भर्तियां, स्थानांतरण, तैनाती, विभागीय खरीद बिक्री के साथ अन्य अनियमितताओं और नियम के खिलाफ हो रहे काम को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल और ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाने जैसी व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने की उनकी योजना उन्हें निगम से ही बेदखल कर देने पर आतुर है।

निगम प्रशासन ने उन्हें तय समय से पहले वापस सेना में भेजने का आदेश जारी कर दिया लेकिन सेना ने उन्हें यह कहकर निगम में ही रहने को कह दिया है कि इस तरह की वापसी डिपुटेशन के लिए सर्विस कोड में दिए गए नियम का उल्लंघन हो सकता है। लिहाजा सिंह निगम के भी नहीं रहे हैं। इस समय सिवाय दफ्तरों के चक्कर काटने के और कुछ नहीं बचा है। इस बारे में जब पूर्वी दिल्ली के मेयर अंजू कमलकांत से बात की गई तो उनका कहना था कि सिंह का मामला उनके संज्ञान में लाया गया है। वे कैट में भी गए थे। उपमेयर संजय गोयल ने उनके लिए मुझे लिखा है लिहाजा निगम की आम सभा में इस बाबत चर्चा की जाएगी। मेयर ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति गठित कर मामले की जांच जाएगी और फिर जांच समिति की रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आएगा उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा।

वे 2018 के अगस्त में निगम में सेना से डिपुटेशन पर तीन साल के लिए आए थे। अभियान सफल भी हो गया और निगम के आयुक्त दिलराज कौर ने आनन-फानन में सिंह को वापस उनके मूल कैडर सेना में भेजने का आदेश जारी कर दिया। यहां से शुरू हुआ सिंह और निगम में कानूनी लड़ाई का दौर। सिंह मामले को लेकर कैट में चले गए। नौ जुलाई को आयुक्त कौर ने सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर उनके ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने कहा। सिंह अभी जवाब देने की तैयारी कर रहे थे तभी दस जुलाई को ही उनका जवाब सुने और देखे बिना उन्हें निगम से जाने का आदेश दे दिया गया। जुलाई में हुए इस आदेश के बाद कैट में सुनवाई शुरू हुई। दोनों तरफ से दी गई दलील सुनने के बाद कैट ने नौ जुलाई के कारण बताओ नोटिस को अपील में नहीं लिखने की बात कहकर सिंह को मामला वापस लेने और निगम आयुक्त को सिंह की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कानून के मुताबिक उसके समाधान निकालने के आदेश दिए लेकिन 14 अगस्त को निगम ने बिना कैट के फैसले को देखे सिंह को सेना में वापस भेज दिया। इस मानसिक प्रताड़ना से सिंह चार-पांच दिन तक बीमार रहे और जब 21 अगस्त को वे अपने मूल कैडर सेना में गए तो वहां सेना ने निगम को यह लिखकर दिया कि चुंकि डिपुटेशन के कुछ नियम और कानून होते हैं और शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि इस कानून की बारीकियों को जाने बिना ही सिंह को वापस मूल कैडर में भेजा गया है लिहाजा यह तुरंत संभव नहीं है और इसलिए एमओटी के मुताबिक सिंह की मूल वापसी के लिए छह महीने का समय दिया जाए और तब तक उन्हें निगम में सामंजस्य करने का रास्ता निकाला जाए।

SRF FOUNDATION
स्पिक मैके
एस आर एफ विरासत
परम पावन दलाई लामा द्वारा संबोधन
स्कूल के छात्रों के लिए मन और हृदय को शिक्षित करने हेतु

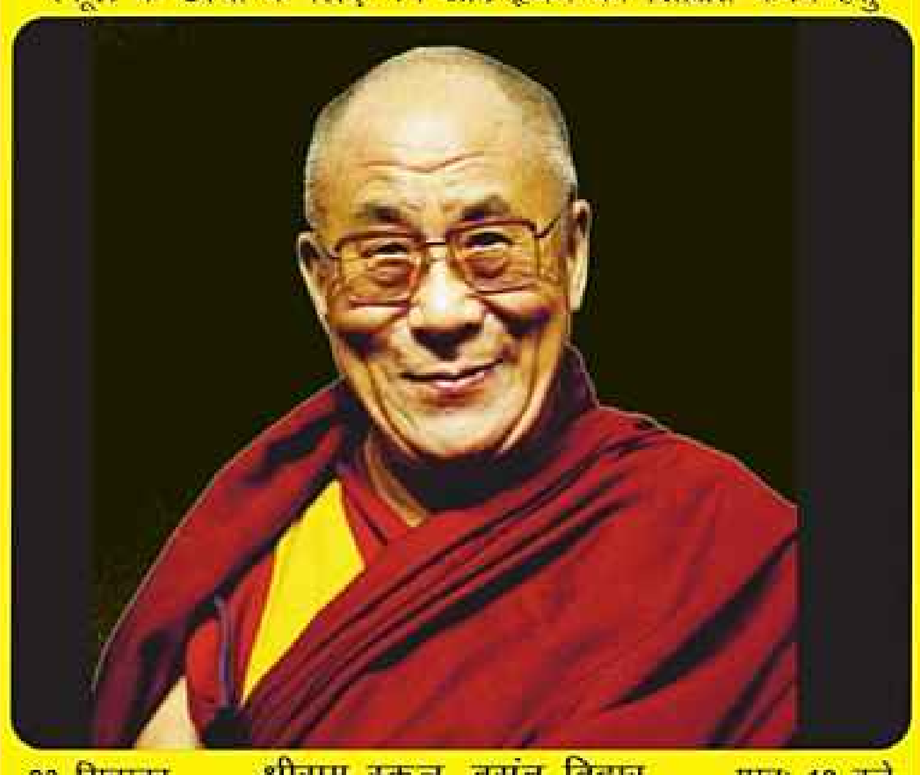

20 सितम्बर
श्रीराम स्कूल, वसंत विहार
प्रातः 10 बजे
स्कूली द्वारा पंजीकरण 13 सितंबर तक अनिवार्य है
सम्पर्क: giri.rajiv@spicmacay.com, 9899465665
(प्रत्येक विद्यालय से 5 छात्र और 1 शिक्षक)
अधिक जानकारी के लिए देखें www.spicmacay.com
स्पिक मैके 41/42, लखनऊ रोड, दिल्ली-110054
PIONEER

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	33.5 डि.से.	33.5 डि.से.	34.0 डि.से.	35.0 डि.से.
न्यूनतम	26.4 डि.से.	26.4 डि.से.	27.0 डि.से.	27.0 डि.से.

'थापर से माफी मांगे जेएनयू'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन की ओर से इतिहासकार रोमिला थापर को भेजे गए पत्र को जेएनयू शिक्षक संघ ने उनको अपमानित करने के लिए उठाया गया राजनीतिक कदम बताया है। संघ के अध्यक्ष और सचिव ने पत्र की कड़ी निंदा करते हुए विवि प्रशासन से तत्काल इस मामले में रोमिला थापर से माफी मांगने की मांग की है। शिक्षक संघ का कहना है कि जेएनयू प्रशासन ने पत्र लिखकर जेएनयू की पढ़ाने और सीखने की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया है। एमेरिटस प्रोफेसर के लिए रोमिला थापर का मनोयन एक सम्मान की पदवी है, जो जीवन भर के लिए उन्हें जेएनयू के निर्माण में उनकी सेवाओं के बदले दी गई। इस मामले को लेकर जेएनयू प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि जेएनयू अधिनियम के मुताबिक अगर कोई एमेरिटस प्रोफेसर 75 साल की आयु पूरी कर लेता है, तो उनके काम के मूल्यांकन का अधिकार प्रशासन के पास है और सीवी मंगाना

उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

जेएनयू प्रशासन ने इतिहासकार थापर को पत्र लिखकर उनसे उनका शैक्षिक अभिलेख व कार्य अनुभव का विवरण (सीवी) जमा कराने को कहा है। दरअसल, विश्वविद्यालय प्रशासन थापर की सेवाओं को जारी रखने के लिए उनके कामों का मूल्यांकन करेगा। थापर 1993 से जेएनयू में बतौर एमेरिटस प्रोफेसर सेवाएं दे रही हैं जबकि इससे पहले वह दो दशकों तक जेएनयू में ही प्रोफेसर रही हैं। जेएनयू रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार की ओर से थापर को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। बीते महीने जारी किए गए इस पत्र में जेएनयू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनके काम का मूल्यांकन करना चाहता है, जिसके लिए उनका सीवी आवश्यक है। रजिस्ट्रार की ओर से जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि जेएनयू प्रशासन ने उनके कामों के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। यह समिति इस पर अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर उनकी सेवाओं को जारी रखने या नहीं रखने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में जेएनयू प्रशासन कहा है कि जेएनयू अधिनियम के मुताबिक अगर कोई एमेरिटस प्रोफेसर 75 साल की आयु पूरी कर लेता है, तो उनके काम के मूल्यांकन का अधिकार प्रशासन के पास है और सीवी मंगाना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

एमेरिटस प्रोफेसर मामले में सिर्फ प्रक्रिया का पालन हो रहा है : सचिव

एचआरडी मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रह्मयण्म ने ट्वीट कर कहा कि एमेरिटस प्रोफेसर विवाद पर जेएनयू के कुलपति से बातचीत हुई है। किसी एमेरिटस प्रोफेसर, विशेषकर सम्मानित शिक्षाविदों, के दर्जे में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। सिर्फ प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

डॉक्टर ने की खुदकुशी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

जीटीबी अस्पताल में एक डॉक्टर ने छत से कूद कर जान दे दी। घटना की सूचना शनिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे पुलिस को मिली थी। डॉक्टर की पहचान पल्लव सहारिया (44) के रूप में हुई है। पल्लव मूलरूप से गुवाहटी, असम के रहने वाले थे। उनकी पत्नी जीटीबी अस्पताल में कार्यरत हैं। वह पत्नी के साथ मिले सरकारी आवास में रहते थे। वह इन दिनों नोएडा स्थित एक लैब में नौकरी करते थे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण आत्महत्या के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस आत्महत्या का मामला मान कर चल रही है।

जानकारी के मुताबिक मूलरूप से गुवाहाटी, असम के रहने वाले डॉ पल्लब नोएडा स्थित सीआरएन डायग्नोस्टिक सेंटर में पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत थे।

बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर युवक को पीटा, आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 सितंबर।

सेक्टर-45 में शनिवार देर रात बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर एक युवक को तीन लोगों ने लाठी-डंडों से जमकर पीटा। सूचना मिलने पर पहुंची थाना सेक्टर-39 पुलिस ने घायल युवक को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाया। पूछताछ में बच्चा चोरी करने की सूचना झूठी निकली। पुलिस ने युवक को पीटने वाले तीनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। युवक की पहचान एस. गुप्ता निवासी सेक्टर-45 के रूप में हुई है।

सेक्टर-45 में बालगिरी मंदिर है। आरोप है कि शनिवार रात करीब साढ़े दस बजे बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर विशाल, महिपाल और संतोष ने लाठी-डंडों से जमकर पीटा। पीटते हुए तीनों बच्चा चोर-बच्चा चोर कह रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस प्रक्रिया वाहन (पीआरवी) मौके पर पहुंची। तब तक पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। पुलिसकर्मियों ने पिट रहे युवक को बचाया। जब पुलिसकर्मियों ने पिटाई करने वाले तीनों से पूछताछ की तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर तीनों को गिरफ्तार किया। एसएचओ नीरज मलिक के मुताबिक तीनों आरोपियों ने बच्चा चोर होने की अफवाह फैलाकर युवक की पिटाई की है।

मरीज की मौत पर अस्पताल में परिजनों ने काटा हंगामा

सेक्टर- 62 स्थित एक नामी अस्पताल पर इलाज के दौरान महिला की मौत होने पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। परिजनों ने अस्पताल पर मौत होने के बाद भी मृत शरीर पर जांच उपकरण लगाकर रकम वसूलने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची थाना सेक्टर-58 पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

हरित स्वराज संवाद और पानी बाबा फाउंडेशन : अरुण कुमार पानीबाबा की जयंती उत्सव पर विषमुक्त अन्नजल : जैविक खेती-पानी की चुनौतियां पर विचार गोष्ठी, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आइटीओ, सुबह 10:30 बजे से।

इंडिया हेबीटेट सेंटर : 'द क्राइसिस इन ह्यूमन अफेयर्स : ए नोवेल पर्सपेक्टिव वीयांड कन्वेंशनल ट्राप्स' पर चर्चा, गुलमोहर हाल, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

आम्रपाली मामला : कई निवेशक संदेह के दायरे में

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 सितंबर।

आम्रपाली की परियोजनाओं में कब्जा ले चुके खरीदारों की रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले सैफायर परियोजना की सूची जारी की गई है लेकिन काफी ऐसे निवेशक हैं, जिन्होंने अभी तक प्राधिकरण अधिकारियों से रजिस्ट्री के लिए संपर्क तक नहीं किया है। ऐसे निवेशक संदेह के दायरे में हैं क्योंकि कालाधन खपाने वालों के लिए बिल्डर का फॉरेंसिक ऑडिट परेशानी की वजह बन सकता है। निर्धारित दर से कम में खरीदारी करने को एक निर्धारित कीमत के आधार पर अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ताकि अन्य परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिल सके।

इसके लिए एक योजना बनाई गई है। जिसके तहत फ्लैट की बुकिंग या खरीदारी करते समय वर्ष के आधार पर एक दर निर्धारित की जाएगी। ताकि उस समय के सभी फ्लैट खरीदारों के लिए दर बराबर हो सके। यह फैसला फ्लैट को नकद में खरीदने वालों के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। आम्रपाली समूह के तीन निदेशकों के जेल जाने के बाद शीर्ष अदालत ने बची परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को नियुक्त किया है। इसके साथ जिन फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है, उनकी रजिस्ट्री करने के भी आदेश हैं।

इस पर काम शुरू हो चुका है। इस बीच एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में मिली खामियां कई निवेशकों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। एक रुपए लेकर भी फ्लैट की बुकिंग की गई जबकि काफी ऐसे निवेशक हैं, जिन्होंने काफी कम दाम पर फ्लैट खरीदे हैं। ऐसे खरीदारों के लिए माना जा रहा है कि उन्होंने बैंक के बजाए नकद में भुगतान किया होगा।

सड़क हादसे में युवक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

बाहरी दिल्ली के रानी बाग में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस को उस व्यक्ति के पास से ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस आसपास के थानों में संपर्क कर उसकी पहचान करने में जुटी हुई है।

पुलिस के मुताबिक, रविवार सुबह करीब सात बजे पुलिस को सूचना मिली कि रानी बाग के पास एक युवक को एक कार ने टक्कर मार दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए व्यक्ति की उम्र 30 से 35 के बीच की है।

एटीएम कार्ड बदलकर निकाले 45 हजार

दिल्ली में ठगों का कारनामा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के रणहौला का है। यहां सहायता करने की बात कहकर एक व्यक्ति ने महिला का एटीएम कार्ड बदल कर पीड़िता के खाते से 45 हजार रुपए निकाल लिए। पुलिस पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर ठग की पहचान करने में जुटी हुई है।

पीड़िता सुमन परिवार के साथ रणहौला में रहती है। शनिवार दोपहर में वह इलाके में स्थित एक एटीएम से रुपए निकालने गई। कार्ड मशीन में डालने के बाद उसने पासवर्ड डाला लेकिन रुपए नहीं निकले। उसका कार्ड भी मशीन में फंस गया। इसी बीच एटीएम के बाहर खड़ा एक व्यक्ति पीड़िता के पास आया और मदद करने की बात कहकर कार्ड निकाला और झांसा देते हुए कार्ड बदल लिया। पीड़िता कार्ड लेकर दूसरे एटीएम में गई जहां उसे पता चला कि उसका कार्ड बदल लिया गया है।

छात्र की चाकू से हत्या

बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में शनिवार रात बदमाशों ने एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेंद्र सिंह सागर ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की धरपकड़ के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि शनिवार रात सूचना मिली कि सुल्तानपुरी सी-ब्लाक के पास एक युवक घायल हालत में पड़ा हुआ है।

ऑटो सवार बदमाशों ने फौजी को लूटा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 सितंबर।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से शनिवार रात बदमाशों ने ऑटो में बैठाकर एक फौजी को नोएडा में लाकर लूट लिया। आरोप है कि ऑटो में पहले से बैठे बदमाशों ने जबरन शीतल पेय (कोल्ड ड्रिंक) पिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में उससे पांच हजार रुपए, एटीएम कार्ड, मोबाइल और पर्स लूट लिया। चारों बदमाशों ने नशे की हालत में पीड़ित से एटीएम कार्ड का पिन पूछकर खाते में एक दिन पहले आए वेतन समेत 50 हजार रुपए निकाल लिए। आरोपी फौजी को सेक्टर-98 में फेंक कर फरार हो गए। थाना सेक्टर-39 पुलिस ने फौजी की जांच कराने के बाद मामला दर्ज किया। मूल रूप से मध्य प्रदेश के भिंड निवासी राघवेंद्र सिंह रजावत भारतीय सेना में नौकरी करते हैं।

आपकी शिकायतें

यातायात जाम से परेशान बुराड़ी के लोग

बुराड़ी क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यातायात विशेष आयुक्त ताज हसन को समस्यओं के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। यहां के यमुना पुस्ता झरौदा गांव से नगली बाईपास तक बिना किसी के घर तोड़े पुस्ते रोड का चौड़ीकरण, बुराड़ी अथारिटी, बुराड़ी थाना, संत नगर मेन बाजार, बाबा कॉलोनी, अमृत विहार, नत्थूपुरा मोड़ पर फुट ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने के लिए लोगों ने कई बार पहल की है।

शालीमार पैलेस बुराड़ी गांव मुकुंदपुर पुलिस चोकी से जनता विहार चौक तक रोड को चौड़ीकरण करने के लिए रोड के किनारे बने मकान मालिकों से बात कर उन्हें उचित मुआवजा देकर रोड को कम से कम 100 फिट चौरीकरण करने की मांग की जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बुराड़ी के विधायक ने यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। भाग दौड़ की जिंदगी बिता रहे बुराड़ी की जनता को घंटों सड़क पर प्रदूषण झेलना पड़ता है।

-गोपाल झा, भाजपा के पूर्व विधायक उम्मीदवार, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी-नोएडा, सी-03बी, सेक्टर-55, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, (यू.पी.)

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी ने, **भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-नोएडा, सी-03बी, सेक्टर-55, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, (यू.पी.)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **16-05-2019** जारी की थी, जिसमें **कर्जदार श्री कमल कांत पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद,** निवासी मकान सं-711, 7वाँ तल, एल्कॉन अपार्टमेन्ट, प्लॉट सं-19, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद (यू.पी.)-201010 से सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि **रु. 17,64,734/- (शब्दों में- रुपए सत्तरह लाख चौसठ हजार सात सौ चौंतीस मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उपरोक्त कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त (अधिनियम) की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा **27 अगस्त, 2019** को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

एतद्द्वारा, उपरिवर्णित कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार भारतीय स्टेट बैंक की बकाया राशि **रु. 17,64,734/- (शब्दों में- रुपए सत्तरह लाख चौसठ हजार सात सौ चौंतीस मात्र) + एवं भावी ब्याज** चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति के सभी भाग और पार्सलः

मकान संख्या 711, 7वाँ तल, एल्कॉन अपार्टमेन्ट, प्लॉट संख्या-19, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी.

दिनांक : 27-08-2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी-नोएडा, सी-03बी, सेक्टर-55, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, (यू.पी.)

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी ने, **भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-नोएडा, सी-03बी, सेक्टर-55, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, (यू.पी.)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **21-04-2019** जारी की थी, जिसमें **कर्जदार श्री राहुल चौहान पुत्र श्री ब्रह्म सिंह चौहान,** निवासी प्लॉट संख्या बी-26, सेक्टर-105, नोएडा से सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि **रु. 1,34,69,984/- (शब्दों में- रुपए एक करोड़ चौंतीस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ चौरासी मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उपरोक्त कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त (अधिनियम) की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा **27 अगस्त, 2019** को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

एतद्द्वारा, उपरिवर्णित कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार भारतीय स्टेट बैंक की बकाया राशि **रु. 1,34,69,984/- (शब्दों में- रुपए एक करोड़ चौंतीस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ चौरासी मात्र) + एवं भावी ब्याज** चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति के सभी भाग और पार्सलः **मकान संख्या बी-26, सेक्टर-105,नोएडा**

दिनांक : 27-08-2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्यक्रम रोका

टैंट, टाट, कुर्सी और मंच पर वक्ता आ चुके थे। कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई थी। दिल्ली भाजपा के एक बड़े नेता का बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम की चमक उस समय खत्म हो गई जब उस कार्यक्रम को आखिरी समय में स्थगित किया गया। कहा गया कि ऐसा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन के शोक में किया गया। शोर तो जेटली के नाम कर दिया गया पर वजह थी कि पार्टी के कुछ नेता इसे पसंद नहीं कर रहे थे। इस नेता की फितरत रही है कि वे जब से राजनीति में हैं तब से अपने को हरदम सक्रिय रखे हुए हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए या दिल्ली भाजपा अध्यक्ष रहते हुए तो वे सक्रिय रहे ही जब कुछ भी नहीं रहे तब भी सक्रिय रहे। जब वे प्रदेश अध्यक्ष थे तो पार्टी ने उनके बजाए दूसरे नेता की अगुआई में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना तय किया, तब वे भी उन्होंने अपनी सक्रियता बनाए रखी। उन्हें लोकसभा के उन सीटों से चुनाव लड़ाए गए जिसे पार्टी सबसे कठिन मानती थी लेकिन संयोग से वे विजयी होते गए। अब उनके लिए चुनौती इसलिए बड़ी है कि एक तो उम्र बढ़ने लगी और पार्टी में गुटबाजी भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगी है। अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब कम समय रह गया है। लंबे समय से दिल्ली की सरकार से बाहर हो गई भाजपा के लिए चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है। इसके लिए वैसे नेता को आगे करना पड़ेगा जो हर विधा में महारत हासिल करने की क्षमता रखता हो।

अध्यक्ष जी की तलाश

कोई कहता है मुफ्त में पानी, बिजली और सफर देंगे। तो कोई कह रहा 4.5 चार साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। 'आप' और भाजपा ने आरोप-प्रत्यारोप के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और एक इधर कांग्रेस है कि प्रदेश अध्यक्ष तय की तलाश खत्म नहीं कर पा रही है। कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, ये तय नहीं कर पा रही है। लोग अजय माकन को इस पद के लिए प्रमुख दावेदारों में मानते हैं लेकिन वे इसका खंडन करते हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माकन ने गुरुवार को भव्य संवाददाता सम्मेलन बुलाया था जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के बिजली पर किए गए दावे को फर्जी करार दिया था। माकन चार साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और अपनी बीमारी के नाम पर बिना वैकल्पिक नाम तय हुए अपनी कुर्सी छोड़ दी। तब उनका यह भी कहना था कि वे नहीं चाहते कि जिस आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ कर कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया, उससे लोकसभा सीटों के लिए कोई गठबंधन किया जाए। चार महीने बाद उनकी जगह पर प्रदेश अध्यक्ष बनीं शीला दीक्षित ने जब गठबंधन के बजाए अपने बूते चुनाव लड़ने की घोषणा की तो माकन और प्रदेश के प्रभारी पीसी चाको गठबंधन करवाने में लग गए। इस चक्कर में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा आखरी समय में हुई। बावजूद इसके कांग्रेस भले चुनाव में कोई सीट न जीत पाई, 'आप' को तीसरे नंबर पर पहुंचाने में कामयाबी पाई। अब शीला दीक्षित के निधन के बाद फिर से प्रदेश अध्यक्ष की तलाश चल रही है।

हम में है दम

चुनाव से ठीक पहले विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर मास्टरकार्ड खेला गया है। इस राजनीतिक कार्ड से भाजपा में राजनीतिक बवाल और तेज हो गया है। इस वजह से भाजपा के तीनों ही शख्स एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि पार्टी भी इस बवाल को शांति से देख रही है क्योंकि पार्टी एक बार फिर से मोदी चेहरा-'कमल निशान' पर ही चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी में है। यह घमासान एक बार फिर दिल्ली भाजपा के नए समीकरण को बिगाड़ता नजर आ रहा है। हालांकि तीनों ही गुट अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता के साथ ये बता रहे हैं कि हम में है दम।

बगावत का चेहरा

आम आदमी पार्टी (आप) के बागी चेहरों की बगावत अब सोशल मीडिया पर भी साफ नजर आ रही है। इसको लेकर बड़े ही सधे अंदाज में 'आप' नेता अलका लाम्बा ने पार्टी में चल रही गतिविधि पर तीखी टिप्पणी की है। इसका सीधा इशारा बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इस संदेश में उन्होंने एक चुटकुले से पार्टी की चुटकी ली है। इसमें बताया गया है कि चांदनी चौक आज कल तो यह बोलती हैं। भाजपा : पूर्व निगम पार्षद के पति गुप्ता जी, कांग्रेस : पूर्व सांसद के पुत्र अग्रवाल जी और आप : पूर्व लोकसभा गुप्ता जी (जिनकी जमानत जब्त हुई)। इसमें उन्होंने एक संदेश जोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनका इशारा उनके टिकट काटने के लिए चल रही सक्रियता की तरफ था।

चाको चले केरल

दिल्ली को लेकर कहते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों से जो यहां एक बार आ जाता है, वह आसानी से नहीं लौटना चाहता। चाहे वह सियासत में हो, व्यापार में हो या किसी अन्य पेशे में। कांग्रेसी सूबेदारों का आलम तो यह है कि ज्यादातर के एक पांव दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको दिल्ली से वापस अपने गृह प्रदेश जाना चाहते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि दिवंगत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित से आखिरी दिनों में हुए विवाद की वजह से कांग्रेस हाईकमान चाको को हटाना चाहता है। लिहाजा, उन्होंने खुद ही पद छोड़ने का प्रस्ताव दे दिया है लेकिन हकीकत यह है कि चाको ने दिल्ली के प्रभारी के तौर पर करीब साढ़े चार साल के अपने कार्यकाल में इस बात को पूरी शिद्दत से महसूस कर लिया है कि दिल्ली में कांग्रेस की वापसी आसान नहीं है जबकि केरल में पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। आने वाले दिनों में वहां विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे आसार हैं कि कांग्रेस वहां पर अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। माना जा रहा है कि सियासत के दाव पेंच समझने में माहिर चाको ने स्थिति को भांपकर ही कांग्रेस हाईकमान से दिल्ली की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करने का आग्रह किया है। यही वजह है कि चाको दिल्ली छोड़कर केरल जाना चाहते हैं।

एक जैसा जवाब

दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए फेसबुक और ट्विटर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। साथ ही लोगों से अपील की जाती है कि वह अपने आसपास की परेशानियों को इन सोशल साइट पर साझा करें, ताकि उनका उचित और समय पर समाधान किया जाए। कई बार पोस्ट करने के बाद यातायात पुलिस समस्या के समाधान को लेकर पहल करती है और कुछ समय बाद समस्या का समाधान भी हो जाता है। पर पिछले कुछ दिनों से देखने में मिल रहा है कि लोगों की समस्या को लेकर इन दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक ही तरह का जवाब दिया जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर का निगरानी करने वाले अधिकारी की ओर से जवाब दिया जाता है कि आप से जुड़ी समस्या या फिर परेशानी के बारे में क्षेत्र के संबंधित अधिकारी को अवगत करा दिया गया है, जल्दी ही संबंधित अधिकारी संपर्क करेंगे। पर कई दिन बीत जाने के बाद क्षेत्र के संबंधित अधिकारी संपर्क नहीं करते और बाद में अपनी परेशानी को पोस्ट करने वाला शख्स भी थक कर हार मान लेता है और चुप बैठ जाता है।

ऑनलाइन ठगी

दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी को ही ठगों ने ऑनलाइन चूना लगा दिया। अधिकारी तब चौंके-जब पता चला कि उनका क्रेडिट कार्ड तो जेब में है और खाते से हजारों गायब हो गए। यह अलग बात है कि चोरों यह नहीं पता होगा कि जिसके क्रेडिट कार्ड का माल वो उड़ा रहे हैं वो उसी मुख्यालय में बैठा है जहां से इन साइबर चोरों के काम तमाम होते है। कहना न होगा कि साइबर अपराध का मामला भी महकमें ने तुरंत दर्ज कर लिया। चर्चा है कि जल्द वे पकड़े भी जाएंगें। क्योंकि मामला जो हाईफाई है। किसी ने ठीक ही कहा- 'बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी।' कम से कम भंडाफोड़ तो होगा। कुछ और लोगों के मामले भी सुलटेंगे। देखना है इस मामले को पुलिस कितनी जल्दी सुलटाती है।

प्राधिकरण बीमार

अंतरराष्ट्रीय स्तर की विकासशील परियोजनाओं पर हर साल कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने वाला नोएडा प्राधिकरण अब इंजीनियरों को लेकर बीमार हो गया है। आलम यह है कि प्राधिकरण में अवर अभियंता के स्वीकृत 117 पदों के सापेक्ष केवल 16 की तैनाती है। यानी 101 पद अवर अभियंता के खाली हैं। प्रबंधक, परियोजना अभियंता, वरिष्ठ परियोजना अभियंता, उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक पद के इंजीनियरों के भी पद काफी खाली हैं लेकिन सबसे अहम जमीनी स्तर और परियोजनाओं के कार्यों की निगरानी रखने वाले अवर अभियंताओं की इतनी बड़ी कमी से विकासीय परियोजनाओं पर ग्रहण लग रहा है। बात केवल यहीं तक नहीं है, पूर्व में तैनात रहे काफी बड़ी संख्या में इंजीनियर विभिन्न जांचों के दायरे में हैं। कई वर्षों पहले सेवानिवृत्त हो चुके इंजीनियरों की सीबीआइ से लेकर अन्य स्तर पर जांच की जा रही है। नतीजतन जो बचे कुचे इंजीनियर वर्तमान में तैनात भी हैं, वे भी अपने आप को किसी जांच के पचड़े से बचाने के लिए बचाव की मुद्रा में रहकर बचकर काम केवल खानापूर्ति योग्य काम कर रहे है।

-बेदिल

epaper.jansatta.com

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सेना के उपप्रमुख का कार्य संभाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने रविवार को सेना के उप प्रमुख का काम संभाल लिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, वह लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू की जगह लेंगे, जो शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। जब वर्तमान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, तब लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने सेना प्रमुख के पद की दौड़ में होंगे, क्योंकि वे वरिष्ठतम कमांडर होंगे।

सेना के उप प्रमुख का पदभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने सेना की पूर्वी कमान की अगुवाई कर रहे थे, जो चीन के साथ लगती भारत की करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की देखभाल करती है। उन्होंने 37 साल की अपनी सेवा के दौरान कई कमान में अपनी सेवा दी। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद निरोधिक अभियानों में सक्रिय रहे और कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं।

पदभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने सेना की पूर्वी कमान की अगुआई कर रहे थे, जो चीन के साथ लगती भारत की करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की देखभाल करती है। उन्होंने 37 साल की अपनी सेवा के दौरान कई कमान में अपनी सेवा दी। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद निरोधिक अभियानों में सक्रिय रहे।

वे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन और पूर्वी मोर्चे पर इंफ्रैंटी ब्रिगेड की कमान भी संभाल चुके हैं। वे श्रीलंका में शांति मिशन दल का भी हिस्सा रह चुके हैं और वे म्यांमा में भारतीय दूतावास में तीन साल तक भारत के रक्षा अताशे रहे हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें जून, 1980 में सिख लाइट इंफ्रैंट्री रेजीमेंट की सातवीं बटालियन में कमीशन मिला था।

सेना प्रवक्ता ने कहा, 'उनके पास सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है।' उन्हें जम्मू-कश्मीर में अपनी बटालियन की कमान प्रभावी तरीके से संभालने को लेकर सेना पदक मिल चुका है। उन्हें नगालैंड में असम राइफल्स (उत्तरी) के महानिरीक्षक के तौर पर उल्लेखनीय सेवा को लेकर विशिष्ट सेवा पदक तथा प्रतिष्ठित स्ट्राइक कोर की कमान संभालने को लेकर अतिविशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है।

'एनआरसी सूची में शामिल नहीं किए लोगों को तुरंत आदेश की प्रति मिले'

गुवाहाटी, 1 सितंबर (भाषा)।

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन 'सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस' (सीजेपी) ने रविवार को कहा कि जिन्हें एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें इस फेहरिस्त से बाहर रखने संबंधी आदेश की प्रति तुरंत दी जाए ताकि वे निर्धारित समय में अधिकरणों में अपील दायर कर सकें।

एनजीओ ने कहा कि यह अपील किस तरह से की जाएंगी और उसका स्वरूप क्या होगा, इसकी अभी जानकारी नहीं है। सीजेपी सचिव सीतलवाड ने एक बयान में कहा कि एनआरसी सूची में शामिल नहीं होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूची से बाहर करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति और उनके द्वारा एनआरसी अधिकारियों को प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अधिकारी जल्द से जल्द दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे और स्पष्ट करेंगे कि 120 दिनों की मियाद ये दस्तावेज मिलने के बाद शुरू होगी।

सीआइसी ने सीबीआइ से पूछा

माल्या के प्रत्यर्पण के खर्च से उसका अभियोजन कैसे बाधित होगा

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को निर्देश देकर कहा कि वह यह बताए कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर आने वाले खर्च की जानकारी देने से कैसे उसकी लंबित हिरासत और अभियोजन बाधित होगा। सीबीआइ ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत माल्या के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण पर आने वाले कानूनी और अन्य खर्चों की जानकारी देने से इनकार कर दिया था।

आरटीआइ के तहत जांच एजंसी ने प्रत्यर्पण पर आने वाले कानूनी और अन्य खर्चों की जानकारी देने से इनकार कर दिया था

माल्या 2015 में अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की धाराओं को हल्का किए जाने के बाद 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। माल्या ने ब्रिटेन से अपने प्रत्यर्पण को वहां की अदालत में चुनौती दे रखी है। अपने आरटीआइ आवेदन के तहत पुणे स्थित कार्यकार्ता विहार धुर्वे ने सीबीआइ से छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिनमें कुल कानून खर्च और परामर्श शुल्क, कुल यात्रा खर्च, माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सरकार द्वारा जिन वकीलों को फीस अदा की गई उनका नाम शामिल था। एजंसी ने आरटीआइ अधिनियम की धारा 24 और धारा 8(1)एच के तहत मिली छूट का हवाला देते हुए जवाब देने से बचने की कोशिश की। धारा 24 के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल सुरक्षा और खुफिया संगठनों को आरटीआई अधिनियम के तहत छूट दी गई है। हालांकि इस धारा के प्रावधान कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामलों में खुलासे पर फैसला आरटीआइ अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।

समुद्री अध्ययन में विकसित देशों की कतार में शामिल होगा भारत

कोलकाता, 1 सितंबर (भाषा)।

गहरे पानी में जाने वाले वाहन (सबमर्सिबल वीकल) के माध्यम से गहरे समुद्र में व्यक्तियों को भेजने की भारत की महत्वाकांक्षा 2021-22 तक 'समुद्रयान' परियोजना के साथ ही हकीकत में बदल जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान (एनआइओटी) के निदेशक एमए आत्मानंद ने बताया कि इस परियोजना में गहरे पानी का अध्ययन करने के लिए तीन व्यक्तियों को सबमर्सिबल वीकल के माध्यम से करीब 6000 मीटर की गहराई पर भेजने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि स्वदेश में विकसित यह वाहन छह किलोमीटर की गहराई में समुद्र तल पर 72 घंटे तक चल सकता है।

उन्होंने गहरे समुद्र खनन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'अंतरिक्ष मिशन पर व्यक्तियों को ले जाने की इसरो की योजना की भांति ही एनआइओटी समुद्रयान परियोजना पर काम कर रहा है। 200 करोड़ रुपए की इस परियोजना में विभिन्न अध्ययनों के लिए तीन व्यक्तियों को सबमर्सिबल वीकल के माध्यम से समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजने का प्रस्ताव है।' एनआइओटी की समुद्रयान परियोजना इसरो की 2022 तक अंतरिक्ष में अंतरिक्षयात्री को भेजने के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तर्ज पर ही है।

200 करोड़ की 'समुद्रयान' परियोजना में 2022 तक खनन शुरू होगा

आत्मानंद ने बताया कि 'समुद्रयान' की सफलता से भारत को समुद्रों से खनिजों के उत्खनन में विकसित देशों की लीग में शामिल होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकसित देश पहले ही ऐसे मिशन चला चुके हैं और भारत विकासशील देशों में पहला ऐसा देश हो सकता है। 'समुद्रयान' दुर्लभ खनिजों के वास्ते गहरे समुद्री खनन के लिए भू विज्ञान मंत्रालय की पायलट परियोजना का हिस्सा है। आत्मानंद ने कहा, 'हम अधिक परीक्षण के साथ विभिन्न चरणों में गहराई पर उतरते जाएंगे और 2022 तक खनन के शुरू हो जाने की संभावना है।'

कपिल मिश्रा का कोर्ट में दावा

दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार उजागर किया इसलिए ठहराया गया अयोग्य

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

आप के दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शहर की सरकार के पदाधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया। हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाले मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

उन्होंने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि वह 27 जनवरी को विजय गोयल के आवास पर गए थे और वहां भाजपा सांसद मनोज तिवारी से भी उनकी मुलाकात हुई थी लेकिन किसी कानून के तहत इसे आम आदमी पार्टी (आप) से स्वैच्छिक इस्तीफे के तुल्य नहीं माना जा सकता है। करावल नगर से विधायक रहे मिश्रा को 27 जनवरी से अयोग्य ठहराया गया था जब उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा आयोजित चुनावी कार्यक्रम में मंच साझा किया था। मिश्रा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरावील जैसे पार्टी के अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विरोधी राजनीतिक दलों के साथ मंच साझा किया है और ऐसे में सदस्यों के लिए अलग-अलग पैमाने नहीं हो सकते हैं। इस मामले में चार सितंबर को सुनवाई होनी है।

सुप्रीम कोर्ट में सामुदायिक रसोई के लिए याचिका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे भूख और कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई योजना तैयार करें। यह याचिका न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूख और कुपोषण की वजह से पांच साल से कम उम्र के कई बच्चे मर जाते हैं और यह स्थिति भोजन के अधिकार और नागरिकों के जीवन के अधिकार समेत विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

सामाजिक कार्यकर्ता अनून धवन, ईशान सिंह और कुंजन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में भूख से होने वाली मौतों को कम करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) को एक योजना तैयार करने का आदेश देने की मांग की गई है।

याचिका में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओड़ीशा, झारखंड और दिल्ली में सरकार के वित्तपोषण से चलाई जा रही सामुदायिक रसोई का उल्लेख किया गया है। इसमें लोगों को स्वास्थ्यकर स्थिति में रियायती दरों पर खाना दिया जाता है। यह याचिका वकील आशिमा मांडला और फुजैल अहमद अयूबी के जरिए दाखिल की गई है।

पॉल मर्चेन्ट्स लि. (आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित कं.) (CIN: L74900DL1984PLC018679)
कॉर्पो. कार्या.: एससीओ 829-830, सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022
फोन: 0172-5041760, फैक्स: 0172-5041304, ई-मेल: info@paulmerchants.net, वेबसाइट: www.paulmerchants.net
पंजीकृत कार्या.: दीपालय 335, 336, 337, 3री मंजि., दीपालय हाउस, 15, दिनदयाल मार्ग, मजफ्फर रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-48702000

35वीं वार्षिक सामान्य बैठक, इ-वोटिंग तथा किताब बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम सूचना के निर्दिष्ट अनुसार व्यापार को चलाने के लिए पै. पॉल मर्चेन्ट्स लि. के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) फॉरएवर बैंक्वेट, 20, पश्चिम विहार एक्स., मेट्रो पिलर नं. 193, पिर. ओर्डिनेन्स डिपो, नई दिल्ली-110063 में सोमवार, 30 सितंबर, 2019 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी ने अनुमत विधि द्वारा 30.08.2019 को एजीएम सूचना भेजने का कार्य पूर्ण कर लिया है।

कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 तथा समय समय पर संशोधित, के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आवश्यकताओं के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों की अनुपालना में सदस्यों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा 35वीं एजीएम पर वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और व्यापार सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त की गई इ-वोटिंग सुविधा ("रिमोट इ-वोटिंग") के माध्यम से संपादित किया जा सकता है।

इ-वोटिंग के लिए निर्देश एजीएम सूचना में दिए गए हैं। सदस्यों से निम्नलिखित नोट करने का अनुरोध है:

क. रिमोट इ-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे (आइएसटी) शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2019 को सायं 5.00 (आइएसटी) बंद होगी। रिमोट इ-वोटिंग की कथित तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा अवरोध कर दिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट इ-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. सदस्यों को वोटिंग अधिकार (डाकीय मतपत्र के माध्यम से एजीएम में या रिमोट इ-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग) सोमवार, 23 सितंबर, 2019 ("कट-ऑफ तिथि") को कंपनी की भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में कर सकेंगे। कट-ऑफ तिथि (कार्यालय समय के समापन) को सदस्य को केवल रिमोट इ-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के हकदारी में शामिल किया जाएगा और वह एजीएम में उपस्थित हो सकता है।

ग. कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयरधारक है वह कंपनी पै. लिमिटेड आइडेन्टिफ़ाइ लि., 1-ई/13, झंडेवालान, एक्स., नई दिल्ली-110055 (इंडिया) फोन नं. 011-42541959 के आरटीए या सीडीएसएल को अनुरोध भेजने द्वारा लॉग इन आइडी व अनुक्रम सं. प्राप्त कर सकते है। तथापि, यदि कथित शेयरधारक इ-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं तब वह वोट डालने के लिए वर्तमान यूजर आइडी व पासवर्ड प्रयोग कर सकता है। यदि वह पासवर्ड भूल गया है, वह www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" के प्रयोग द्वारा पासवर्ड रिसेट कर सकता है।

घ. जिन सदस्यों ने रिमोट इ-वोटिंग सुविधा का प्रयोग नहीं किया है उसे एजीएम के स्थान पर डाकीय मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट इ-वोटिंग द्वारा अपने वोट का पहले प्रयोग नहीं किया है वह डाकीय मतपत्र के माध्यम से एजीएम के स्थान पर अपनी सहमति या असहमति पर वोट के अधिकार का प्रयोग करने के सक्षम होंगे।

ङ. सदस्य एजीएम में केवल एक विधि में वोटिंग अर्थात रिमोट इ-वोटिंग या डाकीय फार्म के द्वारा प्रयोग कर सकता है। यदि सदस्य दोनों विधियों में वोट डालता है तो रिमोट इ-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट को प्राथमिकता दी जाएगी और डाकीय फार्म को अवैध माना जाएगा।

च. सदस्य रिमोट इ-वोटिंग के माध्यम से वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकता है परंतु एजीएम में दोबारा वोट के प्रयोग के लिए सक्षम नहीं किया जाएगा।

35वीं एजीएम, उपस्थिति पर्ची और प्रोक्सी फार्म से युक्त वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को प्रदर्शित किया गया है और वैबसाइट http://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2019/08/Annual-Report-2018-19.pdf. के अलावा कंपनी की वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 35वीं एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची और प्रोक्सी फार्म सीडीएसएल वैबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कंपनी के निदेशकों के बोर्ड ने विस्तृत तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट इ-वोटिंग और डाकीय मतपत्र प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए छाटनीकार के तौर पर श्री कंवलजीत सिंह खनेजा, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस नं. 5901 तथा सीपी नं. 5870) एससीओ 64-65, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ को नियुक्त किया है।

एजीएम में रिमोट इ-वोटिंग तथा डाकीय फार्म का परिणाम मंगलवार, 1 अक्तूबर, 2019 को अपरान्ह 2.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022 में घोषित किया जाएगा। छाटनीकार की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत परिणाम घोषित करने के बाद कंपनी की वैबसाइट (www.paulmerchants.net) और सीडीएसएल की वैबसाइट (https://www.evotingindia.com) पर डाले जाएंगे और उसके साथ सीएसई लि. जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, भेजे जाएंगे। प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में डाले गए वोट की संख्या के साथ वोटिंग का परिणाम, अवैध वोट तथा प्रस्ताव निष्पादित किए या नहीं किए गए, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय नई दिल्ली और संयुक्त कार्यालय चंडीगढ़ पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

यदि कोई सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की प्रिंट की गई प्रति चाहता है, कंपनी सदस्य से अनुरोध की प्राप्ति पर निशुल्क उसे भेजेगी। ऐसे अनुरोध cs@paulmerchants.net पर भेजे जा सकते हैं।

इ-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले की स्थिति में आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") तथा www.evotingindia.co.in पर हैल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध इ-वोटिंग मॉड्यूल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें। आप श्री हरदम सिंह, कंपनी सचिव, पॉल मर्चेन्ट्स लि., दीपालय हाउस, एससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022, पर या टेलीफोन नं. 0172-5041760, या फैक्स नं. 0172-5041613 या ईमेल investor.redressal@paulmerchants.net पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों का ध्यान सेबी सर्कुलर नंबर SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 दिनांक 20.04.2018 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को उनके आरटीए के माध्यम से भौतिक विधि में सभी शेयरधारक का पैन नंबर और बैंक खाता विवरण का रिकार्ड रखने का निर्देश दिया है। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों को कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), अलॉटमेंट्स लि., 1-ई/13, झंडेवालान, एक्स., नई दिल्ली-110055 (इंडिया) फोन नं. 011-42541959 को निम्नलिखित सूचित भेजना, यदि पहले प्रदान नहीं किए हैं, का अनुरोध है।

क. कैंसल्ड चैक द्वारा उनके बैंक खाता विवरण, इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से लाभांश की अदायगी प्राप्त करने के आशय से, जो भी भौतिक हो, ।

ख. उनके स्वयं सत्यापित पैन।

आगामी तौर पर सूचना दी जाती है कि कंपनीज एक्ट, 2013 तथा वहां इसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों 2015 के विनियम 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक कंपनी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य के लिए 24.09.2019 से 30.09.2019 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

दिनांक: 31 अगस्त, 2019
स्थान: चंडीगढ़

हस्ता./-
हरदम सिंह,
कंपनी सचिव, एफसीएस 5046

लीड फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 101, सीता राम मैंशन, 718/21, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
वेबसाईट: www.leadfinancialservices.in, ईमेल: lead_financial@rediffmail.com
फोन: 011-23549822-23, CIN No.: L74140DL1993PLC053485

सदस्यों के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) खण्डेलवाल समाज विकास ट्रस्ट, 2सी/24, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में शनिवार, 28 सितम्बर, 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 से शनिवार, 28 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।
2. एजीएम की सूचना ऐसे सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धत्ति में उनके पंजीकृत पते/ईमेल आईडी पर भेज दी गई है जिनके नाम 17 अगस्त, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर/आरटीए के अभिलेख में शामिल हैं। एजीएम की सूचना का प्रेषण 30 अगस्त, 2019 को पूरा कर लिया गया है।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2019 को भौतिक पद्धत्ति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड "सीडीएसएल" की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर इलोक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई-वोटिंग) अपना मतदान कर सकते हैं। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

i) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है;
ii) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी;
iii) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी;
iv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 21 सितम्बर, 2019 है।
v) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हैं तो सभा की सूचना तथा ई-वोटिंग की प्रक्रिया (लागिन आईडी तथा पास्वर्ड सहित) प्राप्त करने के लिये उपरोक्त ईमेल आईडी पर अथवा उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को लिखें।
vi) सदस्यगण कृपया ध्यान रखे कि; क) शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी; ख) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी; ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे, तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यो के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।
vii) कम्पनी के जिन सदस्यों को सूचना प्राप्त नहीं हुआ हो, उनसे आग्रह है कि वे उसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.lead financialservices.in से डाउनलोड करें।
viii) पूछताछ के लिये सदस्यगण उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में श्री विजय कुमार प्रबंधक, फोन 011-23549822-23, ईमेल आईडी: lead-financial@rediffmail.com से अथवा अधोलिखित पते पर रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स से सम्पर्क करें: बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, 3रा तल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेन्टर के पीछे, दादाहरसुख दास मंदिर के निकट, नई दिल्ली- 110062, टेली.: 011-29961281, 29961282, फैक्स: 011-29961284, ई मेल आईडी: beetal@beetalfinncial.com.

लीड फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
पी.सी. बिन्दल
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 31.8.2018

MSTC LIMITED
CIN: U27320WB1964GOI026211 GSTIN: 19AACCM0021E1Z4
225-सी, ए. जे. सी. बोस रोड, कोलकाता - 700020, भारत
वेबसाइट: www.mstcindia.co.in दूरभाष: 2281-9627/2008
ईमेल: cosec@mstcindia.co.in

सूचना
54वीं वार्षिक साधारण बैठक

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की चौवनवीं वार्षिक साधारण बैठक **हॉल 6 (लेवल 1 में प्रेक्षागृह), विश्व बांगला कॉन्वेंशन सेंटर**, विश्व बांगला सरणी, सॉल्ट लेक सिटी, न्यू टाउन, कोलकाता 700156 में **बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** आयोजित होगी। सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बही **बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 से बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सहित)** बंद रहेंगी।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन के साथ बैठक के आयोजन की सूचना, प्रतिभागिता प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्ची आज डाक द्वारा सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है तथा जिन सदस्यों के ईमेल का पता डिपॉजिटरी/कंपनी के पास पंजीकृत है उन्हें यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है। वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा निरीक्षण के लिए यह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक सभी कार्यकारी दिवस को कार्यालयीन घंटे के दौरान उपलब्ध रहेगी।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अपने सदस्यों को अपनाया चौवनवीं वार्षिक साधारण बैठक ('बैठक') की कार्यसूची में सम्मिलित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने की सुविधा प्रदान करेगी। सदस्यगण बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से (रिमोट ई-वोटिंग) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर अपने वोटाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा द्वारा अपने वोट नहीं डालने वाले बैठक में उपस्थित सदस्यों के लिए टीएसी आधारित वोटिंग प्रणाली अथवा बैलट अथवा पोलिंग पेपर के जरिए वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित संचार, अन्य विषय, यूजर आईडी तथा पासवर्ड के साथ बैठक आयोजन की सूचना की प्रतिलिपियां सदस्यों को भेज दी गई है। संचार तथा बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.mstcindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है। वर्ष 2018-19 के लिए लेखा तथा प्रतिवेदन भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है तथा उसकी प्रतिलिपि कंपनी की उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा **शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 को सुबह 9.00 बजे (भारत)** शुरू होगी तथा **मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 को अपरान्ह 5.00 बजे (भारत) समाप्त होगी।** ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अंतिम तारीख यानी **बुधवार, 18 सितम्बर, 2019** को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर जिनके नाम दर्ज हैं, सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोट डालने की सुविधा पाने के पात्र होंगे।

जिन व्यक्तियों ने सूचना भेजने के बाद शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी के सदस्य बने हैं तथा वे अंतिम तारीख तक शेयर धारण रखते हैं वे **evoting.nsdl.co.in** अथवा **cosec@mstcindia.co.in** पर अनुरोध भेज कर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वे अपने वोट डालने के लिए वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वे अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो **https://www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध विकल्प **"Forget User Details/Password?"** अथवा **"Physical User Reset Password?"** का प्रयोग कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।

यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध बैठक की सूचना से भी प्राप्त की जा सकती है।

रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके सदस्यगण बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे बैठक में दोबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोटिंग से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न/शिकायत रहने पर कृपया **https://www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा श्री असित विश्वास, वरिष्ठ प्रबंधक/सुश्री पल्लवी पालवे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, कमला मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से दूरभाष नं. 022-24994360/022-24994545 पर सम्पर्क करें तथा **evoting@nsdl.co.in** पर ईमेल भेजें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबं

जनसत्ता

2 सितंबर, 2019

कालेधन का सच

आखिरकार स्विस बैंक में जमा भारतीय नागरिकों के कालेधन की जानकारी साझा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेशी बैंकों में खाता खोल कर गैरकानूनी तरीके से धन जमा कराने वालों के नामों का पता लगाने और वह धन वापस भारत लाने की मांग उठती रही है। इसे लेकर बाबा रामदेव ने व्यापक आंदोलन भी चलाया था। भाजपा ने भी पिछले लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने का मुद्दा उठाया था। मगर अभी तक इस दिशा में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब स्विट्जरलैंड और भारत के बीच हुए समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच बैंक सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया इस महीने से शुरू हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इसे अहम कामयाबी बताया है। हालांकि स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के खातों की जानकारी हासिल करने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था, पर इस बैंक के नियमों के मुताबिक इसके खाताधारकों के बारे में जानकारी साझा नहीं की जा सकती। यहां तक कि वहां की सरकार भी उस पर ऐसा करने का दबाव नहीं डाल सकती थी। पर स्विट्जरलैंड सरकार ने कालेधन के मुद्दे को गंभीर मानते हुए नियमों में बदलाव कर बैंक सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया का रास्ता खोल दिया।

दरअसल, स्विट्जरलैंड सहित कई देशों के बैंकों में खाता खोलना बहुत आसान है। किसी भी देश का कोई भी नागरिक आनलाइन अपना खाता खोल सकता है। ये बैंक अपने ग्राहकों के नाम-पते वगैरह को गोपनीय रखते हैं। वहां की सरकारों ने ही इन बैंकों को यह स्वायत्तता दी है। इसलिए दुनिया के तमाम देशों के ऐसे लोगों के लिए ये बैंक अपना कालाधान छिपाने के सबसे मुफीद ठिकाने बनते गए। इन बैंकों का कारोबार भी इसी तरह के धन से चलता है। भारत के भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं और कारोबारियों आदि के लिए भी ये बैंक एक प्रकार से सुरक्षित तिजोरी साबित होते रहे हैं। यह छिपी बात नहीं है कि भारत अन्य मामलों में भले निचले पायदान पर रहता आया हो, पर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ अव्वल देशों में शुमार है। रिश्वत और कर चोरी करके जमा काले धन को लोग स्विस बैंक जैसे विदेशी बैंकों में जमा कराते रहे हैं। स्विस बैंक में जमा कुल धन का 0.07 फीसद पैसा अकेले भारतीय नागरिकों का है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे विदेशी बैंकों में कितना भारतीय काला धन जमा होगा।

हालांकि स्विस बैंक इससे पहले भी सौ भारतीय नागरिकों की पहचान साझा कर चुका है, जिनके स्विस बैंक में खाते हैं। अब इस बैंक के सभी भारतीय खाता धारकों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जिन लोगों ने पिछले साल अपने बैंक खाते बंद करा दिए, उनके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। लंबे समय से इस पर परदा पड़ा हुआ था, अब वह उठ जाएगा। मगर अभी सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि स्विस बैंक में जमा काले धन को वापस कैसे लाया जाए। स्विट्जरलैंड सरकार बैंकों पर शायद ही दबाव बनाए कि वे भारतीय नागरिकों के पैसे भारत सरकार को सौंप दें। फिर भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्विस बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आधार तो बनेगा। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगाने को प्रतिबद्ध है, इसलिए कर चोरी और रिश्वत आदि से जमा धन विदेश भेजने वालों पर कड़े कदम उठाने की उम्मीद स्वाभाविक है।

नागरिकता पर सवाल

असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की आखिरी सूची भले जारी हो गई हो, लेकिन नागरिकता संबंधी विवादों का मूल वहीं का वहीं है। अब भी लाखों लोगों के सामने यह सवाल है कि वे भारत के नागरिक हैं या नहीं। इसलिए बुनियादी सवाल यही बना हुआ है कि इस अंतिम सूची में जो उन्नीस लाख लोग अब छूट गए हैं, क्या वे विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं या भारतीय नागरिक नहीं हैं? जब तक वे विदेशी पंचाट के समक्ष अपने भारतीय नागरिक होने के दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर देते तब तक उनकी स्थिति क्या होगी? पिछले साल जुलाई में जब एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी हुआ था तो उसमें से चालीस लाख से ज्यादा लोगों के नाम गायब थे। यानी साल भर में करीब बीस लाख और लोगों को एनआरसी में शामिल कर उन पर से विदेशी होने का कलंक मिटाया गया। दरअसल, जिस तरह से एनआरसी बनाने और उसे अद्यतन करने का काम हुआ है उसमें व्यावहारिक तौर पर यह संभव ही नहीं है कि सही मायने में किसी घुसपैठिए की पहचान की जा सके। इसीलिए अंतिम सूची के जारी होते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई। आसू से लेकर सारे दल और कई संगठनों ने इसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

असम के लिए यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। यह राज्य भारत की आजादी के बाद से ही घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा है। इसीलिए 1951 में पहली बार राज्य में एनआरसी की शुरुआत की गई थी, ताकि बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) से आने वाले घुसपैठियों का पता लगा कर वापस उनके देश के हवाले किया जा सके। हालात तब बिगड़े जब बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए सातवें दशक के आखिर में असम में हिंसक आंदोलन शुरू हुआ और असम समझौते के बाद बंद हुआ। तभी यह तय हुआ था कि 1971 के बाद असम में आने वाले को बाहरी, विदेशी माना जाएगा। लेकिन एनआरसी की लंबी-चौड़ी कवायद बता रही है कि ऐसी सूचियों से यह फैसला हो पाना मुमकिन नहीं है कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं। हालांकि सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन उन्नीस लाख लोगों के नाम इस सूची में नहीं हैं वे विदेशी नहीं माने जाएंगे, उन्हें एक सौ बीस दिन के भीतर विदेशी पंचाट के समक्ष पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

एनआरसी पर जैसी त्रुटियां आई हैं, उससे साफ है कि इसे बनाने में भारी लापरवाही तो हुई ही है, साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी इसे प्रभावित करने की कोशिशें होती रही हैं। एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के नाम सूची में हैं तो कुछ के नहीं। इनमें ज्यादातर लोग तो वे हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और वंचित तबके से हैं और इन्हें नागरिकता के दस्तावेजों की जानकारी तक नहीं है। इन्हें ही हिरासत केंद्रों में रखा गया है। इसलिए ऐसे लोगों में खौफ पैदा होना स्वाभाविक है। सवाल है कि अगर घुसपैठियों का पता लग भी जाता है तो उन्हें कैसे उनके देश भेजा जाएगा। ऐसे में एनआरसी जैसी कवायद पर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे!

कल्पमेधा

जो शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है, वह अपने शत्रु पर अपूर्ण विजय ही प्राप्त कर पाता है।

-मिल्टन

श्रम सुधारों की दशा और दिशा

जयंतीलाल भंडारी

अब श्रम कानूनों में लचीलापन लाने और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए श्रम नियमों को सरलतापूर्वक लागू करना होगा, नए कानूनों की भरमार कम करनी होगी, ऐसी नीतियां और कार्यक्रम लागू करने होंगे जिनसे उत्पादन बढ़े और उपयुक्त सुरक्षा ढांचे के साथ श्रमिकों का भी भला हो।

सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर पचास करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह विधेयक सरकार को श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने में मदद करेगा। साथ ही, इससे कर्मचारियों को वेतन भुगतान में मदद मिलेगी। वेतन संहिता में चार श्रम कानूनों, न्यूनतम वेतन कानून, वेतन भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून और समान भत्ता कानून को समाहित किया है। सरकार ने न्यूनतम वेतन का विस्तार देश के पूरे श्रमबल तक किया है और नियोक्ताओं को ठेके पर श्रमिक रखने के लिए कई कई के लाइसेंस लेने की जरूरत भी खत्म कर दी है। इस समय राज्यों को न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार है और देश में दो हजार से ज्यादा तरीके के वेतन-स्तर हैं, इसलिए नए कानून से देशभर में न्यूनतम वेतन का नया तरीका लाभकारी होगा।

नए कानून में यह भी प्रावधान है कि नौकरी छोड़ने या नौकरी से हटाए जाने या कंपनी के बंद होने की स्थिति में कंपनी को दो दिन के अंदर बकाया वेतन का भुगतान करना होगा। नए कानून में एक सौ अठहत्तर रुपए न्यूनतम दैनिक वेतन सुनिश्चित किया गया है। जिन राज्यों में इससे ज्यादा की व्यवस्था है, वहां श्रमिकों को ज्यादा वेतन देने की व्यवस्था जारी रहेगी। इस प्रावधान से मजदूरों का शोषण रुकेगा, क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में दैनिक मजदूरी पचास, साठ और सौ रुपए पर ही अटकी पड़ी है।

इन दिनों न सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों और अगले पांच वर्षों में उसे पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने के मद्देनजर भारत की नई श्रम संहिता पर टिकी हैं। इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार चवालीस श्रम कानूनों को मिला कर चार श्रम संहिताएं बनाएगी। ये संहिताएं न्यूनतम वेतन और कार्यगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों पर केंद्रित होंगी।

श्रम और औद्योगिक कानूनों की संख्या के मामले में हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। देश में ढेरों श्रम कानून लागू हैं। केंद्र सरकार के पास श्रम से संबंधित चवालीस और राज्य सरकारों के पास सौ से अधिक कानून हैं। देश में कारोबार के रास्ते में कई कानून ऐसे भी लागू हैं जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डेढ़-दो सौ साल पहले बनाए गए थे। कई वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि श्रम कानून भी उत्पादकता वृद्धि में बाधक बने हुए हैं। उच्चतम न्यायालय भी कई बार अप्रासंगिक हो चुके ऐसे कानूनों की कमियां गिनाता रहा है जो काम को कठिन और लंबी अवधि का बनाते हैं। दुनिया के आर्थिक और श्रम संगठन बार-बार यह कहते रहे हैं कि श्रम सुधारों से ही नए भारत का निर्माण हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए श्रम सुधार करना काफी जरूरी है। देश के श्रम कानून लंबे समय से लाइसेंस राज की विरासत को ढो रहे हैं। वस्तुतः जो श्रम सुधार नए दौर में आर्थिक व औद्योगिक विकास की मांग है, उसके लिए देश की नई चार श्रम संहिताओं से नई राह बनी है। ऐसे सुधारों से आर्थिक विकास और रोजगार के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। निसंदेह श्रमिक हितों का संरक्षण जितना महत्त्वपूर्ण है, उससे ज्यादा जरूरी निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। भारत में विदेशी निवेश और कारोबार संबंधी अनुकूल ठोस कदमों की कमी बनी हुई है। विश्व व्यापार के संदर्भ में आई इकॉनोमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट (ईआइयू) की रिपोर्ट में विकासशील और विकसित देशों में व्यापार करने या उद्योग लगाने के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल माहौल की चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को छियालीसवां स्थान दिया गया है। जबकि चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको और थाईलैंड की रैंकिंग भारत से काफी ऊपर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी और जटिल है और श्रम सुधारों की गति मंद है।

अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती के कारण भारत में भी पिछले एक साल से आर्थिक सुस्ती का जो दौर चल रहा है, उसमें श्रम सुधारों से तेजी लाई जा सकती है और इसका देश की

अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। स्थिति यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने वर्ष 2019-20 के लिए विकास दर का अनुमान घटा कर 6.9 फीसद कर दिया है। रेंटिग एजंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान 7.2 फीसद से घटा कर सात फीसद कर दिया है। अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि श्रम सुधारों से निर्यात को गति दी जा सकती है। भारत के मुकाबले कई छोटे-छोटे देश मसलन बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों ने अपने यहां निर्यातकों को एक ओर श्रम सुधारों का उपहार दिया, तो दूसरी ओर ढेरों सुविधाएं भी हैं। इससे इन देशों ने भारतीय निर्यातकों के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। छोटे-छोटे देश श्रम सुधार करके तेजी से निर्यात बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार का नया श्रम सुधार अभियान निर्यात वृद्धि में सहायक साबित होगा।

अब श्रम कानूनों में लचीलापन लाने और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए श्रम नियमों को सरलतापूर्वक लागू करना होगा, नए कानूनों की भरमार कम करनी होगी और ऐसी नीतियां और कार्यक्रम लागू करने होंगे जिनसे उत्पादन बढ़े और उपयुक्त सुरक्षा ढांचे के साथ श्रमिकों का भी भला हो। श्रम कानूनों में नए बदलाव का मतलब श्रमिकों का संरक्षण समाप्त करना नहीं है, वरन इससे उद्योग-कारोबार में तेजी आएगी और उद्योगों में नए श्रम अवसर निर्मित होंगे। उद्योग जगत को भी यह समझना होगा कि वह श्रमिकों को खुश रख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। सरकार को अधिकतम प्रयास करना होगा कि श्रम संगठन और उद्योग संगठन श्रम और पूंजी के हितों में तालमेल बनाने के लिए खुले मन से संवाद करें। ऐसा होने पर ही सरकार श्रम एवं पूंजी के बीच संतुलन बनाने की कठिन चुनौती का समाधान निकल सकेगा।

इस समय जब देश श्रम सुधारों के रास्ते पर बढ़ रहा है, तब औद्योगिक एवं श्रम संगठनों के विचार मंथन को ध्यान में रखा जाना होगा। यह संतोषप्रद है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाली कमेटी में मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना सुनिश्चित किया है। देश के प्रमुख श्रम संगठनों ने जहां वेतन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता को लाभप्रद बताया है, वहीं इन संगठनों ने औद्योगिक संबंधों से जुड़ी संहिता पर आपत्ति भी है। कहा गया है कि श्रम संगठनों के पदाधिकारियों के लिए पात्रता सरकार द्वारा तय किए जाने, हड़ताल करने का अधिकार सीमित करने, कर्मचारियों को एकतरफा तौर पर निकालने और एप्रेंटिस श्रमिकों को अलग करने जैसे प्रावधानों से श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में श्रमिकों की संतुष्टि के मद्देनजर सरकार को सभी संहिताओं में यथासंभव सुधार करके ही उन्हें कानून की शक्ल देनी चाहिए।

उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में तेजी से आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए चार श्रम संहिताएं देश के श्रम क्षेत्र को नया रूप देंगी। इससे देश उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, रोजगार वृद्धि और विकास दर के ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ेगा और भारत वैश्विक उद्योग-कारोबार के क्षितिज पर भी अपनी नई पहचान बनाने में कामयाब हो सकेगा।

ऐसी बानी बोलिए

घनश्याम कुमार देवांश

दुनिया मेरे आगे

भक्त कवि कबीर ने एक दोहे में लिखा था-'ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय/ औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय'। इसका अर्थ यह है कि हमें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो हमें भी अच्छी लगे और दूसरों को भी। लेकिन आज हम अपने आसपास जितने भी लोगों से मिलते-जुलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसमें क्या हमें इस दोहे के करीब का भी आशय महसूस होता है? सच यह है कि आजकल हम अपने चारों तरफ जो इतनी अशांति, उत्तेजना, तनाव और मारपीट देखते हैं, उसके पीछे प्रमुख कारण है लोगों में धैर्य का न होना। यह अधैर्य सबसे ज्यादा उनकी जुबान में साफ झलकता है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि मामूली-सी बात पर लोग कई बार अपना आपा खो देते हैं और गुस्सा होकर दूसरे पक्ष के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि लोग आपस में मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। अनेक बार ऐसे मामलों में लोग गंभीर चोटों के शिकार हो जाते हैं और कुछ मामलों में तो लोगों की जान तक चली गई। कुछ समय पहले मैं अपने एक सज्जन मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था। सड़क पर बहुत भीड़ थी। मित्र की गलती से मोटरसाइकिल हमसे आगे चल रही एक कार में छू गई, जो आगे चलते हुए अचानक ही धीमी हो गई थी।

इसके बाद कार में सवार व्यक्ति ने गाड़ी रोक दी, फिर गुस्से में बाहर निकला और हमारी तरफ बढ़ा। मित्र ने धीरज नहीं खोया और बेहद शालीनता से मुस्कराते हुए कहा- 'मैं माफी चाहता हूं।' कार में से गुस्से में उतर कर हमारे पास तैश में आया वह व्यक्ति मित्र के इस व्यवहार से अचानक ही एकदम शांत हो गया और वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने मित्र से पूछा कि गलती तुम्हारी तो नहीं थी, उसने गलत ढंग से ब्रेक का इस्तेमाल अचानक किया था... फिर तुमने उससे माफी क्यों मांगी? मित्र ने कहा कि वह समय लड़ने-झगड़ने का नहीं... परिस्थिति को समझदारी और ठंडे दिमाग से सुलझा लेने का था। मुझे मित्र की बात अच्छी लगी। अगर कोई और उस जगह होता और उस व्यक्ति से सही या गलत होने पर बहस करता तो अच्छा-खासा झगड़ा सड़क पर हो सकता था, शायद मारपीट भी हो सकती थी।

दरअसल, आजकल हमारी बोलचाल की भाषा इतनी सूखी हो गई है कि उसमें एक दूसरे के लिए न तो प्यार बचा है और न ही सम्मान। हम लगातार एक बिना सहानुभूति वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं और ऐसा करते हुए हमारा बर्ताव कब संवेदनहीन हो जाता है, हमें खुद भी पता नहीं लगता। इस रवैए की वजह से अब हमें एक दूसरे को समझने और एक दूसरे से जुड़ पाने में अच्छी-खासी दिक्कत होने लगी है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि एक ही जगह पर काम करने वाले लोग एक दूसरे का अभिवादन करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की तरफ मुस्कराकर देखते भी नहीं है। अगर कोई अपने सहयोगी का अभिवादन करता भी है तो उसे उचित उत्तर नहीं मिलता। आसपास बैठने और काम करने के बावजूद एक दूसरे के बीच इस तरह की दूरी कैसे पलने लगती है?

जाहिर है, लोगों के बीच मानवीय रिश्ते सूखते जा रहे हैं। हमारे भीतर सहानुभूति का पानी सूख चुका है। आज लोगों को एक दूसरे के दुख-दर्द और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। सड़क पर घायल पड़े किसी जीव-जंतु की तो बात ही क्या, किसी हादसे में जख्मी इंसान को भी छोड़ कर हम आगे निकल जाते हैं। हमारे समाज में आज जितनी गरीबी और शोषण दिखाई दे रहा है, उसे देख कर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति बेचैन हो जाए। अलग-अलग जातियां, धर्म, संप्रदाय आदि में लोग न केवल बंटे हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए बहुत नफरत भी रखते नजर आते हैं। वे एक दूसरे को लेकर हमेशा डरे रहते हैं।

इस सबसे हमारा समाज टूट कर बिखरता जा रहा है। राजनीति ने इस माहौल को और खराब कर दिया है। अलग-अलग राजनीतिक दल इस सामाजिक बिखराव का फायदा उठा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल किसी अल्पसंख्यक समुदाय का भला करने का दावा करता है तो कोई दूसरा आकर किसी अन्य धर्म के उद्धार का ठेका उठाने की घोषणा करता है। कोई दल किसी खास समुदाय का हितैषी बनता नजर आता है तो कोई अन्य समुदायों के लोगों का भला करने के नाम पर राजनीति कर रहा है। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच इंसानियत कहीं खो गई लगती है। ऐसा लगता है कि सब अपने अपने हितों को बचाने में लगे हैं। दूसरे पीड़ित वर्गों का किसी को कोई ध्यान नहीं है। इस स्वकेंद्रित जीवन की राह का मंजिल क्या होगा?

अमेजन की आग

दुनिया की प्राणवायु माने जाने वाले अमेजन के जंगल आज जल रहे हैं। दुनिया की करीब बीस फीसद कार्बन डाई आक्साइड को सोखने के कारण पर्यावरणविदों ने इन्हें पृथ्वी के फेफड़े, गुर्दे और एक 'कार्बन सिंक' की संज्ञा दी है। ये दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन हैं। यहां पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं जो भाप बन कर ऊपर जाता है और बाद में बारिश के रूप में बरस जाता है। इस कारण यहां मौसम हमेशा नम रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं से निकलती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के करीब दोगुने में ये जंगल फैला हुआ है जो पचपन लाख वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण अमेरिका के कई देशों पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और गुयाना तक फैले हुए हैं। लेकिन इनका सबसे ज्यादा साठ प्रतिशत हिस्सा ब्राजील में है। अगर ये जंगल जल गए तो कार्बन डाई ऑक्साइड को सोखने का चक्र बंद हो जाएगा। जितनी जैव विविधता अमेजन में है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है जो आज तबाह हो रही है। जब ये जंगल जल जाएंगे तो आक्सीजन की जगह हमें और अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड मिलेगी और दुनियाभर में प्रदूषण बढ़ेगा। पहले ही दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तापमान बढ़ रहा है, सूखा और बाढ़ बढ़ रहे हैं। आग से अमेजन के पारिस्थकीय तंत्र को हो रहा नुकसान पूरी दुनिया की जलवायु पर बुरा असर डाल सकता है। अमेजन की आग से निपटने के लिए जी-7 समूह ने भी ब्राजील को वित्तीय मदद देने का एलान किया। लेकिन ब्राजील ने इसके लिए मना कर दिया। इसके पहले फ्रांस, फिनलैंड और आयरलैंड ने यूरोपीय संघ से ब्राजील पर सख्ती करने को कहा। इस मुद्दे पर अमेरिका, भारत और चीन जैसे बड़े देशों की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि, भारत और चीन दोनों ही ब्राजील के साथ ब्रिक्स के सदस्य हैं। इनकी ओर से भी कुछ दबाव पड़ना चाहिए। अमेजन के जंगलों में आग सिर्फ ब्राजील की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। अगर समय रहते पूरे विश्व ने एकजुट होकर अमेजन की आग को बढ़ने से नहीं रोका तो धुआं गहराता ही जाएगा और इस काले धुएं में दुनिया के तंदरुस्त फेफड़े कमजोर और बीमार होकर काल के गाल में समा जाएंगे।

● *डा. कुलदीप बालियान, कोटा,*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बुनियादी शिक्षा का सच

भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर हर साल अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद बच्चों में पढ़ने-लिखने का कौशल क्यों नहीं आ पा रहा हैं, इस पर गंभीरता से मंथन करने की जरुरत है। अनेक संस्थाओं ने अपनी रिपोर्टों में बुनियादी शिक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और बताया है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम इसमें बहुत पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रारंभिक शिक्षा एकदम चौपट हाल में है जहां आठवीं का छात्र गुणा-भाग तक सही तरीके से नहीं कर सकता और पांचवीं का छात्र किताब नहीं पढ़ सकता। देश में लाखों ऐसे स्कूल हैं जिनके कमरों में कबाड़ भरा पड़ा है और प्रशासन की शिथिलता के कारण इनका खमियाजा बच्चों को उठाना पड़ा रहा है। कमरों की कमी के चलते बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। प्रारंभिक शिक्षा की इन्हीं कमजोरियों और शासन तंत्र की लापरवाही के कारण हम शिक्षा की दौड़ में पिछड़े हैं और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने के अभाव के कारण शिक्षा की बदहाली का रोना रो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली के लिए अध्यापकों की पठन-पाठन के काम में उदासीनता और लापरवाही भी एक बड़ा कारण रही है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के नौ साल बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल न जाकर घरों पर सफाई, पंक्चर की दुकानों, सब्जियों के ठेलों, होटलो-ढाबों, साड़ी-कालीन बिनाई, ईट भट्ठों और निर्माण कार्यों में काम कर रहे हैं। इन बच्चों के मां-बाप का कहना है कि पहले पेट भरेंगे फिर स्कूल भेजेंगे। यह है हमारी वास्तविकता जिस पर मंथन की जरूरत है।

● *बाल मुकुंद ओझा, जयपुर*

कैसे बचेंगे तालाब

हमारे देश में विभिन्न तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे- पेड़ बचाओ, स्वच्छता अभियान, जनसंख्या नियंत्रण, नदियों को बचाने का अभियान आदि। इन अभियानों के चलने से कुछ हद तक लोगों का नजरिया बदला है और इन समस्याओं को लेकर जागरूकता भी पैदा हुई है। इन अभियानों के साथ एक अभियान तालाब बचाने का भी चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में तालाब समाप्त हो रहे हैं उससे बरसात में गिरने वाले पानी को बचाने की समस्या गंभीर होती जा रही है। देश की आजादी के समय जितने तालाब थे, आज उसके आधे भी नही बचे हैं। गांव-देहात में जिस तरह से तालाबों पर अवैध कब्जे कर उनको घेरा जा रहा है, उससे बरसात के पानी को जमा करना और तालाब के आसपास के घरों को डूबने से बचाना एक चुनौती बनता जा रहा है। तालाबों को बचाने के लिए हर प्रदेश की सरकार को जिले के जिलाधिकारी और संबंधित ग्राम प्रधानों को इस बारे में सख्त निर्देश जारी कर तालाबों, नालों की जांच करा कर उन्हें कब्जा मुक्त करना चाहिए।

● *दीपक शर्मा, मवाना (मेरठ)*

जरूरी है शुद्ध हवा-पानी

राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश तो दिए फिटनेस संदेश में बताया है कि बिना शारीरिक श्रम, व्यायाम, योग और खेलकूद के हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते। यह कहावत भी है कि एक स्वस्थ शरीर में ही अच्छा मस्तिष्क होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा, पानी, अन्न, सब्जी और फल बहुत जरूरी है। इसलिए पेड़-पौधे और पानी ही सभी प्राणियों के प्राण हैं जिसे हम भूले हुए हैं। पानी बिन पेड़-पौधे नहीं, इनके बिना पानी नहीं। आज अच्छी आबोहवा के कारण ही जम्मू -कश्मीर में अनेकों वृद्ध सौ या इससे भी अधिक आयु के हैं जो बिल्कुल फिट हैं। इसलिए शुद्ध हवा, पानी और अन्न के लिए व्यापक स्तर पर पेड़-पौधों का संवर्धन, संरक्षण और जल प्रबंधन जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे।

● *वेद मामूरपुर, नरेला*

6 सितंबर
377 फैसले का एक साल

निजता के अधिकार और लैंगिक रुझान का मुद्दा

समलैंगिक यौन संबंधों के संदर्भ में यह तथ्य दिलचस्प है कि इसे अपराध की श्रेणी में रखने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ के फैसले से पहले इसी मुद्दे पर अदालत के दिसंबर 2013 फैसले में सुधार के लिए उपचारात्मक याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित थी। आधार योजना प्रकरण पर सुनवाई के दौरान अदालत में निजता के अधिकार का मुद्दा उठा। इस पर विचार के लिए अदालत ने नौ सदस्यीय संविधान पीठ गठित की थी। संविधान पीठ द्वारा अगस्त, 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे में शामिल करने की व्यवस्था के साथ ही समलैंगिकता का मुद्दा नए सिरे से अदालत में पहुंचा था।

अब बुनियादी मानवाधिकारों की मांग

दीपक रस्तोगी

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले छह सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 377 को खत्म कर दिया था। इस फैसले के बाद वयस्कों के बीच मर्जी से समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं अधिकार मान लिया गया। तब संविधान पीठ ने अपने फैसले में सर्वसम्मति से व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 377 का एक हिस्सा संविधान में प्रदत्त समता और गरिमा के साथ जीने की आजादी प्रदान करने वाले 14 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करता है।

भावी कदम

अब एक साल बाद समलैंगिक संबंधों को सामाजिक मान्यता के तहत बुनियादी मानवाधिकारों की बात उठाई जा रही है। समलैंगिक विवाह, उनके द्वारा बच्चा गोद लेने, किराए की कोख से संतान प्राप्त करने और आइवीएफ तकनीक से गर्भधारण जैसे अधिकारों को मान्यता की मांग उठ रही है। इस वर्ग की यह दलील है कि इन अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में मान्यता नहीं मिलने की वजह से संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 29 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

आज की मांग का आधार बन रहा तब का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में टिप्पणी की थी कि सामाजिक नैतिकता की वेदी पर संविधान को शहीद नहीं किया जा सकता और कानून के शासन में सिर्फ संविधान की हुकूमत को ही इजाजत दी जा सकती है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के फैसले में कहा था कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को भी संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थीं।

शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी को प्रमुख आधार बनाते हुए समलैंगिक (एलजीबीटीक्यू) समुदाय अब अपने लिए समावेशी कानून की मांग करने लगा है। यह समुदाय अपने अधिकारों को संरक्षित करने की मांग करने लगा है। एक विधिक संस्था ने समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को समायोजित करते हुए हाल में रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ऐसे कानूनों की पहचान की गई है, जो स्त्री और पुरुष ढांचे के तहत ही काम करता है और एलजीबीटीक्यू समुदाय से विभेद करता है। पहचान, हिंसा, परिवार और रोजगार के पहलुओं पर अध्ययन किया गया है।

देश में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ऐसे विवाह करने वाले सामने आने लगे हैं। शायद ऐसा करने वाले समलैंगिक जोड़ों को उम्मीद है कि देर सबेर उनके समुदाय को विवाह करने सहित कई अन्य नागरिक अधिकार मिल जाएंगे। एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्य अलग-अलग मंचों से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वयस्कों के बीच स्वेच्छा से बनाये गये समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बाद लोग अब समलैंगिक विवाह, गोद लेने और किराए की कोख का इस्तेमाल करके संतान सुख प्राप्त करने जैसे नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं।

नागरिक अधिकारों की मांग करते हुए समलैंगिक समुदाय ने पिछले साल के उस बड़े फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब अदालत ने समाज और लोगों के नजरिए में बदलाव लाने पर जोर देते हुए कहा था, 'समलैंगिकता एक जैविक तथ्य है और इस तरह के लैंगिक रुझान रखने वाले समुदाय के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।'

एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्य तुषार नैयर ने अपने वर्ग के सदस्यों के लिए समलैंगिक विवाह, बच्चा गोद लेने और किराए की कोख से संतान सुख प्राप्त करने जैसे नागरिक अधिकारों की मांग की।

शीर्ष अदालत ने 29 अक्तूबर, 2018 को यह याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने इस साल 11 जुलाई को उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी।

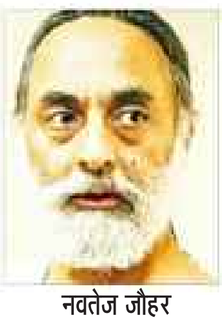

नवतेज जौहर

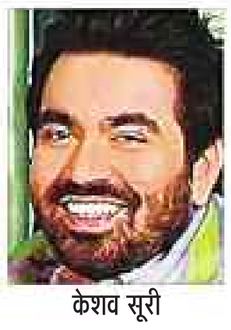

केशव सूरी

आधार योजना बनी आधार

आधार योजना से जुड़े निजता के अधिकार के सवाल पर अपने फैसले में संविधान पीठ ने कहा था कि लैंगिक रुझान निजता की एक आवश्यक विशेषता है और लैंगिक रुझान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव करना ऐसे व्यक्ति की गरिमा को गंभीर ठेस पहुंचाना है। निजता के अधिकार के बारे में संविधान पीठ की व्यवस्था के बाद नर्तक नवतेज जौहर, शेफ ऋतु डालमिया, पत्रकार सुनील मेहरा, ललित होटल के कार्यकारी निदेशक केशव सूरी और आइआइटी के 20 पूर्व तथा वर्तमान छात्रों एवं शिक्षकों ने धारा 377 की संवैधानिक वैधता को सीधे चुनौती दी। पहले के फैसले में सुधार के लिए दायर याचिका लंबित रहने के दौरान ही इन याचिकाओं को न्यायालय ने संविधान पीठ को सौंप दिया था। इसके बाद ही संविधान पीठ ने छह सितंबर, 2018 को अपने फैसले में एकांत में सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर करते हुए कहा था कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को भी संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है।

ऋतु डालमिया

सुनील मेहरा

समलैंगिक जोड़ों के सामाजिक जीवन की चिंता

धारा 377 के प्रावधान के बारे में संविधान पीठ की व्यवस्था के साथ ही इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भविष्य में समलैंगिक जीवन गुजार रहे जोड़ों की शादी, उनके लारा बच्चे गोद लेने की कवायद, ऐसे जोड़ों में उत्तराधिकारी का मुद्दा, घरेलू हिंसा और संबंध विच्छेद होने की स्थिति में गुजारा भत्ता जैसे कई अन्य मुद्दे भी उठेंगे जिनका संबंध दूसरे कानूनों से होगा। इस समय हमारे देश के दीवानी और विभिन्न धर्मों के कानूनों में समलैंगिक जोड़ों के विवाह का कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह, कानून में ऐसे जाड़ों के लिए बच्चा गोद लेने की भी व्यवस्था नहीं है।

ऐसे में एलजीबीटीक्यू समुदाय उनके नागरिक अधिकारों को बुनियादी मानव अधिकारों का हिस्सा बनाने की मांग कर रहा है, क्योंकि धारा 377 के बारे में संविधान पीठ के फैसले में इन अधिकारों पर विचार ही नहीं किया गया। यह समुदाय चाहता है कि समलैंगिक विवाह, उनके द्वारा बच्चा गोद लेने, किराए की कोख से संतान प्राप्त करने और आइवीएफ जैसे अधिकारों को मान्यता दी जाए ताकि वे भी सेना, नौसना और वायु सेना में खुलकर शामिल हो सकें और उनके यौन रुझान के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो।

इस वर्ग की यह भी दलील है कि इन अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में मान्यता नहीं मिलने की वजह से संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 29 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

समलैंगिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समावेशी कानून का तर्क

एलजीबीटीक्यू समुदाय अब अपने लिए समावेशी कानून की बात उठा रहा है। 'विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' ने इस विषय पर अध्ययन किया है।

अध्ययन का विषय है, 'क्वियरिंग द लॉ : मेकिंग इंडियन लॉज एलजीबीटी प्लस इंक्लूसिव'। इसमें पहचान, हिंसा, परिवार और रोजगार के मुद्दों पर व्यापक अध्यन किया गया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य ऐसे कानूनों की पहचान करना है जो स्त्री और पुरुष ढांचे के अंतर्गत काम करता है या एलजीबीटी सदस्य के खिलाफ भेदभाव करता है। विधि शोध टीम के अक्षत अग्रवाल के मुताबिक, 'इस अध्ययन का मकसद समावेशी कानून को स्थापित करने के लिए बातचीत शुरू करना है।'

अध्ययन के मुताबिक समलैंगिक संबंध को गैर-आपराधिक बनाने के बाद घरेलू हिंसा की वारदातों में इजाफा हुआ है। दबाव में हुई शादियों से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जिससे हिंसा अधिक बढ़ी है।

तब फैसले का आधार बना एड्स संक्रमण का मुद्दा

जनसत्ता ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सहमति से दो वयस्कों के बीच बने समलैंगिक यौन संबंध को एक मत से अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की अनुच्छेद 377 के एक हिस्से को, जो सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध बताता है, तर्कहीन, बचाव नहीं करने वाला और मनमाना करार दिया। अनुच्छेद 377 पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था समलैंगिकता कोई मानसिक विकार नहीं। अनुच्छेद 377 की संवैधानिकता को पहली बार 2001 में चुनौती दी गई थी।

दिल्ली की एक संस्था है 'नाज फाउंडेशन'। यह संस्था काफी समय से एड्स की रोकथाम और इसके प्रति जागरूकता का काम कर रही है। 2001 में इसी संस्था ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुच्छेद 377 को गैर-संवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। इसके बारे में संस्था की संस्थापक अंजलि गोपालन का कहना था, 'समलैंगिक संबंध बनाने वाले पुरुष एड्स होने पर भी सामने नहीं आते। उन्हें डर होता है कि अनुच्छेद 377 के तहत उन्हें सजा न हो जाए। ऐसे में एड्स की रोकथाम तो क्या संक्रमित लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती। पुलिस अधिकारियों द्वारा समलैंगिक लोगों के उत्पीड़न के भी कई मामले हुए हैं। ऐसे में वे लोग सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए चिकित्सकीय सामग्री खरीदते वक्त भी घबराते थे।'

अंजलि गोपालन

इन्हीं कारणों को लेकर यह संस्था दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। फाउंडेशन की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि धारा 377 कई लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। अदालत को यह तय करना था कि क्या अनुच्छेद 377 संविधान के 21, 14 और 15 का अतिक्रमण करती है? यह फैसला करने में न्यायालय ने लगभग नौ साल का समय लिया। इस बीच अनुच्छेद 377 के हर पहलू और उसकी संवैधानिक मान्यता पर बहस हुई। नाज फाउंडेशन ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया कि विधि आयोग भी अपनी 172वीं रिपोर्ट में अनुच्छेद 377 को हटाने की संस्तुति कर चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

केंद्र की तरफ से दो विरोधाभासी जवाब दाखिल किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शपथपत्र दाखिल करते हुए कहा कि यह धारा एड्स की रोकथाम में बाधा उत्पन्न करती है, लिहाजा इसे हट जाना चाहिए। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने इसे बनाए रखने की बात कही। गृह मंत्रालय ने अपने शपथपत्र में कहा कि अनुच्छेद 377 बच्चों पर होने वाले अपराध एवं बलात्कार संबंधी कानून की कमियों को भरने का काम करती है। हालांकि केंद्र सरकार के इस तर्क का आज कोई महत्त्व नहीं रह गया है। बच्चों के लिए 2012 में अलग से 'बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम, 2012' बन चुका है। साथ ही बलात्कार की परिभाषा की जिन कमियों को अनुच्छेद 377 पूरा करती थी, उन कमियों को भी निर्भया मामले के बाद अब दूर किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क था कि यह अनुच्छेद संविधान के 15 और 21 का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से उसके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 21 के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इस अधिकार में सम्मान से जीवन जीना और गोपनीयता/ एकांतता का अधिकार भी शामिल है। इसी अनुच्छेद का सहारा लेते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दो वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से एकांत में जो भी करते हैं उसका उन्हें पूरा अधिकार है।

दो जुलाई, 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में दे दिया। इसके विरोध में कई धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल अदालत पहुंचे। समलैंगिकता के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हुई। हाई कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले को पलटते हुए दिसंबर, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग 100 पन्नों का फैसला दिया। 11 दिसंबर, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। बाद में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया।

ऐसे लड़ी लड़ाई

अनुच्छेद 377 में क्या था

धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में था। इसमें 10 साल या फिर जिंदगी भर जेल की सजा का भी प्रावधान था, वो भी गैर-जमानती। समलैंगिकता की इस श्रेणी को एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीअर) कहा जा रहा है। इसी समुदायों के लोग लंबे समय से इस धारा में बदलाव की मांग कर रहे थे।

किन मामलों में अब भी लागू

अगर दो लोग बालिग हैं और उनके बीच यौन संबंध को लेकर सहमति नही है।
अगर बच्चों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया जाता है।
अगर कोई शख्स जानवरों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते पाया जाता है। इन मामलों में 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। ये गैर-जमानती मामले हैं।

अनुच्छेद 377 की शुरुआत

इस एक्ट की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1861 में इंडियन पीनल कोड (आइपीसी) ड्राफ्ट करते वक्त की। आपसी सहमति के बावजूद दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच सेक्स, पुरुष या महिला का आपसी सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध, पुरुष या महिला का जानवरों के साथ यौन संबंध या अप्राकृतिक हरकतों को इस श्रेणी में रखा गया है। धारा-377 इस देश में अंग्रेजों ने 1862 में लागू की थी।

इन देशों में अपराध नहीं समलैंगिकता

ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, जर्मनी, फिनलैंड, कोलंबिया, आयरलैंड, अमेरिका, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, लक्जमबर्ग, इंग्लैंड और वेल्स, ब्राजील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, उरुग्वे, डेनमार्क, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे 26 देशों में समलैंगिकता अपराध नहीं है।

कानूनी मंजूरी, पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की दूरी

जनसत्ता ब्यूरो

यूएन में मतदान

इस साल समलैंगिक अधिकारियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान भारत ने दूरी बना ली। इस मुद्दे पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया।

संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर मतदान प्रक्रिया में किस देश ने क्या फैसला लिया, इसकी सूची चार्ट के रूप में जारी की है। इस प्रक्रिया में भारत अनुपस्थित रहा, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने मतदान में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर असहमति जताई। इसमें कुल 37 देशों ने हिस्सा लिया। समलैंगिक (एलजीबीटीक्यू) समुदाय के अधिकारों के समर्थन में 27 देशों ने मतदान किया और इसके खिलाफ 12 देशों ने वोट डाले। वहीं इस प्रक्रिया से भारत समेत सात देश बाहर रहे।

दरअसल, न्यूयॉर्क में होने वाले एलजीबीटी परेड को गर्वोत्सव (प्राइड परेड) की मान्यता मिली हुई है। इस परेड में इस कम्युनिटी के लोग हाथों में एक छह रंगों वाला झंडा लेकर निकलते हैं। इस साल प्राइड के 50 साल पूरे होने के जश्न की मेजबानी न्यूयॉर्क अंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी प्राइड परेड ने किया। इसे स्टोनवैल 50 के रूप में जाना जाता है। पूरे एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए ये परेड एक तरह के विशेष उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसके जरिए वे दैहिक चेतना, खुद की पहचान और यौनिक मुक्ति का ऐलान करते हैं। न्यूयॉर्क शहर की क्रिस्टोफर स्ट्रीट पर प्राइड परेड का आयोजन किया जाता है। यह समलैंगिकों का गर्वोत्सव है। अब धीरे-धीरे भारत के तमाम शहरों में भी गर्वोत्सव (प्राइड परेड) प्रचलित हो रही है।

गूगल ने इस साल चार जून के डूडल को 50 साल के प्राइड और एलजीबीटीक्यू समुदाय की स्वीकृति को समर्पित किया। गूगल ने कई स्लाइड्स में प्राइड परेड के सफर को दिखाया। 1969 से हर 10 साल के बाद प्राइड परेड में किस तरह के बदलाव आए। पिछले साल भारत में भी समलैंगिकता को कानूनन स्वीकार कर लिया गया।

मुकदमा जीतने वालीं दोनों वकील खुद भी हैं 'जोड़ा'

जनसत्ता ब्यूरो

पते की बात

समलैंगिक समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने वाली वकील अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी का नाम पिछले दिनों दुनिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में आया था। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका 'टाइम' की ओर से जारी सूची में महज तीन भारतीय नाम शामिल थे, जिनमें मुकेश अंबानी के अलावा ये दोनों वकील शामिल हुईं। इन दोनों वकीलों ने खुलासा किया है कि ये 'कपल' (जोड़ा) हैं। अरुंधति ने हाल ही में हैशटैग साड़ी ट्विटर ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी साथी मेनका के साथ वाली फोटो ट्विटर पर पोस्ट की थी।

अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने 18 जुलाई को टीवी चैनल सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में दुनिया के सामने अपना प्यार कबूला। इंटरव्यू के दौरान मेनका और अरुंधती ने कहा कि यह लड़ाई आसान नहीं थी। बहुत लंबी और मुश्किल जंग थी। आखिरकार वह पांच जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इस बात के लिए मनाने में कामयाब रहीं कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मिली यह जीत सिर्फ उनके पेशे की जीत नहीं थी बल्कि निजी कामयाबी भी थी। मेनका और अरुंधति दोनों ही सफल वकील हैं। मेनका ने हावर्ड स्कूल से एलएलएम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया है। वह बर्लिन के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज की फेलो रह चुकी हैं। यही नहीं वह कोलंबिया लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जैसे विश्वप्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों की विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। वहीं अरुंधति ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री हासिल की है।

सुप्रीम कोर्ट में मिली ऐतिहासिक जीत के लगभग एक साल बाद एडवोकेट मेनका और अरुंधति ने खुलासा किया है वह खुद भी समलैंगिक जोड़ा हैं। सीएनएन को दिए इंटरव्यू में दोनों ने न सिर्फ धारा 377 के खिलाफ अपनी जीत के बारे में बताया, बल्कि अपने रिश्ते को भी सार्वजनिक किया। इंटरव्यू के दौरान जब टिप्पणी की गई कि 377 के खिलाफ जीत सिर्फ वकीलों के तौर पर बड़ी जीत नहीं थी, बल्कि एक जोड़े (कपल) के तौर पर भी थी, तो वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि साल 2013 में (फैसला विरुद्ध आने पर) एक वकील के तौर पर, देश के नागरिक के तौर पर नुकसान हुआ था, वह व्यक्तिगत नुकसान था। एक 'अपराधी' होना अच्छा नहीं लगता, जिसे दूसरे मामलों पर बहस के लिए एक वकील के रूप में कोर्ट में वापस जाना पड़ता है।

कश्मीर पर राहुल के बयानों से शर्मिंदा होना चाहिए कांग्रेस को : शाह

सिलवासा/सोलापुर, 1 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को इस पर 'शर्मिंदा' होना चाहिए कि उसके नेता राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर अपनी याचिका में इस्तेमाल किया। भाजपा अध्यक्ष शाह ने सिलवासा एक जनसभा में राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के नरेंद्र मोदी सरकार के कदम का समर्थन किया है लेकिन कुछ लोग अब भी उसका विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के कदम का विरोध किया। राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं उसकी गूंज पाकिस्तान में सुनाई देती है। पाकिस्तान ने अपनी अर्जी में उनके बयानों को शामिल किया है। कांग्रेस नेताओं को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि इन बयानों का भारत के विरूद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के बाद कश्मीर में हिंसा की खबरों और 'लोगों के मरने' का बयान में जिक्र किया था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी याचिका में इसका उल्लेख किया।

शाह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं पूरे देश और दुनिया को बताना चाहूंगा कि कश्मीर पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से एक भी गोली नहीं चली और न ही आंसू गैस का गोला दागा गया और न किसी की जान गई। गृह मंत्री ने कहा कि विशेष दर्जा समाप्त करने से जम्मू कश्मीर के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और यह आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील होगा।

शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 'महाजनादेश यात्रा' का दूसरा चरण समाप्त होने के मौके पर सोलापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राकांपा प्रमुख शरद पवार को चुनौती दी कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने पर अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने कहा, 'मैं राहुल गांधी और शरद पवार से महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में जाने से पहले पूछना चाहता हूं कि वे संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को खत्म करने के हमारे निर्णय पर अपना रुख स्पष्ट करें।'

शाह ने कांग्रेस और राकांपा के नेताओं के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने पर दोनों पार्टियों पर रविवार को तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे के गृह नगर में कहा कि भाजपा अगर अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दे तो शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण के सिवाय उनकी पाटियों में कोई नहीं बचेगा। बताते चलें कि दोनों पार्टियों, खासकर, राकांपा के कई नेता भाजपा और शिवसेना में शामिल हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेताओं में उभरे मतभेद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के नेता आपस में ही बंट गए हैं। जहां पार्टी के कुछ नेता प्रधानमंत्री के अच्छे कामों की तारीफ करने के पक्षधर हैं, वहीं नेताओं का एक गुट न केवल इस सलाह के खिलाफ खड़ा हो गया है, बल्कि पीएम मोदी के पक्ष में बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा है।

कांगेस नेता जयराम रमेश ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक मॉडल में सब कुछ खराब ही नहीं है और उनके द्वारा किए गए काम को स्वीकार नहीं करने और हमेशा उनकी आलोचना करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस के अन्य नेताओं शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस टिप्पणी को लेकर जयराम रमेश का साथ दिया था और कहा था कि सही काम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी होनी चाहिए।

दूसरी ओर, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम में अच्छाई खोजना भूसे के ढेर में सूई खोजने जैसा है। देश जिस तरह से चल रहा है कांग्रेस उसे लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने एक

- जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी व शशि थरूर सरीखे नेताओं ने पीएम के अच्छे कामों के समर्थन की कही थी बात
- सलमान खुर्शीद और केरल कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने अलापे विरोधी सुर
- कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली भी जयराम व अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की कर चुके हैं मांग

साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा आलोचना नहीं करने की रमेश और अन्य नेताओं की टिप्पणी के संबंध में वह किसी को सीधे-सीधे जवाब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उससे और भ्रम पैदा होगा। उन्होंने कहा कि रमेश ने वह कहा जो वह कहना चाहते थे। हम सभी चीजों को उसी हिसाब से देखते हैं जो हमारे लिए सही होता है।

इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने भी जयराम रमेश व पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा पीमए मोदी के अच्छे कामों की तारीफ करने संबंधी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और पार्टी हाईकमान से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। केरल कांग्रेस ने भी ऐसे विचार व्यक्त करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सूबे की राजधानी तिरुवनंनतपुरम संसदीय सीट से पार्टी के सांसद शशि थरूर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि पार्टी ने सांसद थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई तो फिलहाल नहीं की है लेकिन प्रदेश के एक अन्य सांसद मुरलीधरन ने यह कह कर शनिवार को थरूर का नाम लिए बगैर पर हमला बोला कि कांग्रेस तिरुवनंनतपुरम की सीट ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी की वजह से नहीं, बल्कि भाजपा व मोदी विरोध की अपनी नीति की वजह से जीती।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू

जयपुर, 1 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चयनित परिवारों और सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना रविवार से प्रदेशभर में लागू कर दी गई है। एक सरकारी बयान के अनुसार इस योजना से राज्य के 1 करोड़ 10 लाख से अधिक परिवारों को निशुल्क इलाज उपलब्ध हो सकेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि पूर्व में लागू भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आयुष्मान भारत योजना को एकीकृत करके प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि योजना में शामिल परिवारों को संपूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं कैशलेस उपलब्ध होंगी। वर्तमान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के पात्र परिवारों को पूर्ववत इलाज मिलता रहेगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि आर्थिक सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों को भी वर्तमान योजना से जोड़कर योजना का दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान में भामाशाह से संबद्ध सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि योजना के लागू होने से प्रदेश के दो तिहाई से भी अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा।

क्षत्रपों के दबाव में नहीं झुकेगी कांग्रेस, हरियाणा-दिल्ली पर फैसला शीघ्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस की सियासी ताकत भले कम हो गई हो, उसके पास केंद्र की सत्ता का दमखम बेशक नहीं हो लेकिन पार्टी अपने क्षत्रपों के दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगी। चुनावी राज्यों में नई टीम के गठन की जारी कवायद के तहत दबाव बनाने वाले कद्दावर नेताओं को साफ संकेत दे दिया गया है कि पार्टी हाई कमान ऐसे किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ऐसे संकेत हैं कि महाराष्ट्र व झारखंड के बाद कांग्रेस अगले एक-दो दिन में हरियाणा व दिल्ली में अपनी नई टीम का एलान करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले कुछ दिनों में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के पार्टी नेताओं से अलग अलग सूबों में कांग्रेस के नए नेतृत्व को लेकर चर्चा की है। बीते कुछ दिनों में उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी सहित सूबे के अन्य नेताओं से मुलाकात की है, वहीं उन्होंने दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉ एके वालिया की राय भी उन्होंने जान ली है। मध्य प्रदेश व पंजाब के पार्टी नेताओं से भी उनकी गुफ्तगू हो चुकी है। चूंकि हरियाणा व दिल्ली में चुनाव होने हैं, लिहाजा इन दोनों राज्यों के लिए पार्टी की चुनावी टीम की घोषणा जल्दी की जानी है।

- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा-दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं की राय जानी
- दोनों प्रदेशों में नई चुनावी टीम का एलान जल्दी होने के आसार

हरियाणा को लेकर कहा जा रहा है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी हाई कमान से कहा है कि आगामी चुनाव में या तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए या फिर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें सौंपी जाए। इस कुर्सी पर पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने भी दावा ठोक रखा है जबकि हुड्डा के कट्टर विरोधी अशोक तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष की अपनी कुर्सी पर जमकर बैठे हैं। सूबे के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के समर्थक भी लगातार कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान इस बार बिश्नोई को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा जबकि कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी जोरों पर है। हुड्डा ने हाल ही में रोहतक में एक रैली कर बागी तेवर दिखाए थे। लिहाजा, माना जा रहा है कि वे पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं।

दिल्ली में अध्यक्ष पद के दावेदारों में जयप्रकाश अग्रवाल, सुभाष चोपड़ा, अजय माकन और अरविंदर सिंह लवली के नाम लिए जा रहे हैं जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को सूबे की कमान देने की मांग भी होती रही है। अपने 15 साल के शासन में दिल्ली को चमकाने वाली दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दो-दो बार पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस महाराष्ट्र व झारखंड में भी तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए उचित फैसले लिए और हरियाणा व दिल्ली सरीखे राज्यों में भी पार्टी सही लोगों को सही कुर्सी पर बैठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की यह कोशिश है कि संतुलन और समन्वय बने और सबको उचित प्रतिनिधित्व मिले। हरियाणा व दिल्ली में कुछ नेताओं द्वारा पार्टी छोड़े जाने संबंधी कयासों को लेकर पूछने पर उनका कहना था कि ऐसी खबरें विरोधी पक्ष के लोग उड़ा रहे हैं।

आरिफ मोहम्मद खान होंगे केरल के राज्यपाल

पेज 1 का बाकी

हमें ईएसएल नरसिम्हन की उत्तराधिकारी होंगी। केरल में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की जगह नए राज्यपाल बने खान (68) मुसलमानों में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर पत्नी से संबंध खत्म करने की परंपरा के मुखर विरोधी हैं और लंबे समय से मुसलिम पर्सनल लॉ में बदलाव की वकालत कर रहे हैं।

शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शुरुआती दिनों में राजीव गांधी सरकार द्वारा समर्थन किए जाने पर 1985 में संसद में खान का भाषण बेहद महत्त्वपूर्ण है। हालांकि बाद में मुसलमान मौलवियों के तथाकथित दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने संसद में एक विधेयक पारित कर शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य करार दिया। खान ने उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश के खान बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे लेकिन 2007 तक वे राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक विधेयक लाए जाने पर खान ने उसका समर्थन किया। शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात कही थी।

'सिख लड़कियों के अपहरण व धर्मांतरण पर कार्रवाई करे पाक'

पेज 1 का बाकी

लगाया कि एक ग्रंथी की किशोर बेटी का अपहरण कर बंदूक के बल पर धर्मांतरित करने के बाद एक मुसलिम व्यक्ति से उसका निकाह कराया गया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जन्मस्थल ननकाना साहिब में सिख समुदाय के लोगों ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

मंदी की आहट के बीच जीएसटी संग्रह में गिरावट

पेज 1 का बाकी

की है, जबकि 24,239 करोड़ राशि राज्यों को मिली है। 48,958 करोड़ रुपए आइजीएसटी से मिले हैं। राजस्व विभाग के अनुसार जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2019 तक कुल 75.80 लाख लोगों ने जीएसटीआर 3 बी के तहत रिटर्न भरा है। इस साल यह दूसरी बार हुआ है जब जीएसटी संग्रह फिसलकर एक लाख करोड़ के नीचे आया है। पहली बार ऐसा जून में हुआ था, जब 99,939 करोड़ का संग्रह हुआ था। राजस्व विभाग के मुताबिक, कुल 7,273 करोड़ रुपए सेस से मिले, जिसमें 841 करोड़ रुपए का कलेक्शन आयात से किया गया। जुलाई का जीएसटीआर 3बी रिटर्न 31 अगस्त तक 75.80 लाख रुपए का जमा किया गया।

अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी से आय में पहले भी कई बार गिरावट या बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में चिंता की जरूरत नहीं है। अगले कुछ महीनों में जीएसटी से होने वाली आय से ही असल परिस्थिति साफ होगी। गौरतलब है कि जीएसटी के पहले जीडीपी का झटका लगा। देश की विकास दर में गिरावट दर्ज हुई है। पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर 5.8 फीसद से घटकर पांच फीसद हो गई। अगर सालाना आधार पर तुलना करें तो लगभग तीन फीसद की गिरावट है। एक साल पहले इसी तिमाही में जीडीपी की दर आठ फीसद थी।

विपक्ष के चार-पांच नेता शामिल किए गए, नहीं पड़ेगा भाजपा पर असर : फडणवीस

मुंबई, 1 सितंबर (भाषा)।

विपक्षी कांग्रेस और राकांपा के कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को संकेत दिया कि जो पार्टी में शामिल किए गए हैं वे सत्तारूढ़ दल के नेताओं की कुल संख्या का महज दो फीसद हैं।

फडणवीस ने कहा कि किसी भी भविष्यवेत्ता के लिए कांग्रेस एवं राकांपा के अंधकारमय भविष्य का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। वह आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क अभियान महाजनादेश यात्रा के तहत लातूर जिले में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

जब उनसे एक संवाददाता ने भाजपा में बड़ी संख्या में नए लोगों के शामिल होने के बीच भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'हमने अब तक ऐसे चार-पांच नेताओं को ही शामिल किया है, जिन्हें पार्टी में शामिल हुए लोगों के बीच में से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने की जरूरत है। भाजपा नेताओं का मूल संख्या बल 98 फीसद है।'

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर भी निशाना साधा जिन्होंने कटाक्ष किया था कि फडणवीस यह अनुमान लगाकर राजनीतिक भविष्यवेत्ता की तरह बात कर रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी को अगली विधानसभा में विपक्ष का नेता पद मिल सकता है।

'लिंकन हाउस का कब्जा न मिलने के लिए नौकरशाही जिम्मेदार'

मुंबई, 1 सितंबर (भाषा)।

व्यवसायी अदार पूनावाला ने मुंबई के चर्चित लिंकन हाउस का कब्जा नहीं मिल पाने के लिए नौकरशाही उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया है।

पुणे मे वैक्सीन निर्माता संस्थान 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' चलाने वाले अरबपति पूनावाला परिवार ने 2015 में 750 करोड़ रुपए की बोली लगाकर लिंकन हाउस को खरीदा था। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला ने बताया कि चार साल बाद, पर्याप्त राशि का भुगतान करने के बाद भी परिवार को संपत्ति का कब्जा मिलना बाकी है। उन्होंने इसके लिए भारतीय अधिकारियों के नौकरशाही उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया। वांकानेर के तत्कालीन महाराजा के दो एकड़ में फैले इस बंगले को 1957 में अमेरिका ने लीज पर लेकर वाणिज्य दूतावास का कार्यालय बनाया था। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बाद में यहां बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में ले जाया गया। पूनावाला परिवार ने अमेरिका के साथ सौदा किया था, जिसमें पट्टे के अधिकारों का हस्तांतरण शामिल था। पूनावाला ने कहा, 'मैंने कभी भी इस संपत्ति को नहीं छुआ क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इस सौदे में कोई समस्या न आ जाए। पट्टा 999 वर्षों के लिए है और 1957 में शुरू हुआ। हमारे पास 900 और वर्ष हैं।' हालांकि पूनावाला ने कहा कि उन्हें सौदा रोकने के लिए कोई खास कारण नहीं बताए गए है। यह भूमि रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा विभाग के अधीन आती है, जिसे सौदे के लिए आगे बढ़ने और पट्टे के अधिकारों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

पुंछ : पाक की गोलाबारी में जवान शहीद

पेज 1 का बाकी

कर्नल देवेंद्र आनंद ने बयान में बताया था, 'दोपहर बाद करीब एक बजे पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।' अधिकारियों के अनुसार सीमा पर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी और अंतिम समाचार मिलने तक जारी थी।

गैर-सबसिडी वाला सिलेंडर 15.5 रुपए महंगा

पेज 1 का बाकी

है। पेट्रोलियम कंपनियों की अधिसूचना के मुताबिक बिना सबसिडी वाली रसोई गैस (एलपीजी) प्रति सिलेंडर 15.5 रुपए महंगी हो गई। यह अब 590 रुपए का हो गया है। दिल्ली में विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) 596.62 प्रति किलोलीटर या 0.9 फीसद सस्ता होकर 62,698.86 प्रति किलोलीटर हो गया। किरोसिन की कीमत में लगातार 26वें महीने प्रति लीटर 25 पैसे की वृद्धि जारी रही।

राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी के दामों में रविवार को वृद्धि की गई। अप्रैल से सीएनजी के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। रुपए की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से सीएनजी महंगी हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लि. (आइजीएल) ने बयान में कहा कि दिल्ली, रेवाड़ी, गुरुग्राम और करनाल में सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमतों में 55 पैसे प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी अब 47.10 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अब यह 53.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। गुरुग्राम और रेवाड़ी में सीएनजी का दाम 58.95 रुपए प्रति किलोग्राम और करनाल में 55.95 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है।

इस साल अप्रैल से सीएनजी के दामों में यह तीसरी वृद्धि है। अप्रैल, 2018 से इसमें आठवीं बार बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर अप्रैल, 2018 से सीएनजी के दामों में 7.39 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। आइजीएल ने कहा कि वह रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में चुनिंदा सीएनजी आउटलेट्स पर डेढ़ रुपए प्रति किलोग्राम की छूट जारी रखेगी।

जम्मू-कश्मीर में अगस्त तक 139 आतंकियों का सफाया

पेज 1 का बाकी

मंत्रालय के मुताबिक, इसी अतंराल में भारतीय सेना ने 26 जवान गंवाए हैं। इनमें सैनिकों से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक शामिल हैं। सबसे ज्यादा आठ सिपाही इस साल फरवरी महीने में शहीद हुए थे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगस्त महीने में पांच आतंकियों को मार गिराया गया जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया है। मई के महीने में सेना और आतंकियों के बीच कई मुठभेड़ हुई।

केवल मई के महीने में ही सेना ने 27 आतंकियों को मार गिराया, जोकि बाकी किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा है। मई के महीने में ही सबसे ज्यादा 22 मुठभेड़ हुई। इस साल आतंकियों ने कुल 87 हमले करने की कोशिश की। जुलाई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान की बॉर्डर ऐक्शन टीम (बैट) के स्पेशल सविर्सेज ग्रुप कमांडोज की कोशिशों को भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। एलओसी पार करने की कोशिश में लगे चार बैट कमांडोज को भी भारतीय सेना ने मार गिराया।

अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ने इस साल भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की ज्यादा कोशिश की है, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ के नए प्रयास किए गए हैं। यह इस साल पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन की संख्या से स्पष्ट है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन के 222 मामले सामने आए हैं। संघर्ष विराम उल्लंघन के सबसे ज्यादा 296 मामले जुलाई में दर्ज किए गए।

कुलभूषण जाधव को आज राजनयिक पहुंच की पेशकश

पेज 1 का बाकी

के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि हम राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के संपर्क में हैं। हमने आइसीजे के आदेश के आधार पर तत्काल, प्रभावी और अबाधित राजनयिक पहुंच देने को कहा है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ताजा पेशकश की पुष्टि की है। साथ ही कहा कि हम अभी इसका अध्ययन करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक पहुंच को लेकर हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अबाधित और बिना किसी प्रतिबंध के होना चाहिए। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी।

इस फैसले का विरोध करते हुए भारत ने द हेग स्थित आइसीजे का रुख किया था जिसने जाधव की फांसी पर तत्काल अंतरिम रोक लगा दी थी। वहीं, इस साल जुलाई में एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई। अपने 42 पेज के फैसले में आइसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से सजा की समीक्षा करने को कहा है। इसके साथ-साथ उसे जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया गया।

आइसीजे ने अपने आदेश में कहा कि भारत को राजनयिक पहुंच न देकर पाकिस्तान ने वियना सम्मेलन का उल्लंघन किया है।

अर्थव्यवस्था को सुस्ती से निकाले सरकार : सिंह

पेज 1 का बाकी

भी मुश्किल से निकल पाने की आरबीआइ की क्षमता की परीक्षा भी होगी। उन्होंने कहा कि घरेलू मांग में नरमी है और खपत का दर 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर है, वहीं जीडीपी की विकास दर 15 साल में सबसे कम है और कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि अभी भी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कर संग्रह में उछाल की जो उम्मीद थी वह नजर नहीं आ रही है, कारोबारी, चाहे छोटे हों या बड़े, उन्हें परेशान किया जा रहा है, कर आतंकवाद में कमी नहीं आई है। निवेशकों का उत्साह डांवाडोल है।

इस आधार पर तो आर्थिक नरमी से उबरना संभव नहीं लगता। बिना रोजगार सृजन वाले वृद्धि के लिए मोदी सरकार की नीतियों को दोषी बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में साढ़े तीन लाख से ज्यादा नौकरियां गई हैं।

सिंह ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर नौकरियां गई हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर तबके के लोगों को हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत की हालत बहुत खराब है क्योंकि किसान को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र की आय घटी है। उन्होंने कहा कि राजग सरकार मुद्रास्फीति के जिस कम दर का प्रचार करती रहती है उसका सबसे प्रतिकूल असर किसानों और उनकी आय पर पड़ रहा है।

अपनों पर जुल्म करने वाले हमें न दें सीख : भारत

पेज 1 का बाकी

पलटवार किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा, 'जिस मुल्क ने बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों का नरसंहार किया हो, उसे मानवाधिकार पर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है।' उन्होंने पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद बंद करने की भी नसीहत दी। पाकिस्तानी नुमाइंदों का हंगामा जारी रहा तो रोकने के लिए मालदीव की संसद के स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा।

यह सम्मेलन सतत विकास (सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल) के मुद्दे पर आयोजित किया गया था। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व वहां की नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सुरी और पाकिस्तानी सेनेटर कुर्तुल एन मारी कर रहीं थी। मालदीव इसका मेजबान है। अपने भाषण के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि कासिम सुरी ने कश्मीर का राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा, 'हम कश्मीर की जो स्थिति है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां लोगों पर अत्याचार हो रहा है।' इसका भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तीखा विरोध किया। जोरदार पलटवार करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा, 'भारत के आंतरिक मामले को इस फोरम में उठाए जाने पर हम पुरजोर आपत्ति जाहिर करते हैं। इसके अलावा सम्मेलन के विषय से इतर मुद्दों को उठाकर इस फोरम के राजनीतिकरण को भी हम खारिज करते हैं।'

आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरते हुए हरिवंश ने कहा, 'पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद और इसे अपने तरफ से दिए जा रहे हर तरह के समर्थन को खत्म करना चाहिए। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए यह करना जरूरी है। संपूर्ण मानवता के लिए आज आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है।' हरिवंश के बोलने के दौरान पाकिस्तानी सेनेटर मारी ने कश्मीरियों पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इस पर हरिवंश ने कहा, 'एक ऐसा देश जिसने अपने ही लोगों का नरसंहार किया हो, उसे बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है।' इस दौरान बौखलाई मारी चीख-चीखकर उनके भाषण में बाधा पहुंचाने की कोशिश करने लगीं। इसके बाद कार्यक्रम का संचालन कर रहे मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद को दो टूक कहना पड़ा कि इस फोरम में किसी देश के आंतरिक मामले को नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से कहा कि कश्मीर को लेकर जो भी उठाई गई है उसे कार्यवाही से हटा लिया जाएगा।

एनआरसी से छूट गए लोग 'राष्ट्र विहीन' नहीं

पेज 1 का बाकी

नहीं लिया जाएगा और कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार होने तक उन्हें पहले की तरह ही सभी अधिकार मिलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह सूची से बाहर किए गए व्यक्ति को 'राष्ट्र विहीन' नहीं बनाती है। यह कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को 'विदेशी' नहीं बनाती। वे पहले से प्राप्त किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे।' असम में बहुप्रतीक्षित एनआरसी की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई। एनआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है।

epaper.jansatta.com

खबर कोना

इटली में 76वें वार्षिक वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर अभिनेत्री इसाबेल हुपर्ट।

यमन में हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका

सना, 1 सितंबर (एएफपी)।

यमन में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे सऊदी अरब नीत गठबंधन ने रविवार को धमार शहर स्थित हिरासत केंद्र पर हवाई हमले किए जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (आइसीआरसी) ने रविवार को यह जानकारी दी। यमन में आइसीआरसी के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख फ्रांज रॉसेनस्टीन ने धमार का दौरा करने के बाद बताया, 'हमारे आकलन के अनुसार 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।' उन्होंने बताया कि हमले में घायल हुए कम से कम 40 लोगों का शहर के अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बोको हराम के हमले में आठ नाइजीरियाई मारे गए

कानो, 1 सितंबर (एएफपी)।

पूर्वोत्तर नाइजीरिया में बोको हराम के आतंकवादियों ने किसानों पर और एक गांव पर हमला किया जिसमें आठ लोग मारे गए। इसके अलावा आतंकवादी दो लोगों को अगवा करके ले गए। स्थानीय लोगों और मिलिशिया के सदस्यों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने शुक्रवार की शाम बोर्नो प्रांत की राजधानी मायदूगुरी से 15 किलोमीटर दूर बालुम्री गांव पर हमला किया और चार पुरुषों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इसके अलावा आतंकवादी दो लोगों को अगवा कर अपने साथ ले गए। बोको हराम विरोधी मिलिशिया के सदस्यों ने बताया कि आतंकवादियों ने शनिवार को शहर के उपनगर गिदान वाया में एक खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला किया और चार किसानों के सिर धड़ से अलग कर दिए। बालुम्री गांव के एक निवासी ने बताया कि आतंकवादी शुक्रवार देर शाम हमला करने के लिए पैदल आए थे।

अफगानिस्तान के एक और शहर पर तालिबान ने किया हमला

काबुल, 1 सितंबर(एपी)।

तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान के पुली खुमारी शहर पर हमला किया। हाल के दिनों में यह दूसरा शहर है जिसे तालिबान ने निशाना बनाया है और वह भी तब जब अमेरिकी दूत ने दावा किया है कि तालिबान और अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के बेहद करीब हैं। बघलान प्रांत के पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता जवाद बशरात ने बताया कि राजधानी पुली खुमरी के बाहरी इलाके में गोलाबारी जारी है।

प्रदर्शनकारियों ने हवाई अड्डे जाने वाले मार्ग पर यातायात रोका

हांगकांग, 1 सितंबर (एएफपी)।

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रविवार को शहर के हवाई अड्डे को जाने वाले कुछ मार्गों को बंद कर प्रदर्शन किया।

'एयरपोर्ट एक्सप्रेस' ट्रेन के संचालकों ने कहा कि उन्होंने रविवार दोपहर तक सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने हवाई अड्डा बस स्टेशन पर अवरोधक लगाकर टर्मिनलों की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर यातायात को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के इस कदम से उड़ानों में बाधा उत्पन्न हुई और टर्मिनल के अंदर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हांगकांग में बेजिंग समर्थित सरकार द्वारा प्रत्यर्पण विधेयक को पारित कराने के प्रयास के विरोध में दो महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन जारी हैं।

विधेयक के विरोधी इसे हांगकांग की स्वायत्तता में बड़ी सेंध मान रहे हैं। इसी को लेकर वहां लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हो रहे हैं।

हांगकांग में रविवार को हवाई अड्डे के बाहर एकत्रित लोकतंत्र समर्थक।

टेक्सास में गोलीबारी में पांच लोगों की मौत, 21 घायल

ह्यूस्टन, 1 सितंबर (भाषा)।

अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को एक व्यक्ति ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसमें कम से कम पांच व्यक्तियों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि घटना ओडेसा और उसके पास के मिडलैंड की है। पुलिस ने हमलावर का पीछा किया और सिनर्जी थिएटर के पास उसे ढेर कर दिया। पुलिस ने हमलावर की पहचान और उसके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। गोलीबारी की यह घटना स्थानीय समयानुसार शाम तीन बजे की है। स्थानीय मीडिया ने ओडेसा पुलिस विभाग के प्रमुख माइकल गेरके के हवाले से बताया कि हमलावर की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी और जब यातायात पुलिस के अधिकारियों ने उसे रोका तो उसने अधिकारी पर गोलियां चलाईं और इसके बाद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। उन्होंने बताया कि हमलावर ने कई स्थानों पर लोगों पर गोलियां चलाईं। कुछ देर बाद उसने अपनी कार छोड़ दी और डाक सेवा के एक वाहन पर कब्जा कर लिया और उसी पर से गोलियां चलाता रहा। गेरके ने बताया कि इस घटना में कम से कम पांच लोग मारे गए और 21 लोग घायल हो गए। शुरुआत में माना जा रहा था कि गोलीबारी की घटना में दो लोग शामिल हैं। पुलिस ने कहा था कि दोनों हमलावर दो अलग-अलग वाहनों, एक सुनहरे/सफेद रंग की टोयोटा कार में और दूसरा अमेरिकी डाक सेवा की चोरी गई वैन में घूम रहे हैं। मिडलैंड पुलिस विभाग ने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'इस वक्त कोई सक्रिय हमलावर नहीं है। सभी एजंसियां संभावित संदिग्धों के बारे में पता लगा रही हैं।

> *हमलावर का* पीछा कर पुलिस ने सिनर्जी थिएटर के पास उसे ढेर कर दिया। पुलिस ने उसकी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। *गोलीबारी की* घटना स्थानीय समयानुसार शाम तीन बजे की है।

'आस्ट्रेलिया से तमिल परिवार को निर्वासित न करे सरकार'

मेलबर्न, 1 सितंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के राजनेताओं ने रविवार को सरकार से श्रीलंकाई तमिल परिवार को निर्वासित नहीं करने का अनुरोध किया। इस तमिल दंपति और उनके आस्ट्रेलियाई मूल के दो बच्चों के समर्थन में निकाली गई राष्ट्रव्यापी रैलियों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दंपती और उनके बच्चों को देश की सख्त आव्रजन नीतियों के तहत पकड़ा गया है।

अदालत द्वारा उनके निर्वासन पर रोक लगाने के बावजूद शनिवार को दंपति प्रिया व नदेसलिंगम और उनकी दो बेटियों चार वर्षीय कोपिका व दो वर्षीय थारुनिका को सुदूर क्रिसमस द्वीप के एक हिरासत केन्द्र ले जाया गया। यह परिवार आस्ट्रेलिया में रहने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उन्हें श्रीलंका में उत्पीड़न का डर है। संवाद समिति आस्ट्रेलियाई एसोसिएटेड प्रेस की खबर के अनुसार विपक्षी नेता एंथनी अल्बानी ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के समक्ष यह मुद्दा उठाया और इस मामले में आव्रजन मंत्री के हस्तक्षेप करने की जरूरत बताई। लेबर पार्टी के नेता ने सिडनी में पत्रकारों से कहा, 'इन लोगों को यहां आस्ट्रेलिया में बसाना चाहिए। यह सरकार की प्रवासन नीतियों को कमजोर नहीं करेगा। इससे यही स्पष्ट होगा कि सरकार उस बात को सुनने के लिए तैयार है जोकि समुदाय कहना चाह रहा है।' ग्रीन्स नेता रिचर्ड डी नताले परिवार को हिरासत केंद्र में भेजने की सरकार की कार्रवाई को एक 'संवेदनहीन क्रूरता' बताया। प्रिया और नदेसलिगम 2012 में नौका से आस्ट्रेलिया आये थे और 2013 में उन्होंने शरण मांगी थी। आस्ट्रेलिया में जन्मीं उनकी बेटियां कभी भी श्रीलंका नहीं गई है। इस बीच मेलबर्न और आस्ट्रेलिया के अन्य शहरों तथा नगरों में हुई रैलियों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सरकार से इस परिवार को यहीं रहने देने का अनुरोध किया। गृह मामलों के विभाग ने इससे पूर्व आदेश दिए थे कि इस परिवार को श्रीलंका भेजा जाए। हालांकि एक संघीय अदालत ने शुक्रवार को निर्वासन के खिलाफ अंतरिम आदेश की अवधि बुधवार तक बढ़ा दी थी।

> *आस्ट्रेलिया के* राजनेताओं ने सरकार से श्रीलंकाई परिवार के लिए किया अनुरोध *तमिल दंपति* और उनके आस्ट्रेलियाई मूल के दो बच्चों के समर्थन में निकाली गई

पश्चिमी तट पर बसाई गई एक नई यहूदी बस्ती इलकाना में शिक्षा मंत्री राफी पेरेत्ज के साथ बच्चों के स्कूल का दौरा करते इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू।

बांग्लादेश में मंत्री को निशाना बनाकर आइएस ने किया हमला, दो पुलिसकर्मी घायल

ढाका, 1 सितंबर(भाषा)।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक मंत्री को निशाना बनाकर किए गए धमाके में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने ली है।

डेली स्टार अखबार ने पुलिस और चश्मदीदों के हवाले से बताया कि शनिवार रात जब मंत्री साइंस लैब चौराहे से गुजर रहे थे तभी उन पर बम फेंका गया। इस हमले में मंत्री बालबाल बच गए। अखबार ने सहायक उपनिरीक्षक एबी शहाबुद्दीन को उद्धृत किया, 'मंत्री के सुरक्षा दल में छह पुलिसकर्मी थे। घटना के समय मंत्री बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के कार्यक्रम में जा रहे थे। साइंस लैब चौराहे के पास हम लाल बत्ती की वजह से फंस गए। मैं वाहन से उतर कर यातायात पुलिस से मंत्री के लिए रास्ता साफ करने के लिए कहने जा रहा था तभी विस्फोट हुआ।' विस्फोट में शहाबुद्दीन के अलावा यातायात पुलिस आरक्षी अमीनुल इस्लाम भी घायल हो गए।

केदारनाथ की वीरान गुफा बनी ध्यान साधना के लिए पसंदीदा स्थल

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

केदारनाथ में रुद्र ध्यान नामक जिस गुफा में कभी सन्नाटा पसरा रहता था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने के बाद गुलजार हो गई है और पहली बार उसके लिए 78 प्री बुकिंग हुई है। वर्ष 2018 में यह गुफा आम लोगों के लिए खोली गई थी और तब से पहली बार सितंबर के लिए 19 और अक्तूबर के लिए 10 पर्यटकों ने पहले से बुकिंग कराई है।

इस साल मई में आम चुनाव के अंतिम दिनों के दौरान मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से महज एक किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में एक दिन ध्यान लगाकर बिताया था। इस गुफा का प्रबंधन गढ़वाल मंडल विकास निगम के जिम्मे है।

पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर हैं। उनकी उपस्थिति अतुलनीय है और वह जहां कहीं जाते हैं, लोगों का ध्यान खींचते हैं। वह हमारे सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं।' उन्होंने कहा कि इस साल जिस रुद्र गुफा में वह गए थे, वहां अब पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी है। यह देश के पर्यटन के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बताया गया कि रुद्र गुफा में पहली बार प्री-बुकिंग हुई।

मोदी की यात्रा के तत्काल बाद गुफा के लिए मई में चार, जून में 28, जुलाई में 10, अगस्त में आठ, सितंबर में 19 और अक्तूबर में 10 बुकिंग हुई।

> *प्रधानमंत्री मोदी* के दौरे के बाद लोकप्रिय हुई केदारनाथ रुद्र गुफा, हो रही है भारी प्री बुकिंग, यात्रा के तत्काल बाद गुफा के लिए मई में चार, जून में 28, जुलाई में 10, अगस्त में आठ, सितंबर में 19 और अक्तूबर में 10 बुकिंग हुई।

निगम के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें सितंबर और अक्तूबर में दिवाली तक और बुकिंग मिलने का यकीन है, जब भयंकर सर्दी पड़ने लगती है। उसके बाद हम मई 2020 के लिए बुकिंग करेंगे। इस गुफा को रात्रि के लिए 1500 रुपए में और दिन में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक के लिए 999 रुपए में बुक कराया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि चूंकि यह गुफा सुदूर क्षेत्र में है और ध्यान लगाने के लिए है इसलिए एक बार में केवल एक व्यक्ति को यहां जाने की अनुमति होती है। वैसे यह गुफा नितांत एकांत स्थान है लेकिन उसमें एक फोन लगाया गया है जिसे आपात स्थिति में आंगुतक इस्तेमाल कर सकता है।

इस गुफा में आगंतुकों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था है और इसके भीतर बाथरूम और हीटर भी है। यहां पर्यटक को सुबह की चाय, नाश्ता, लंच, शाम की चाय और डिनर परोसा जाता है। सुविधा के अनुसार इन सेवाओं के समय में फेरबदल किया जा सकता है। गुफा में एक घंटी भी लगी है, जिसे बजाकर सहायक को बुलाया जा सकता है। गुफा में आगंतुक के लिए 24 घंटे सहायक की व्यवस्था की गई है।

रक्षा अनुसंधान संस्थान ने सोलो को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया

लेह/नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने भाषण में औषधीय पौधे सोलो का जिक्र किए जाने के बाद लेह स्थित रक्षा अनुसंधान संस्थान डीआइएचएआर ने लद्दाख में इसकी खेती को लोकप्रिय बनाने का कदम उठाया है।

'डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च' ने लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर पाए जाने वाले सोलो को लोकप्रिय बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया है। सोलो, अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जलवायु अनुकूलन में मदद के अपने गुणों के लिए मशहूर है।

डीआइएचएआर के निदेशक ओपी चौरसिया ने कहा, 'लद्दाख में, सोलो 16,000-18,000 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगला और चांगला जैसे उच्च दर्रों के पास पाया जाता है। इसमें थकावट रोधी और रेडियो-प्रतिरक्षा की क्षमता होती है। यह याददाश्त को बरकरार रखता है और कुछ प्रकार के कैंसर का इलाज कर सकता है। ये गुण इसे एक अद्भुत पौधा बनाते हैं।' उन्होंने कहा, 'इसकी पत्तियां खाने योग्य होती हैं और स्थानीय लोग इसे दही के साथ खाते हैं। इस व्यंजन को 'तंतूर' के नाम से जाना जाता है।'

चौरसिया ने कहा, 'हमने इसकी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को साथ लिया है। हम स्थानीय स्तर पर इसके संरक्षण के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, वन विभाग और सोया रिग्पा संस्थान के भी संपर्क में हैं।' उन्होंने कहा, 'गैर सरकारी संगठन किसानों से बात कर उन्हें 'सोलो' की पैदावार के लाभ से अवगत कराएंगे। वह उन्हें आश्वस्त करेंगे कि उनका निवेश बेकार नहीं जाएगा। हमें किसानों को औषधीय पौधे 'बकथॉर्न' की खेती के लिए मनाने में लगभग 20 साल लगे, जिससे उनकी आय पांच गुना तक बढ़ गई।'

चौरसिया के अनुसार प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने पर अपने भाषण के दौरान इस पौधे का जिक्र किया था, लिहाजा डीआइएचएआर को उम्मीद है कि किसान इसकी पैदावार के लिए प्रोत्साहित होंगे।

> *लद्दाख की* बर्फीली चोटियों पर पाए जाने वाले सोलो को लोकप्रिय बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया है। सोलो, अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जलवायु अनुकूलन में मदद के अपने गुणों के लिए मशहूर है। *सोलो* याददाश्त को बरकरार रखता है और कुछ प्रकार के कैंसर का इलाज कर सकता है।

भारतीय सैनिकों के सम्मान में विदेशों में दो दर्जन से ज्यादा शहीद स्मारक निर्मित हैं | **सम्मान** | ब्रिजटन में छत्री स्मारक का निर्माण करा शहीदों के नाम अंकित कराए हैं

भारतीयों की वीरता का गुणगान कर रहे विश्व के शहीद स्मारक

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

भारतीय सैनिकों की वीरगाथा को भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में संजोया गया है। एशिया, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक दर्जन भर देश हैं जहां भारतीय सैनिकों के सम्मान में दो दर्जन से ज्यादा शहीद स्मारक निर्मित हैं। इन पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारतीय जवानों के नाम अंकित हैं।

जिन देशों ने भारतीयों के बलिदान को अमर करने वाले इन स्मारकों का निर्माण कराया है, उनमें ब्रिटेन, थाइलैंड, बेल्जियम, हांगकांग, मिस्र, यूनान, इटली, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, म्यांमा, सिंगापुर, तुर्की, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। सूचना के अधिकार के तहत विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर तीन दशक पूर्व श्रीलंका गई भारतीय शांति सेना के शहीदों के स्मारक सहित कई देशों में भारतीय सैनिकों के नाम शहीद स्मारकों में सम्मानपूर्वक दर्ज हैं। हरियाणा के आरटीआइ कार्यकर्ता ओम प्रकाश ने सरकार से जानना चाहा था कि भारतीय सैनिकों को शामिल कर-के विदेशों में कितनी लड़ाई लड़ी गई तथा उन देशों में युद्ध स्मारक कहां कहां बने हुए हैं। आरटीआइ के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेल्जियम में लीपर क्षेत्र मेनिन गेट पर शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां विश्व युद्ध में उस देश की रक्षा करते हुए शहीद 413 भारतीय सैनिकों को सम्मान दिया गया हैं।

मित्र राष्ट्रों के गुट की अगुवाई करने वाले ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 12 हजार से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में ब्रिजटन में छत्री स्मारक का निर्माण करा उनके नाम अंकित कराए हैं। ब्रिटेन में ही स्कॉटलैंड में किंग्वीसी युद्ध स्मारक है, जहां द्वितीय विश्वयुद्ध में शहीद होने वाले नौ भारतीय सैनिकों के बलिदान को नमन किया गया है।

यहीं नहीं, चीन के हांगकांग में निर्मित शी वान शहीद स्मारक में 1941 में युद्ध के दौरान शहीद 118 भारतीय सैनिकों के नाम उल्लेखित हैं। मिस्र में अलआमीन युद्ध स्मारक में 1802 भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं। मिस्र में ही हाइफाया सोलुम स्मारक पर 142 शहीद भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। इसी देश में हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर 83 भारतीय सैनिकों के नाम उकेरकर उनके बलिदान को अमरता प्रदान की गई है।

यूनान की रक्षा करते हुए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 58 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इनकी स्मृति में पहेलेरॉन में शहीद स्मारक बना है। तुर्की में प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने जर्मन और तुर्क सेना का मुकाबला किया था। इस युद्ध में अकेले तुर्की में 1516 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों की याद में गैलीपोली में समुद्र के किनारे शहीद स्मारक बनाया गया ।

थाइलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 12 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। सरकार ने कंचानुबूरी शहीद स्मारक में इन शहीदों को सम्मानपूर्वक स्थान दिया है। बैंकाक से करीब सौ किलोमीटर दूर स्थित इस स्मारक को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं। इंडोनेशिया में जकार्ता युद्ध स्मारक में 161 शहीद भारतीय सैनिकों को सम्मान दिया गया है, जिन्होंने जावा एवं सुमात्रा की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर किया था। ईरान के तेहरान में शहीद स्मारक में 3380 भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं।

इटली में कई युद्ध स्मारकों में भारतीय शहीदों के नाम अंकित हैं। इटली के कैसिनो स्मारक में 1438 भारतीय सैनिकों के नाम उल्लेखित हैं तो फ्लोरेंस युद्ध स्मारक में 142 भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं। इटली के फोर्ली शहीद स्मारक में भी अनेकों भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं । इटली के रिमिनी गोरखा युद्ध स्मारक में भारतीय सैनिकों के नाम का उल्लेख है। जापान के योकोहामा युद्ध स्मारक में 46 भारतीय सैनिकों, म्यामां के तुकियान युद्ध स्मारक में 981 भारतीय सैनिकों व सिगापुर के शहीद स्मारक में 781 भारतीय शहीदों को सम्मान प्रदान करते हुए नाम अंकित कराए गए हैं। श्रीलंका में वर्ष 1987 से 90 तक श्रीलंका में लिट्टे के साथ युद्ध लड़ने वाली भारतीय शांति सेना के सैकड़ों जवान शहीद हुए थे। इन शहीदों की स्मृति को चिर स्थाई रखने के लिए श्रीलंका सरकार ने वर्ष 2008 में कोलंबो के बाहर शहीद स्मारक का निर्माण कराया।

> *जिन देशों ने* भारतीयों के बलिदान को अमर करने वाले इन स्मारकों का निर्माण कराया है, उनमें ब्रिटेन, थाइलैंड, बेल्जियम, हांगकांग, मिस्र, यूनान, इटली, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, म्यांमा, सिंगापुर, तुर्की, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं।

नई बिजली नीति को जल्द मिल सकती है मंजूरी

इसमें आपूर्ति में गड़बड़ी पर ग्राहकों को मिलेगा भुगतान

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार ग्राहकों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण बिजली देना सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक नई बिजली नीति मंजूर कर सकती है जिसमें आपूर्ति गड़बड़ होने पर ग्राहकों को वितरण कंपनी से जुर्माना दिलाने का प्रस्ताव शामिल है।

मामले से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है कि बिजली मंत्रालय ने नई बिजली दर नीति का मसौदा मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया है और इसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित बिजली दर नीति के तहत प्राकृतिक आपदा या तकनीकी कारणों को छोड़कर अगर बिजली कटौती की जाती है तो संबंधित वितरण कंपनियों को हर्जाना देना होगा और इसकी धनराशि सीधे ग्राहकों के खाते में जाएगी। जुर्माने का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग करेगा। सूत्रों ने कहा कि नई प्रशुल्क नीति मंत्रिमंडल को भेजी जा चुकी है। इसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में अपने बजट भाषण में 'एक देश, एक ग्रिड' का लक्ष्य हासिल करने के लिए संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम क्रॉस सबसिडी प्रभार, खुली बिक्री पर अवांछनीय शुल्क या औद्योगिक और बिजली के अन्य उपभोक्ताओं के लिए कैप्टिव उत्पादन (निजी उपयोग के लिए) जैसे अवरोधों को हटाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे। इन संरचनात्मक सुधारों के अलावा प्रशुल्क नीति में महत्त्वपूर्ण सुधार की जरूरत है। बिजली क्षेत्र के प्रशुल्क और संरचनात्मक सुधारों के पैकेज की घोषणा की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित प्रशुल्क नीति के तहत बिजली वितरण कंपनियों के लिए सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्राकृतिक आपदा, तकनीकी कारणों, पूर्व सूचना के अनुसार रखरखाव कार्यों को छोड़कर अगर बिजली कटौती की जाती है तो संबंधित वितरण कंपनियों को जुर्माना देना होगा और यह जुर्माना सीधे ग्राहकों के खाते में जाएगा। जुर्माने का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग करेगा। नीति में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने की भी बात कही गई है। यानी वोल्टेज में उतार-चढ़ाव जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। ट्रांसफर्मर में गड़बडी जैसी समस्याएं को निश्चित समय सीमा में दूर करना होगा।

नई प्रशुल्क नीति में बिजली सबसिडी सीधे ग्राहकों के खातों में देने का भी प्रावधान किया गया है। यानी अगर राज्य सरकारें सस्ती बिजली देने की घोषणा करती हैं तो उन्हें सबसिडी वितरण कंपनियों के बजाए सीधे ग्राहकों के खातों में भेजनी होगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से ग्राहक बिजली बचत के लिए प्रोत्साहित होंगे।

वे अधिक बिजली बचत का प्रयास करेंगे ताकि उन्हें सबसिडी ज्यादा से ज्यादा मिले। नई नीति में अगले तीन साल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का भी प्रावधान होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ग्राहक मोबाइल फोन की तरह जरूरत के अनुसार रिचार्ज करा सकेंगे। इससे जहां एक तरफ बिजली बचत को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत भी अच्छी होगी। नई नीति के अमल में आने के बाद वितरण कंपनियों को अगर 15 फीसद से अधिक तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसान हो रहा है तो उन्हें इस आधार पर बिजली शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

वाहन बाजार में मंदी का दौर जारी, मारुति सुजुकी की बिक्री 33 फीसद घटी

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

देश में वाहन बाजार में मंदी का दौर जारी है। अगस्त महीने में सभी वाहन कंपनियों की बिक्री में भारी कमी देखने को मिली है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री आलोच्य महीने में सबसे ज्यादा 32.7 फीसद घटकर 1,06,413 वाहन रह गई। पिछले साल के समान महीने में कंपनी की बिक्री 1,58,189 इकाई रही थी।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि अगस्त में उसकी घरेलू बाजार में बिक्री 34.3 फीसद घटकर 97,061 इकाई रह गई, जो अगस्त, 2018 में 1,47,700 इकाई थी। कंपनी की मिनी कारों आल्टो और वैगनआर की बिक्री इस दौरान 71.8 फीसद घटकर 10,123 वाहन रह गई। एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 35,895 इकाई का था। कॉम्पैक्ट वाहन खंड में कंपनी की बिक्री 23.9 फीसद घटकर 54,274 इकाई रह गई, जो अगस्त, 2018 में 71,364 इकाई थी। इस खंड में स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजाइर गाड़ियां आती हैं। कंपनी की मध्यम आकार की कार सियाज की बिक्री भी भारी गिरावट के साथ 1,596 इकाई पर आ गई। पिछले साल समान महीने में इसकी बिक्री 7,002 इकाई रही थी। हालांकि, समीक्षाधीन अवधि में कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस क्रॉस और अर्टिगा की बिक्री 3.1 फीसद बढ़कर 18,522 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान महीने में 17,971 इकाई थी। अगस्त में कंपनी का निर्यात 10.8 फीसद घटकर 9,352 इकाई रह गया, जो एक साल पहले समान महीने में 10,489 इकाई था।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री अगस्त में 25 फीसद गिरकर 36,085 वाहन रही। पिछले साल अगस्त में कंपनी के 48,324 वाहन बिके थे। कंपनी ने एक बयान में बताया कि अगस्त में उसकी घरेलू बिक्री 26 फीसद गिरकर 33,564 वाहन रही जो पिछले साल इसी माह में 45,373 वाहन थी। समीक्षावधि में कंपनी का निर्यात 15 फीसद घटकर 2,521 वाहन रह गया जो इससे पिछले साल इसी माह में 2,951 वाहन था।

कंपनी की ट्रैक्टर बिक्री अगस्त में 17 फीसद घटकर 14,817 इकाई रह गई। इससे पिछले साल के समान महीने में कंपनी ने 17,785 ट्रैक्टर बेचे थे। कंपनी ने एक बयान में कहा कि घरेलू बाजार में कंपनी की ट्रैक्टर बिक्री 15 फीसद घटकर 13,871 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 16,375 इकाई थी। माह के दौरान कंपनी का निर्यात 33 फीसद घटकर 946 इकाई रह गया, जो एक साल पहले समान महीने में 1,410 इकाई रहा था।

होंडा कार्स इंडिया की बिक्री अगस्त में 51 फीसद घटकर 8,291 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 17,020 इकाई थी। माह के दौरान कंपनी ने 227 वाहनों का निर्यात भी किया। एचसीआइएल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व निदेशक बिक्री और विपणन राजेश गोयल ने कहा कि उपभोक्ता धारणा कमजोर पड़ने से वाहन क्षेत्र में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जबकि वाहन क्षेत्र में ऊंची छूट दी जा रही है और यह कार खरीदने का अच्छा समय है।

वृहद आर्थिक आंकड़ों से तय होगी शेयर बाजार की दिशा

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

स्थानीय शेयर बाजारों की इस सप्ताह की दिशा ताजा वृहद आर्थिक आंकड़ों और अमेरिका-चीन व्यापार विवाद पर वैश्विक बाजारों की प्रतिक्रिया से तय होगी। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। शेयर बाजारों में इस सप्ताह काम के दिन कम होंगे। सोमवार को गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजारों में अवकाश रहेगा।

गत शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी सरकारी आंकड़ों में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पांच फीसद दिखी। यह इसका छह साल का न्यूनतम स्तर है। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में भारी गिरावट के साथ एक फीसद से भी नीचे आ गई है। कृषि क्षेत्र की गतिविधियां भी सुस्त पड़ी हैं।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि जीडीपी की वृद्धि दर में कमी की उम्मीद थी, लेकिन पांच फीसद की वृद्धि दर का आंकड़ा उम्मीद से काफी खराब है। तीसरी और चौथी तिमाही में पिछले साल के निम्न आधार के प्रभाव से जीडीपी की वृद्धि ऊंची हो सकती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती का लाभ भी तीसरी और चौथी में देखने को मिल सकता है। सतत वृद्धि के लिए श्रम और भूमि जैसे संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है।

सैमको सिक्योरिटीज एंड स्टॉक नोट के संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिमीत मोदी ने कहा कि आगामी सप्ताह सुस्ती भरा रहेगा। कॉरपोरेट क्षेत्र से संकेतकों का अभाव रहेगा। ऐसे में बाजार अंतरराष्ट्रीय संकेतकों से दिशा लेगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रमुख खुदरा शोध दीपक जसानी ने कहा कि सार्वजनिक बैंकों का एकीकरण स्वागत योग्य है। यह सार्वजनिक बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए पहला कदम है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच सरकार ने पिछले कुछ सप्ताह के दौरान सुधारों की घोषणा बढ़ाई है।

विश्लेषकों ने कहा कि बाजार को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए पीएमआइ आंकड़ों का इंतजार रहेगा। इससे भी शेयर बाजारों की धारणा प्रभावित होगी। इसके अलावा मासिक बिक्री आंकड़ों के बाद वाहन शेयरों में गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की बिक्री अगस्त महीने में 32.7 फीसद की गिरावट के साथ 1,06,413 इकाई रह गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में भी 25 फीसद की गिरावट आई है। निवेशकों की निगाह रुपए के उतार-चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों के प्रवाह पर भी रहेगी।

तेल-तिलहन कीमतों में मामूली गिरावट

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के बावजूद देश में सस्ते आयात के कारण बीते सप्ताह अधिकांश तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट रही.

बाजार सूत्रों ने कहा कि बेहद साधारण मांग की वजह से केवल सरसों दाना और सीपीओ एक्स-कांडला के भाव में तेजी के अलावा अन्य तेल तिलहनों के दाम घाटे के साथ बंद हुए। उन्होंने कहा कि देश में त्योहारी मांग आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है। इसके बावजूद सस्ते आयात ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। उन्हें अपनी तिलहन फसल मंडी में लागत मूल्य से नीचे और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर औने-पौने भाव में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। मलेशिया से पाम तेल का आयात सरसों व अन्य तेलों के मुकाबले अधिक सस्ता बैठ रहा है जिसके कारण स्थानीय स्तर पर इसकी खपत निरंतर बढ़ रही है।

पिछले हफ्ते सरसों दाने का भाव पांच रुपए की मामूली तेजी के साथ 3,925-3,945 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी का भाव 7,900 रुपए क्विंटल के पूर्व सप्ताहांत के स्तर पर अपरिवर्तित बंद हुआ। दूसरी ओर सरसों पक्की और कच्ची घानी के भाव पांच-पांच रुपए की गिरावट दर्शाते क्रम से 1,285-1,585 और 1,485-1,685 रुपए प्रति टिन पर अपरिवर्तित बंद हुए।

मूंगफली दाना और मूंगफली मिल डिलीवरी गुजरात के भाव क्रम से 20 और 250 रुपए की हानि के साथ 4,710-4,860 और 11,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए। मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड के भाव 1,885-1,925 रुपए प्रति क्विंटल पर अपरिवर्तित बंद हुए। स्थानीय व्यापारियों की बेहद साधारण मांग के कारण तिल मिल डिलीवरी की कीमत 500 रुपए की हानि के साथ 11,500-17,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुई। सोयाबीन मिल डिलीवरी दिल्ली के भाव 40 रुपए की हानि दर्शाते 8,080 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए जबकि सोयाबीन डिगम के भाव सौ टूटकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए।

एसबीआइ कार्ड जल्द जारी करेगा रुपे क्रेडिट कार्ड : सीईओ प्रसाद

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

एसबीआइ कार्ड जल्द ही रुपे क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। इससे घरेलू भुगतान नेटवर्क को व्यापक वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

मौजूदा समय में क्रेडिट कार्ड श्रेणी में अमेरिका की वीजा और मास्टरकार्ड भुगतान गेटवे कंपनियों का दबदबा है। रुपे को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) ने विकसित किया है। यह घरेलू तौर पर विकसित एक भुगतान गेटवे प्रणाली है, जो यूपीआइ, आइएमपीएस और भीम एप जैसे कई भुगतान विकल्प उपलब्ध कराती है।

इससे घरेलू भुगतान नेटवर्क को व्यापक वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

रुपे अपनी तरह की पहली घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली है। एसबीआइ कार्ड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरदयाल प्रसाद ने एक साक्षात्कार में कहा, 'हम जल्द ही (रुपे आधारित क्रेडिट कार्ड) पेश करने जा रहे हैं। एनपीसीआइ के स्तर पर एक आखिरी समझौता होना बाकी रह गया है। मेरा मानना है कि यह एनपीसीआइ इसे किसी भी दिन भेज सकता है और हम कुछ उत्पाद पेश करना जारी कर देंगे।'

प्रसाद ने विश्वास जताया कि रुपे क्रेडिट कार्ड को चालू वित्त वर्ष में पेश कर दिया जाएगा। रुपे बहुत लोकप्रिय होगा और हम देश में इसे बहुत आक्रामक तरीके से उपयोग करेंगे। उन्हें इस बात को लेकर कोई शक-शुबहा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में एक बड़ा राष्ट्रवादी वर्ग है जो रुपे कार्ड पर जोर दे रहा है। देश का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपने एक तिहाई से भी ज्यादा कार्ड, रुपे कार्ड में जारी करता है।

प्रसाद ने कहा कि कंपनी अपने ग्राहकों को रुपे के साथ-साथ मास्टरकार्ड और वीजा कार्ड भी जारी कर सकती है विशेषकर उन्हें जो विदेश यात्रा करते हैं। अभी रुपे कार्ड सिंगापुर, भूटान में मान्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया।

आठ कंपनियों की बाजार हैसियत 77,222 करोड़ रुपए बढ़ी

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)।

सूचकांक की शीर्ष 10 कंपनियों में से आठ के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 77,222.53 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और आइटीसी के पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली।

शुक्रवार को समाप्त सप्ताह में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस), एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आइटीसी, आइसीआइसीआइ बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) का बाजार पूंजीकरण बढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक के बाजार मूल्यांकन में कमी आई।

सप्ताह के दौरान एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 21,657.69 करोड़ बढ़कर 3,73,860.41 करोड़ रुपए और एचडीएफसी बैंक का 17,950.48 करोड़ की बढ़त के साथ 6,09,441.46 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आइटीसी का बाजार मूल्यांकन 11,917.17 करोड़ बढ़कर 3,01,657.76 करोड़ रुपए रहा। आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार पूंजीकरण 9,490.11 करोड़ बढ़कर 2,64,975.02 करोड़ रुपए, इन्फोसिस का 5,454.71 करोड़ बढ़कर 3,49,874.16 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 4,491.96 करोड़ बढ़कर 4,07,004.24 करोड़ रुपए, टीसीएस का 3,940.01 करोड़ बढ़कर 8,47,307.23 करोड़ रुपए और एसबीआइ का 2,320.40 करोड़ बढ़कर 2,44,266.62 करोड़ रुपए रहा।

इस रुख के उलट रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 17,491.60 करोड़ घटकर 7,91,344.45 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार मूल्यांकन 7,791.07 करोड़ गिरकर 2,73,394.07 करोड़ रुपए पर आ गया।

ट्रंप ने 112 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर लगाया 15 फीसद शुल्क

वाशिंगटन, 1 सितंबर (एपी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का सालाना 112 अरब डॉलर के चीन से होने आयातित होने वाले सामानों पर 15 फीसद शुल्क लगाने का फैसला रविवार से प्रभावी हो गया है। इससे अमेरिका में कुछ कपड़े, जूते, खेल सामान और अन्य उपभोक्ता सामान महंगे हो सकते हैं।

इस शुल्क बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में चीन से आयात किए जाने वाला लगभग दो तिहाई उपभोक्ता सामान अब महंगा हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने जब भी चीन से आयात पर शुल्क बढ़ाने की कार्रवाई की तो उपभोक्ता सामान को छोड़ दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद अधिकतर खुदरा सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप सरकार के इस फैसले से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका लगने का खतरा है क्योंकि उपभोक्ता व्यय यहां की अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है। इसके अलावा कमजोर वैश्विक वृद्धि की वजह से निर्यात कमजोर है और कारोबारों ने निवेश व्यय को कम कर दिया है।

ट्रंप के ऊंचे शुल्क लगाने पर कई अमेरिकी कंपनियों ने सरकार को आगाह किया था कि उन्हें यह बढ़ी लागत ग्राहकों से वसूलने पर मजबूर होना पड़ेगा और उन्हें चीन से आयातित सामान महंगा खरीदना पड़ेगा। हालांकि कुछ कारोबारों का कहना है कि वह कीमतें बढ़ाने के बजाय बढ़ी लागत वहन करने का फैसला कर सकते हैं। रविवार की शुल्क बढ़ोतरी के बाद से चीन से आयातित कपड़े और परिधानों पर शुल्क 87 फीसद और जूतों पर 52 फीसद हो जाएगा।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष नई दिल्ली में क्षेत्र स्थित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) खंड (ख) के मामले में

और

ए-वन आर्थटर्नेटस प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट न. 7, पूसा रोड, 9 एक बंगला नया नई दिल्ली कोड — 110007 में स्थित है के मामले में

आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी कंपनी कानून के नियम अनुसार अधिनियम 2013 की धारा 13 और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तरांचल राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए तारीख 31 अगस्त 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संबंध में कंपनी के सदस्य ध्यान दें संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या वह निवेशक निम्नलिखित प्रकृति, उदाहरण, कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में निर्धारित मंत्रालय के एक पंजीकृत पत्र विवरण प्रपत्र दाखिल कर सकता है या एक शपथ पत्र विवरण प्रपत्र दाखिल कर सकता है जिसमें उसके हित की प्रकृति और उसकी विरोध का कारण उल्लेखित हो की सत्य प्रतियां प्रादेशिक निदेशक को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को या रजिस्टर डाक द्वारा भेज सकता है या चुनौती दर्ज कर सकते हैं और इसकी प्रति कार्यालय कंपनी के पंजीकृत निम्नलिखित पोस्टल आईडी के पते पर भी भेजेगा

ए-वन आर्थटेक्स प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट न. 7, पूसा रोड, 9 एक बंगला नया नई दिल्ली कोड — 110007

कृते ए-वन आर्थटेक्स प्राईवेट लिमिटेड

हस्ता./-

तिथि : 31.08.2019 अंजना गुलाटी कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली निदेशक

डीआईएन : 02833326

पता : प्लॉट नम्बर 21 पर स्थित, 21 / बी ऊपर, आकाश दर्शन कॉलोनी, एमएलसी सोसाइटी लिमिटेड, कल्याण नगर, कुमार मुम्बई 400026 एमएच इन्डिया

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2018 के नियम 41 के के विषय में

तथा

मैसर्स कॉमनवील एस्टेट्स लिमिटेड (सीआईएन : U74899DL1987PLC026759), जिसका पंजीकृत कार्यालय 168-69, अमर कालोनी, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024 में स्थित है के विषय में

.....आवेदक / याचिकादाता

सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी ने इसको पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए 17 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित उक्त नियमों के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके उपरि वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

कृते एवं हिते आवेदक

कॉमनवील एस्टेट्स लिमिटेड

हस्ता./-

कमल बीर सिंह

तिथि : 31.08.2019 निदेशक

स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 00274667

पता : मकान नंबर 27, ब्लॉक एफ साउथ सिटी-1, गुरूग्राम-122001

unitech

यूनीटेक लिमिटेड

CIN: L74899DL1971PLC009720

पंजीकृत कार्यालय: बेस्मेन्ट, 6, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017

टेली/फैक्स:- 11-26857338,

E-mail: share.dept@unitechgroup.com

Web: www.unitechgroup.com

सूचना- बोर्ड की बैठक का स्थगन

अन्य बातों के अलावे 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिये बोर्ड की बैठक की तिथि के स्थगन की सूचना देने के लिये "द फाइनांसियल एक्स्प्रैस" में 15 अगस्त, 2019 को तथा "जनसत्ता" में 16 अगस्त, 2019 को प्रकाशित सूचना के अधिक्रम में सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन) अपेक्षा विनियमन, 2015 में शामिल की गई नई विनियमन 33 (3) (एच) की अपेक्षाऐं प्रक्रिया में है तथा कम्पनी की लेखा विभाग ने नई शामिल की गई उक्त विनियमन की अपेक्षाओं का अनुपालन के लिये कुछ और समय देने के लिये अनुरोध किया है।

उपरोक्त को देखते हुए अन्य निदेशकों, लेखा परीक्षकों तथा मुख्य वित्त अधिकारी के साथ परामर्श के बाद कम्पनी के अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक, जो आज के लिये स्थगित थी, को शनिवार तक निलम्बित / स्थगित रखने का फैसला किया है।

तदनुसार 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अन्य संबंधित व्यवसायों से संबंधित मदों पर अब, शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 को विचार किये जायेंगे।

पुनः उपरोक्त स्थगन को देखते हुए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रेडिंग विण्डो बंद रहने की अवधि अब 14 सितम्बर, 2019 को इन परिणामों को सार्वजनिक किये जाने के 48 घंटे बाद तक समाप्त होगी।

निवेशकगण www.unitechgroup.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com भी देख सकते हैं।

यूनिटेक लिमिटेड के लिये

हस्ता./-

गुरुग्राम रमेश चन्द्रा

31 अगस्त, 2019 अध्यक्ष

ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान)

CIN: U27310WB1920GOI003601

"कंकड़िया सेंटर", (4था एवं 5वाँ तल), 2/1 रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (ई-निआसू) सं. बीएंडआर/एचओ/40079/पारादीप/पाइपिंग टर्मिनल/02/ तिथि: 02.09.2019

"आईओसीएल, पारादीप के टर्मिनल क्षेत्र में प्रॉडक्ट्स, यूटिलिटी एवं अग्नि शमन पाइप लाइनों के परिवहन, संचालन, बिछाने, फैब्रिकेशन, कार्यान्वयन, बेल्डिंग, थ्रेडिंग, बोटलिंग, परीक्षण एवं प्रीकमिशनिंग को निष्पादित करने के कार्य" हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में आनलाइन एकल प्रतिशतता दर प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक बोलीदाताओं को http://www.eprocure.gov.in/eprocure/app में लॉगिंग के जरिए सरकारी ई-प्रापण प्रणाली में सूचीबद्ध व पंजीकृत होना होगा।

प्रस्ताव दाखिले की अंतिम तिथि: 16.9.19 को 16:30 बजे तक इस संदर्भ में कोई भी संयोजन/शुद्धिपत्र सिर्फ कंपनी की वेबसाईट: www.bridgeroop.co.in तथा सीपीपी पोर्टल: http://eprocure.gov.in/ eprocure/app पर जारी की जाएगी।

कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

शाखा : सीसी चर्नाक, गुरुद्वारा पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग, दिल्ली 110088

नियम - 8(1) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत कार्पोरेशन बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री संजीव कुमार तोमर, श्रीमती ललिता तोमर को एक मांग सूचना दिनांक 02.04.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु 17,88,590/- (रु. सत्रह लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ नब्बे मात्र) और साथ में आकस्मिक खर्चे लागत प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में अगस्त 26 अगस्त, 2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन कार्पोरेशन बैंक, द्वारा उल्लेखित राशि रु 17,88,590/- (रु. सत्रह लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ नब्बे मात्र) साथ में भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे लागत प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 1/3014, द्वितीय तल, ब्लॉक 582.42 वर्ग फीट, प्लॉट नं. 21 पर निर्मित, खसरा नं. 793/604, गाँव/जौंती सिकन्दरपुर, गली नं. 16, ब्रह्म नगर, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित

दिनांक: 26-08-2019 स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

CIN: L65110TH2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031

टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

प्राधिकृत अधिकारी: श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नं. +91-9999776185

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की श्री दीपक मुंजाल, संजना मुंजाल, आलोक मुंजाल, नीलम मुंजाल, न्यू लाइट रबड़ इंडस्ट्रीज, श्रीमती शकुन्तला मुंजाल, पत्नी स्व. श्री बलवंत राय मुंजाल, ऋणधारक (सह-ऋणधारक (कों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 17.3.2019 को आईएनआर 5,44,27,480.65/- की वसूली के लिये 22.09.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार

भारत ने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों से वित्तीय मदद की आवाज उठाई

वैश्विक तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य है

कोच्चि, एक सितंबर (भाषा)।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के होने वाले दो अहम सम्मेलनों से पहले भारत ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में विकसित देशों की ओर से वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए आवाज उठाई है। पेरिस समझौते का मकसद इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है, जो पेरिस समझौते-2015 का केंद्र है। यहां शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आए जावडेकर ने कहा, 'चिली में हम जब अगली सीओपी (पक्षकारों का सम्मेलन) में मिलेंगे तब हमारा रुख प्रत्येक देश से राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता का अनुपालन करने और विकसित देशों की ओर से वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराए जाने पर होगा, जो विकासशील विश्व के लिए अहम है।

जावडेकर ने सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' का हवाला देते हुए कहा कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर रोक, सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार, पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक पौधरोपण जैसे कदमों को संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर रेखांकित किया जाएगा। इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस जलवायु कार्रवाई सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। वहीं दिसंबर में चिली की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सच है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं। करीब 70 फीसद ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन विकसित देशों की वजह से होता है जबकि भारत की हिस्सेदारी मात्र तीन फीसद है। विकसित देशों के लोग अधिक उपभोग कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि विश्व निकाय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2020 से विकसित देशों से विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर हस्तांतरित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

केरल में पाक के ध्वज से मिलता-जुलता झंडा लहराने पर छह छात्र निलंबित

कोझीकोड (केरल), 1 सितंबर (भाषा)।

परंबरा के निकट एक कॉलेज के छात्रों ने परिसर में चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज से मिलता-जुलता झंडा लहराया, जिसके बाद कॉलेज के छह छात्रों को निलंबित कर दिया है। निलंबित सभी छात्र फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है।

घटना का वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज, सभी छात्र फरार

हरे रंग का झंडा कॉलेज में हो रहे चुनाव को लेकर मुसलिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (एमएसएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लहराया गया। एमएसएफ इंडियन यूनियन मुसलिम लीग (आइयूएमएल) की छात्र इकाई है। एमएसएफ नेतृत्व ने हालांकि आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यह संगठन का आधिकारिक झंडा है, न कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है।

पुलिस ने रविवार को एजंसी को बताया कि सिल्वर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में 27 अगस्त को हुई घटना का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक मामला दर्ज किया गया है। मामला आइपीसी की धारा 153 (बलवा कराने के आशय से जानबूझकर भड़काना), धारा 143 (गैर कानूनी तरीके से जमा होना) और धारा 147 (बलवे के लिए सजा) के समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक जांच अधिकारी ने एजंसी को बताया, यह घटना वीडियो फुटेज के वायरल होने के बाद प्रकाश में आई। गैर कानूनी तरीके से जमा होने और बलवा कराने के आशय से भड़काने समेत अन्य आरोपों के लिए मामला दर्ज किया गया है। व्यापक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा, इस विवादास्पद झंडे में एमएसएफ का लोगो भी नहीं था। यह मानक आकार के अनुपात में भी नहीं था। इस संबंध में कॉलेज के छह छात्रों को निलंबित कर दिया गया है और वे फरार हैं।

पाबंदियों में ढील के बावजूद कश्मीर में सामान्य जनजीवन प्रभावित

श्रीनगर, 1 सितंबर (भाषा)।

घाटी के 11 और थाना क्षेत्रों में पाबंदियों में ढील के बावजूद रविवार को लगातार 28वें दिन सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।

अधिकारियों ने बताया कि अब घाटी के 105 थाना क्षेत्रों में से 82 में कोई पाबंदी नहीं है।

29 टेलीफोन एक्सचेंजों में लैंडलाइन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। ये एक्सचेंज पहले से चालू 47 एक्सचेंज से अलग हैं। हालांकि, लाल चौक और प्रेस एनक्लेव में सेवाएं अब भी बाधित हैं। उन्होंने बताया कि घाटी में शनिवार को शांति बनी रही और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कश्मीर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानून-व्यवस्था खराब होने की आशंका की वजह से लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। केवल एंबुलेंस को और आपात मामलों में ही आने-जाने की अनुमति थी। शनिवार सुबह अधिकतर इलाकों से पाबंदियां हटा दी गईं। अधिकारियों ने हालांकि कहा कि रविवार को लगातार 28वें दिन आम जनजीवन प्रभावित रहा। दुकानें बंद रहीं और सड़कों से सार्वजनिक वाहन नदारद रहे। परंतु श्रीनगर के कई इलाकों में निजी वाहनों की आवाजाही दिखी। शहर के सिविल लाइन इलाकों में कुछ रेहड़ी वालों ने अपनी दुकानें लगाई। उन्होंने बताया कि घाटी के अधिकतर इलाकों में अवरोधक और पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती जारी है। पांच अगस्त को केंद्र की ओर से अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से बंद बीएसएनएल ब्रॉडबैंड और निजी लीज लाइन इंटरनेट सहित मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अभी बहाल नहीं की गई हैं।

उपराष्ट्रपति ने भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का किया उद्घाटन

गुडुरु (आंध्र प्रदेश), 1 सितंबर (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को चेरलोपल्ली और रापुरु के बीच देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग और वेंकटचलम और ओबुलवारीपल्ली के बीच विद्युतीकृत रेल लाइन का उद्घाटन किया। गुडुरु रेलवे स्टेशन पर पुनर्निमित यार्ड का उद्घाटन करने के अलावा, उपराष्ट्रपति ने गुडुरु और विजयवाड़ा के बीच एक नई इंटर-सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। नायडू ने 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग को इंजीनियरिंग का चमत्कार करार दिया और कहा कि यह माल ढुलाई के निर्बाध आवागमन के लिए कृष्णापट्टनम बंदरगाह और तटीय क्षेत्र के बीच रेल संपर्क प्रदान करेगा।

437 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सुरंग में 44 ट्रॉली रिफ्यूज और 14 पारगमन बनाए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने शनिवार शाम को नवनिर्मित ओबुलवारीपल्ली-कृष्णापट्टनम लाइन को लेकर कहा, 'मैं इसको लेकर अभिभूत व भावुक हूं कि मेरे बचपन का सपना अब सच हो गया है।' उन्होंने कहा, 'मैं भावुक हूं क्योंकि रेलवे लाइन मेरे पैतृक गांवों से गुजरती है जहां मैंने अपना बचपन बिताया। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई ट्रेन इन पहाड़ियों से होकर गुजरेगी।'

छह लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज

जयपुर, 1 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के घमूरवाली थाना क्षेत्र में दो दलित युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में छह लोगों के खिलाफ शनिवार की रात मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

करणपुर के वृत्ताधिकारी प्रताप सिंह डूडी ने रविवार को बताया कि पीड़ित युवतियों ने छह आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवतियों की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार यह घटना शुक्रवार की है। पीड़िताओं से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने दोनों पीड़िताओं को पार्टी में खाना बनाने के लिए बुलाया था जहां उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया।

मेरठ के निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर रोक, एमसीआइ का फैसला बहाल रखा हाई कोर्ट ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरठ के एक निजी मेडिकल कालेज को दाखिल की अनुमति देने से इनकार किए जाने संबंधी भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) के निर्णय को बरकरार रखा है। एमसीआइ ने मेरठ के हापुड़ रोड पर स्थित निजी क्षेत्र के मुलायम सिंह यादव मेडिकल कालेज को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के वास्ते 150 छात्रों के नए बैच को कुछ खामियों के कारण नामांकन दिए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एमसीआइ द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट था कि कालेज संकाय और रेजिडेंट्स में जो खामियां बताई गई हैं, जो क्रमशः 7.4 फीसद और 8.5 फीसद थीं। ये खामियां अधिकतम स्वीकार्य सीमा पांच फीसद से अधिक थीं। सुनवाई समिति ने देखा था कि चिकित्सा से जुड़ी सामग्री पिछले दो आकलन में लगातार अपर्याप्त थी।

कॉलेज ने अदालत से एमसीआइ के 18 मई के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया था। यह कॉलेज डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के परिवार का है। जो पहले सपा की एमएलसी और राष्ट्रीय सचिव थीं। इसी कारण अपने मेडिकल कालेज का नाम उन्होंने मुलायम सिंह यादव के नाम पर रखा था। लेकिन 2017 में उन्होंने सपा और एमएलसी सीट दोनों से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। तब उनकी खाली हुई सीट के उपचुनाव में भाजपा के एक मंत्री को सदन का सदस्य निर्वाचित कराया गया था। हालांकि भाजपा ने कुछ महीने बाद सरोजनी अग्रवाल को छह साल की विधान परिषद सदस्यता देकर उनका हिसाब बराबर कर दिया था।

सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत : पुलिस अफसर पर लापरवाही का मामला दर्ज

मुंबई, 1 सितंबर (भाषा)।

मुंबई में 19 वर्षीय एक युवती के साथ कथित बलात्कार के मामले में निष्क्रियता को लेकर एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला की बाद में एक अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

महिला के वकील के मुताबिक, अनुसूचित जाति की उस महिला के साथ जुलाई के पहले हफ्ते में मुंबई में उसके चार दोस्तों ने कथित रूप से बलात्कार किया था। बाद में उसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, महिला के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नितिन सातपुते की शिकायत के आधार पर, शनिवार को चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक दीपक सुर्वे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें सातपुते ने मामले की जांच को लेकर पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने में भी विफल रही, क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जाति की थी। सातपुते ने आरोप लगाया, 'प्रथम दृष्टया, यह पुलिस की एक गंभीर गलती है, जिसने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पीड़ित परिवार द्वारा गुहार लगाए जाने के बावजूद, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
एन ब्लॉक, प्लॉट नंबर, नई दिल्ली (मेक कॉर्पोरेट शाखा) एन-123, एन ब्लॉक, फ्लॉट रूकमंड, नई दिल्ली-110001 फोन : 45752401 ई-मेल : bm1046@obc.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैसर्स एसएसएमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) पंजी. कार्यालय के-336, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 और: कॉर्पोरेट कार्यालय: ए 126 सैक्टर 63, नोएडा, यू.पी-2013 श्री मनोज कुंवर (कर्जदार / व्यक्तिगत गारंटर) पुत्र श्री धर्मनाथ कुंवर, 9004ए गौर ग्रीन सिटी, वैभव खंड इंदिरापुरम-यू.पी.-201010 यूनिट 410ए, तृतीय तल फ्लैट नं. 07, गली नं. 2 गणेश नगर-11, शकरपुर, दिल्ली-110092 श्रीमती अनुपमा कुंवर (व्यक्तिगत गारंटर) पत्नी मनोज कुंवर 9004ए गौर ग्रीन सिटी वैभव खंड, इंदिरापुरम- यू.पी-201010 यूनिट 410ए, तृतीय तल, फ्लैट नं. 07, गली नं. 2, गणेश नगर-11, शकरपुर, दिल्ली-110092 को नोट नोटिस दिनांक 21.08.2017 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 13,52,60,519.10 (रु. तेरह करोड़ बावन लाख साठ हजार पांच सौ उन्नीस और पैसे दस मात्र) दिनांक 31.08.2017 तक, और भविष्य का ब्याज, लागत, इत्यादि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।**

उधारकर्ता / गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता एवं गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, आदेश नं.1813/CRA/SAREFASI Act/Sec-14 में दिनांकित 03.05.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक **कब्जा दिनांक 30 अगस्त 2019** को सरफासी के अधिनियम उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14, के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने ले लिया है।

उधारकर्ता / सह-कर्जदार / बंधककर्ता / गारंटर्स का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता / सह-कर्जदार / बंधककर्ता / गारंटर्स को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सतर्कता दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार बाबत, बकाया राशि रू. 18,22,85,857.10 (रु. अट्ठारह करोड़ बाईस लाख पिचासी हजार आठ सौ सत्तावन और पैसे दस मात्र) दिनांक 31.07.2019 तक ब्याज, लागत और अन्य प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

रिहायशी फ्लैट नं. 8004, छठा तल, बिना छत के अधिकार के (पेंट हाउस), ब्लॉक ए, जिसमें एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग, चार बैड रूम, चार बाथरूम / टॉयलेट, एक किचन, एक स्टोर, एक सर्वेंट का कमरा है जिसमें अटैच्ड टॉयलेट और बालकनी हैं। जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 2375 वर्ग फीट लगभग (फ्लैट कवर्ड क्षेत्रफल 1750.47 वर्ग फीट, अलमारी 28.8 वर्ग फीट, बालकनी 198.33 वर्ग फीट, और सुपर क्षेत्रफल 396.7 वर्ग फीट) और टैरेस क्षेत्रफल 1440 वर्ग फीट (1010+430 वर्ग फीट), गौर ग्रीन सिटी, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं. 8, जोकि वैभव खंड, इन्दिरापुरम, तहसील और जिला गाजियाबाद (यू.पी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती अनुपमा कुंवर पत्नी श्री मनोज कुमार कुंवर के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – 60' चौड़ी रोड, पश्चिम में – 120' चौड़ी रोड, उत्तर में – 80' चौड़ी रोड, दक्षिण में – 100 मी. चौड़ी ग्रीन बेल्ट

दिनांक : 30.08.2019 स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

बीएलएस इन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय-जी-4 बी-1, एक्सटेंशन मोहन को-ऑपरेटिव इंड. इस्टेट मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044
CIN: L51909DL1983PLC016907; Website: http://www.blsinternational.com
Email: compliance@blsinternational.net; Contact no. +91 11-46980006;
Fax: +91 11-23756264

35वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट-ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि

1. बीएलएस इन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को 3.00 बजे अप. में डा. बी.आर. अम्बेदकर ऑडिटोरियम आन्ध्र प्रदेश भवन, अशोक रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें उसकी सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।
2. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एजीएम की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग के विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी आरटीए तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज हैं तथा उसकी भौतक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर 30 अगस्त, 2019 को भेजी गई है। वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.blsinternational.com पर भी उपलब्ध है।
3. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन हम आपको सूचित करते हैं कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 20 सितम्बर, 2019 से 26 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक कम्पनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यों को अभिलेख में लेने के लिए बंद रहेंगे। पुनः अधिसूचित किया जाता है कि उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए भौतिक पद्धति अथवा डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि 19 सितम्बर, 2019 है।

सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद किन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 सितम्बर, 2019 से पूर्व कम्पनी का सदस्य बनते हैं तो लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं। पुनः यदि सीडीएसएल की रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म पर वह पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिए वे वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

iii) सदस्यगण ध्यान रखें कि:

क) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिनन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

iv) सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप www.evotingindia.com के सहायता खण्ड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com, हेल्प डेस्क नं.: 1800-200-5533 अथवा compliance@blsinternational.net पर ईमेल करें। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.blsinternational.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com, www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

बीएलएस इन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता./-
अर्चणा मैनी
कम्पनी सचिव

तिथि: 31.8.2019
स्थान: दिल्ल

SRM ENERGY LIMITED
CIN L17100DL1995PLC063047
Regd. Office: 21 Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Tel. No. 011-41403205 | Website: www.srmenergy.in | Email: info@srmenergy.in

NOTICE

Notice is hereby given that:-

The 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on **Thursday, the 26th September, 2019 at Federation of Indian Export Organisations, Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, OPP. Army Hospital Research and Referral, New Delhi 110057 at 11:00 A.M.** and Annual Report for financial year 2018-19 have been sent to all members of the Company at their registered address in the permitted mode and soft copies of same have also been sent in electronic mode to all members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). The Annual report for F.Y. 2018-19 is also available and can be downloaded from website of the Company at www.srmenergy.in

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules made there under, it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, of the Companies Act, 2013, the Company has provided all its Members (holding shares both in physical and in electronic form) the facility to exercise their vote (on the resolutions as enumerated in the Notice of the AGM), by electronic voting (e-voting) through the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their vote electronically at the AGM is **19th September, 2019 (Thursday)**.

All the members be informed that (a) the Ordinary Businesses and the Special Businesses as set out in the Notice of 32nd AGM may be transacted by electronic voting, (b) the physical dispatch of Annual Report 2018-19 along with its electronic transmission has been completed on 31st August, 2019, (c) the voting through electronic means shall commence on **9:00 A.M. on 23rd September, 2019 (Monday) and ends on 5:00 P.M. on 25th September, 2019 (Wednesday)**, (d) voting through electronic means shall not be allowed beyond **5:00 P.M. on 25th September, 2019 (Wednesday)**, (e) the Notice of the 32nd Annual General Meeting is available on the Company's website www.srmenergy.in and CDSL's website www.evotingindia.com and (f) for the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions (at page No. 69 & 70) as contained in the Annual Report 2018-19 or visit CDSL's website www.evotingindia.com.

In case any person become member after dispatch of the aforesaid Notice/Annual Report and holding shares as on the cut-off date i.e., 19th September, 2019, may follow the same instructions as mentioned for e-Voting in the Annual Report. The facility for voting through physical mode shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the meeting in physical mode. The members who have cast their votes by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Satish Kumar Nirankar of M/s S.K. Nirankar & Associates, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer, for the ensuring AGM.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under "Help" section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or members may also contact for any query or inconvenience or grievances if any, in voting through electronic mode at phone number 011-41403205 of the Company.

By Order of the Board of Directors
For SRM Energy Limited
Sd/-
(Vishal Rastogi)
Managing Director

Place: New Delhi
Date: 01.09.2019

ADVITIYA TRADE INDIA LIMITED
CIN: L74999DL2017PLC314879
Regd. Office: 2814/6 Ground Floor, Chuna Mandi Paharganj New Delhi - 110055
E-mail ID: goyals2729@gmail.com, Website: advitiyatrades.com
NOTICE OF 3rd ANNUAL GENERAL MEETING
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 3rd Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Tuesday, 24th Day of September, 2019 at 04:00 P.M. at 2814/6 Ground Floor, Chuna Mandi Paharganj New Delhi - 110055 to transact the business as set forth in the Notice of AGM.
2. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by CSDL and the business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM;
3. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.garvindustries.com. Notice of AGM and Annual Report for 2019 has been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 16th September, 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
   I. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronics means;
   II. The remote e-voting shall commence on 21st Day of September, 2019 at 9:00 A.M.;
   III. The remote e-voting shall end on 23rd Day of September, 2019 at 5.00 P.M. and thereafter E-Voting through shall not be allowed;
   IV. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 16th Day of September, 2019.
   V. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday 16th Day of September, 2019 may obtain the Login ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
   VI. Members may note that:
   a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 P.M. on 23rd Day of September, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
   b)the facility for voting through ballot paper shall be made available at venue of the AGM;
   c)the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
   d)a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
   VII. The Notice of AGM is available on the Company's website www.advitiyatrades.com. and also on the CDSL's websitewww.evotingindia.com. For any queries/ grievances related to e-voting shareholders may contact to: Skyline Financial Service Private Limited, D-153-A, 1st Floor, Okhla Industries Area, Phase -1, New Delhi-110020, E-mail:info@skylinerta.com.
5. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Tuesday, 17th Day of September 2019 to Tuesday, 24th Day of September 2019 (both day inclusive).

For Advitiya Trade India Limited
Sd/-
Sandeep Goyal
Managing Director
DIN: 07762515

Place: New Delhi
Date: 02.09.2019

Gogia Capital Services Limited
CIN: L74899DL1994PLC059674
Regd Off.: 100A/1, Right Wing, The Capital Court, Ground Floor, Shopping Centre, Munirka -III, New Delhi -110067
Email: compliance@gogiacap.com Website: www.gogiacap.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, the 30th day of September, 2019 at 10.00 a.m.at the registered office of the company at 100A/1, Right Wing, The Capital Court, Ground Floor, Shopping Centre, Munirka -III, New Delhi - 110067

The notice of AGM and attendance slip has been sent in electronic mode to members whose e-mail ids are registered with the company or the depository participant(s) unless the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the notice of AGM and attendance slip has been sent to those members who have not registered their e-mail ids with the company or the depository participant(s)

The Copy of the Notice of AGM will also be available on the Company's website www.gogiacap.com, members, who do not receive the notice of AGM, may download it from the company's website or may request for the copy of the same by writing to the Company Secretary at the registered office of the company or at compliance@gogiacap.com. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the registered officeof the company during business hours on any working day

Pursuant to the Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the relevant Rules of the Act, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to voteby electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by national securities depository limited (NSDL)

The e-voting period commences on Friday, 27th September, 2019 at 9.00 am and ends on Sunday, 29th September, 2019. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the member(s) as on 23rd September, 2019 (Cut-off date) members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The notice of AGM will also be available on the company's website www.gogiacap.com and on NSDL website http://www.evoting.nsdl.com. The procedure of electronic voting is available in the notice of the Annual General Meeting as well as in the email sent to the members by NSDL. NSDL website http://www.evoting.nsdl.com. The company has appointed

वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत मजबूत

विहारी ने जड़ा पहला शतक, बुमराह की भी हैट्रिक

किंग्स्टन, 1 सितंबर (भाषा)।

हनुमा विहारी के पहले शतक के बाद जसप्रीत बुमराह की हैट्रिक की बदौलत भारतीय टीम ने दूसरे टैस्ट चैंपियनशिप के दूसरे दिन स्टंप तक वेस्ट इंडीज के सात विकेट झटक लिए। दो मैचों की शृंखला में 0-1 से पिछड़ रही मेजबान टीम दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 87 रन पर सात विकेट गंवाकर जूझ रही थी। शनिवार को बुमराह (16 रन देकर छह विकेट) ने अपने घातक शुरुआती स्पैल में वेस्ट इंडीज के पहले पांच विकेट झटक लिए जिसमें से तीन नौंवे ओवर में लगातार गेंदों पर मिले। इससे वह टैस्ट मैचों में हैट्रिक हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए।

बुमराह ने सातवें ओवर से विकेट लेने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जॉन कैंपबेल को आउट किया जिनका कैच विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आसानी से लपक लिया। इसके बाद नौंवें ओवर में लगातार गेंदों पर बुमराह ने डेरेन ब्रावो, शामार ब्रुक्स और रोस्टन चेज के विकेट हासिल कर अपना नाम रेकार्ड बुक में लिखवा लिया। ब्रावो का कैच दूसरी स्लिप में खड़े लोकेश राहुल ने लिया और फिर अगली दो गेंद पर ब्रुक्स और चेज पगबाधा आउट हुए।

बुमराह की हैट्रिक का कुछ श्रेय कप्तान विराट कोहली को भी दिया जाना चाहिए। इन्होंने जोर दिया कि चेज के फैसले का रिव्यू कराया जाए जिन्हें मैदानी अंपायर पॉल रेफेल ने नाटआउट दिया था। बुमराह इस तरह हरभजन सिंह और इरफान पठान के बाद भारत के लिए टैस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। उन्होंने फिर क्रेग ब्रेथवेट (10) के रूप में पांचवां शिकार किया। इसके बाद शिमरोन हेटमायर (34) को मोहम्मद शमी ने पवेलियन भेजा। फिर बुमराह ने वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर को आउट कर छठा विकेट प्राप्त किया।

बुमराह की बन गई हैट्रिक

हनुमा विहारी की परिपक्वता से भरी पहली शतकीय पारी और ईशांत शर्मा के अप्रत्याशित अर्धशतक के दम पर भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए। इससे वेस्ट इंडीज की टीम 329 रन से पीछे है और अभी तीन दिन का खेल बाकी है। अपने पहले के स्कोर 42 रन से आगे खेलते हुए विहारी ने एक छोर संभालकर 111 रन की पारी खेली और वह आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। उन्होंने अपनी पारी में 225 गेंदों का सामना करके हुए 16 चौके लगाए। विहारी को ईशांत के रूप में बेहतरीन साथ मिला और दोनों ने आठवें विकेट के लिए 112 रन जोड़कर भारत को 400 के पार पहुंचाया।

ईशांत ने 80 गेंद में सात चौकों की मदद से 57 रन बनाए। विहारी को वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने आउट किया। होल्डर ने 32.1 ओवर में 77 रन देकर पांच विकेट लिए। वहीं ईशांत को कार्लोस ब्रेथवेट ने पवेलियन भेजा। इससे पहले भारत ने पहले के स्कोर पांच विकेट पर 264 रन से आगे खेलते हुए ऋषभ पंत (27) का विकेट गंवाया जो दिन की पहली ही गेंद पर आउट हो गए।

कप्तान की बदौलत मिली हैट्रिक : बुमराह

किंग्स्टन, 1 सितंबर (भाषा)।

बेहतरीन लाइन एवं लेंथ, रफ्तार और उछाल से वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाने वाले जसप्रीत बुमराह ने भारतीय कप्तान विराट कोहली से कहा कि यह हैट्रिक उनकी बदौलत मिली। बुमराह द्वारा वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज को आउट करने के बाद स्टंप माइक में सुना जा सकता था कि कोहली कह रहे थे, 'कितना बढ़िया गेंदबाज है ये। कितना बढ़िया गेंदबाज है।'बुमराह ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टैस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज की पहली पारी में हैट्रिक सहित छह विकेट झटक लिए हैं। उनकी हैट्रिक का श्रेय कप्तान कोहली को भी जाता है जिन्होंने रोस्टन चेज का रिव्यू कराया जिन्हें पहले मैदानी अंपायर पॉल रेफेल ने नॉटआउट करार दिया था। रिव्यू के बाद वह आउट निकले और बुमराह की हैट्रिक का तीसरा शिकार बने।

यशस्विनी को स्वर्ण के साथ ओलंपिक कोटा

रियो दि जिनेरियो, 1 सितंबर (भाषा)।

यशस्विनी देसवाल ने दुनिया की नंबर एक निशानेबाज ओलेना कोस्तेविच को पछाड़कर आइएसएसएफ विश्व कप में शनिवार को महिलाओं की 10 मीटर एअर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत से उन्होंने भारत को नौवां ओलंपिक कोटा भी दिलाया। पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन 22 बरस की यशस्विनी ने आठ महिलाओं के फाइनल में 236.7 का स्कोर करके पीला तमगा जीता।

दुनिया की नंबर एक उक्रेन की ओलेना कोस्तेविच ने 234.8 अंक से रजत और सर्बिया की जेसमिना मिलावोनोविच ने 215.7 अंक से कांस्य पदक हासिल किया। अर्थशास्त्र की छात्रा यशस्विनी का दबदबा इतना था कि वह फाइनल में ओलेना से 1.9 अंक आगे रहीं। क्वालीफिकेशन में भी वह 582 अंक से शीर्ष पर रही थीं।

इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत यशस्विनी 2020 तोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत की ओर से कोटा हासिल करने वाले निशानेबाज संजीव राजपूत, अंजुम मौदगिल, अपूर्वी चंदेला, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, दिव्यांश सिंह पंवार, राही सरनोबत और मनु भाकर के साथ शामिल हो गईं। यह रियो में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण भी रहा। अभिषेक वर्मा और इलावेनिल वलारिवान ने भी क्रमशः पुरुषों की 10 मीटर एअर पिस्टल और महिलाओं की 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया था।

इससे पहले काजल सैनी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में 1167 के क्वालीफाइंग स्कोर से 22वां और तेजस्विनी सांवत ने 1156 अंक से 47वां स्थान हासिल किया। अनु राज सिंह और श्वेता सिंह फाइनल में जगह नहीं बना सके थे जबकि मनु भाकर ने न्यूनतम क्वालीफिकेशन स्कोर में 580 का स्कोर किया।

टैस्ट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने बुमराह

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शनिवार देर रात वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टैस्ट में हैट्रिक बनाकर इतिहास रच दिया। यह कारनामा करने वाले वह तीसरे भारतीय बने। इनसे पहले हरभजन सिंह और इरफान पठान ने टैस्ट में हैट्रिक बनाया है। बुमराह की धारदार गेंजबाजी से पहली पारी में 416 रन बनाने वाली भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के 87 रन पर सात विकेट चटका दिए। बुमराह ने 9.1 ओवर में 16 रन देकर छह विकेट झटके।

बुमराह ने पारी के नौवें ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर ड्वेन ब्रावो, शामरा ब्रूक्स और रोस्टन चेज को पवेलियन भेजा। हैट्रिक से पहले बुमराह ने जॉन कैंपबेल को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों लपकवाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई थी। एंटिगा टैस्ट की दूसरी पारी में बुमराह ने आठ ओवर में सात रन देकर पांच विकेट चटकाए थे।

बुमराह की हैट्रिक टैस्ट क्रिकेट इतिहास की 44वीं हैट्रिक है। इससे पहले टैस्ट क्रिकेट में आखिरी हैट्रिक इंग्लैंड के स्पिनर मोईन अली ने जुलाई 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओवल में ली थी। पिछले दो साल में और कोई खिलाड़ी टैस्ट क्रिकेट में हैट्रिक नहीं झटक सका था।

पहली हैट्रिक हरभजन के नाम

भारत के लिए पहली टैस्ट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हरभजन सिंह थे। हरभजन ने साल 2001 में कोलकाता में आस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कारनामा किया था। हरभजन ने रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को लगातार तीन गेंदों में अपना शिकार बनाया था।

ओसाका से हारकर युवा कोको हुई बाहर

न्यूयार्क, 1 सितंबर (एएफपी)।

गत चैंपियन नाओमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन टेनिस ग्रैंडस्लैम में 15 वर्षीय कोको गौफ का शानदार सफर समाप्त कर दिया। वहीं पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। दुनिया की नंबर एक ओसाका ने 65 मिनट तक चले मुकाबले में कोको को 6-3, 6-0 से मात दी। हारने के बाद कोको रोने लगीं और जापानी स्टार ओसाका ने प्रतिद्वंद्वी को जाकर गले लगाकर सांत्वना दी।

ओसाका ने कहा कि जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मैंने देखा कि उनके आंसू आ रहे थे। वह इतनी छोटी भी हैं। मैं चाहती थी कि उन्हें महसूस कराऊं कि उन्हें सिर ऊंचाकर कोर्ट से जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में यहां तक का सफर तय किया। तेईस बार की ग्रैंडस्लैम विजेता सेरेना विलियम्स ने कोको के बारे में बात करते हुए उन्हें 'महिला टेनिस का भविष्य' करार दिया। नोवाक जोकोविच ने उन्हें 'नई सुपरस्टार' कहा जो 1996 में अन्ना कोर्निकोवा के बाद यहां तीसरे दौर में पहुंचने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनीं।

अब ओसाका का सामना स्विट्जरलैंड की 13वीं वरीय बेलिंडा बेनसिच से होगा जिन्हें एनेट कोंटावेट के बीमार होने के कारण वॉकओवर मिला। तीन बार के चैंपियन नडाल ने 170वीं रैंकिंग के दक्षिण कोरियाई क्वालीफायर चुंग हियोन को 6-3, 6-4, 6-2 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए स्पेन के इस दूसरे वरीय खिलाड़ी का सामना 2014 के चैंपियन मारिन सिलिच से होगा। इन्होंने जॉन इस्नर को चार सेट तक चले मुकाबले में पराजित किया।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 288, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।